हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

26.08.2026/1100/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्या : 3698 (स्थगित)

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरंभ। माननीय सदस्य श्री दीप राज।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय तीन-चार वर्ष से कार्यरत जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको किस आधार पर हटाया गया और जिन्हें हटाया गया है वे कहां जाएंगे?

दूसरा, क्या यह सत्य है कि शिलाई में मंत्री जी ने एक सभा में कहा कि शिलाई विधान सभा क्षेत्र से 700 बेरोजगार युवा आउटसोर्स पर लगाए गए हैं? क्या यह सत्य है कि वे सभी शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से लगाए गए हैं?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो आउटसोर्स के टेंडर हुए हैं उसमें हमारे जितने भी युवा बेरोजगार साथी हैं उन सभी लोगों से 500-500 रुपये फीस के रूप में लिए गए हैं लेकिन वे कब तक चयनित होंगे? ये आउटसोर्स एजेंसियां किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष व्यक्तियों को दी गई है इसके अलावा जो युवा चयनित नहीं होंगे, क्या उनसे जो 500-500 रुपये लिए गए हैं, वे उनको वापस दिए जाएंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स पर जो सेवाएं ली जाती हैं उसके लिए हम सर्विसीज को आउटसोर्स करते हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त नहीं करते है। सरकार की नीति में व्यक्तियों को लगाने की प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से नहीं है। जहां तक शिलाई का विषय है, इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि अखबारों में दिए गए स्टेटमैंट पर नहीं जाना चाहिए बल्कि वास्तविकता पर बात करनी चाहिए। यदि अखबार में कोई स्टेटमैंट दी गई है तो उसकी वास्तविकता क्या है और कितने व्यक्ति किस विभाग में लगे हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए तथा उसे टेबल पर रखना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आउटसोर्स कंपनियां कितनी हैं? ये हमारे समय से नहीं है। ये काफी समय से चली आ रही हैं। जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी

26.08.2026/1100/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

तब भी आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं ली जाती थीं और उससे पहले भी आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं ली जाती रही हैं। माननीय धूमल साहब के समय भी आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं ली जाती थीं। वे भी सर्विसीज ही आउटसोर्स करते थे। सरकारी सेवाओं में किसी भी व्यक्ति को आउटसोर्स पर आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा लगाया जाता है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, जो अभी लास्ट में इंटरव्यू हुए हैं उन इंटरव्यू को हुए पांच-छह महीने हो गए हैं और उन सभी युवाओं से फीस भी ली गई है। उनको कब तक आउटसोर्स पर लगा दिया जाएगा? ...(व्यवधान) नहीं-नहीं सर, टी0जी0टी0 आट्र्स नहीं। मैं आउटसोर्स की बात कर रहा हूं। अभी जो हेल्थ डिपार्टमैंट में नर्सिज और जल शक्ति विभाग में जलवाहक के इंटरव्यू हुए थे उनके लिए करसोग में भी कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिए गए थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके लिए पूरे मण्डी में करसोग सेंट्रलाइज किया गया था उसमें सराज और इसके साथ वाले क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन वे बेरोजगार युवा तब से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब तक आउटसोर्स पर लगा दिया जाएगा और जो निकाले गए हैं उनको क्या होगा?

अध्यक्ष : यह जो आउटसोर्स और मल्टी टास्क वर्कर्ज हैं, ये दो अलग-अलग बातें हैं। मल्टी टास्क वर्कर्ज की डिवीजन वाइज रिक्रूटमेंट हो रही by the respective Divisions. उन्होंने अपनी डेट व शेड्यूल अलग से दिया है। जो आउटसोर्स रखे जाते हैं उनमें कैटेगरी वाइज इंटरव्यू थ्रू आउटसोर्स एजेंसीज के माध्यम से होते हैं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

26-8-2026/1105/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 3698 -----क्रमागत

अध्यक्ष ------जारी

इसलिए माननीय सदस्य आप स्पैसिफिकली प्रश्न पूछिए। आपने तो सारा प्रदेश मिक्स कर दिया। आप कौन-सी एजेंसी की बात कर रहे हैं, हैल्थ की एजेंसी की या स्कूलों में लगने वाले आया आदि आउटसोर्स हैं और यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल है। माननीय सदस्य आप यह स्पष्ट पूछिए।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, यह स्टाफ नर्सिज वाला मामला है। उनका टाइम पीरियड कब तक होल्ड रखेंगे क्योंकि उन सबसे फीस ले ली गई है। क्या उनको शीघ्र रखा जाएगा?

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में थोड़े कन्फ्यूज थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जो स्टाफ नर्सिज के बारे में पूछ रहे हैं तो ये आउटसोर्स सर्विसिज दी गई हैं जिनके माध्यम से स्टाफ नर्सिज भी हो सकती हैं या कोई मल्टीपर्पज वर्कर भी हो सकता है। आप जो मल्टी टास्क वर्कर की बात कर रहे हैं तो वे पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीतिगत डिपार्टमैंट की पॉलिसीज के तहत रखे गए हैं। वे आने वाले समय में रेगुलर भी होंगे और उन्हें पेंशन भी मिलेगी। आउटसोर्स वालों के लिए अभी नीतिगत विचार चल रहा है कि जिन्होंने अपनी सर्विस दी है उन्हें भविष्य में किस प्रकार रखा जाए? लेकिन उनकी सारी सर्विसिज आउटसोर्स पर हैं और यदि कोई कर्मचारी परफॉर्म नहीं कर रहा है या ड्यूटी से अबसेंट है तो कंपनी वाला उसे निकाल भी सकता है और रख भी सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उनमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाने का भी वायदा किया था। क्या सरकार यह नीति बना चुकी है? अगर नहीं बना पाई है तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? दूसरा, जो विभाग आउटसोर्स पर कर्मचारी रखते हैं तो उनको कौन-सी एजेंसी रखेगी उसे कैसे तय करते हैं? अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत-सी एजेंसियां हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं

26-8-2026/1105/NS-YK/2

कि क्या इसके लिए कोई टेंडर होता है? क्या उनमें कोई कंपिटिशन होता है या पिक एंड चूज होता है? किस आउटसोर्स एजेंसी को किस विभाग के लिए किस कैटेगरी के कर्मचारी रखने हैं और इसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है? यह स्पष्ट किया जाए। तीसरा, सरकार आउटसोर्स एजेंसी को जितना पैसा देती है, क्या सरकार ने यह निश्चित किया है कि आउटसोर्स एजेंसी इतनी ही परसेंटेज रख सकती है और बाकी पेमेंट कर्मचारियों को करनी होगी? क्या इस संबंध में कुछ निश्चित किया गया है या आउटसोर्स एजेंसी की अपनी मर्जी है कि वह जितना मर्जी आगे दे? इसमें क्या प्रणाली अपनाई गई है और क्या व्यवस्था बनाई गई है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी एजेंसियां हैं वे पीछे से चली आ रही हैं। जैसे नाइलिट है तो कुछ कर्मचारी नाइलिट के माध्यम से रखे जाते हैं। कुछ कर्मचारी प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए हैं और कुछ हि0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से रखे गए हैं। तीनों एजेंसियां अपना-अपना इंटरव्यू प्रोसैस करती हैं। ठेकेदार टेंडर भर कर कर्मचारियों को रखता है। वह टेंडर कॉल करता है। जैसे हैल्थ में कोई टेंडर कॉल कर दिया कि इतनी पोस्टें आउटसोर्स पर होंगी तो ऐसे भी कर्मचारी रखे गए हैं। नाइलिट अपना इंटरव्यू करता है। हि0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में जहां एम्पैनलमैंट होते हैं उनमें बिडिंग होती है कि कौन कितनी परसेंट लेगा और उसके हिसाब से सर्विसिज आउटसोर्स कर दी जाती हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि क्या उन्हें पूरा पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? मेरा यह मानना है कि कोई भी कंपनी अगर ऐसा करेगी तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी क्योंकि आउटसोर्स की नीति के तहत उन कर्मचारियों को मिनिमम वेजिज मिलने चाहिए। कई बार यह बात आपके और मेरे भी ध्यान में आती है कि कईयों के पैसे काट दिए गए हैं। उन सब चीजों का हमारी सरकार ने ख्याल रखा है। हमने गवर्नमैंट की एक नोडल एजेंसी हि0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन बनाई है। नाइलिट भारत सरकार की एजेंसी है और तीसरी एजेंसी ठेकेदारों के थ्रू है जिनके माध्यम से भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाते हैं। जैसे जल शक्ति विभाग में जिसके बारे माननीय दीप राज जी बोल रहे थे। यदि ऐसी कोई मामला आपके ध्यान में आया है कि किसी के पैसे काटे गए हैं तो आप उसे मेरे ध्यान में लाइए। सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मैं इनके संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं कि

26-8-2026/1105/NS-YK/3

कई बार यह भी लगता है कि हमने आउटसोर्स के ठेकेदार को 40 पोस्टें दे दी हैं लेकिन वहां केवल 30 कर्मचारी ही रखे जाते हैं और 10 पदों पर कोई नहीं रखा जाता है। ऐसे भी मामले हुए हैं और हम आने वाले समय में इसका भी ख्याल रखेंगे क्योंकि मेरे ध्यान में यह बात आई है कि जब 40 कर्मचारी रखने हैं तो 40 से ही उसकी सर्विसिज होनी चाहिए **लेकिन दिखाया जाता है कि मैंने 40 रखे हैं जबकि वास्तव में 40 होते नहीं हैं। हमारे पास कुछ ऐसा मामला हॉस्पिटल्स में आया है। मैं उसका ध्यान रखूंगा।** यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री राकेश जम्वाल------आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

26.08.2026/1110/RKS/Ag-1

प्रश्न संख्याः 3698... जारी

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, कोविड के दौरान नेरचौक मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्तियां की गई थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह उत्तर दिया है कि कोविड समाप्त हो गया है और जिन कर्मचारियों को उस पीरियड के लिए आउटसोर्स किया था अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन अब उन्हीं पदों को पुनः भरने के लिए आउटसोर्स व्यवस्था अपनाई जा रही है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं दी थीं, चाहे वे स्टाफ नर्सिज हों, वार्ड बॉय हों या वार्ड अटैंडेंट, क्या उन्हें पुनः नियुक्ति के समय प्रायोरिटी दी जाएगी?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल, सुन्दरनगर में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। वर्तमान में वह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। वहां ऑपरेटर के रूप में कार्यरत दो युवाओं को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया गया था

किन्तु उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और वह प्लांट बंद पड़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां दोबारा आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां करेगी या कोई अन्य व्यवस्था करेगी ताकि ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से संचालित हो सके?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने कोविड के दौरान मेडिकल कॉलेज, टांडा और आई0जी0एम0सी0 में कार्यरत अनेक कर्मचारियों को पुनः रखने की प्रक्रिया आरम्भ की थी और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को दोबारा नियुक्त भी किया है क्योंकि उन्होंने कोविड काल में सेवाएं प्रदान की थीं। **यदि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कोविड के समय कार्य किया हो और उसे पुनः नहीं रखा गया हो तो सरकार उसे प्रायोरिटी के आधार पर रखने का विचार करेगी।** दूसरी बात, हम मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी और स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स व्यवस्था को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने निर्णय लिया है कि नर्सों की नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर नहीं की जाएगी बल्कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से टैस्ट कंडक्ट करवाकर नियमित प्रक्रिया के तहत भर्ती की जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या कुताही

26.08.2026/1110/RKS/Ag-2

न बरती जाए।अब तक लगभग 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनकी नियुक्ति राज्य चयन आयोग के माध्यम से की गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बी0एस0सी0 नर्सिंग करने वाली लड़कियों की सामान्य वर्ग में अंतिम मेरिट 70 से 80 प्रतिशत अंकों के बीच जा रही है तथा अन्य वर्गों में भी इसी स्तर की मेरिट रही है। जब इस प्रकार की क्वालिटी नर्सिज सेवाओं में आएंगी तो कैनुला इंजैक्शन ढंग से लगाया जाएगा और मरीजों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त लगभग 600 और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। पैरा-मैडिकल स्टाफ में जहां रेडियोग्राफरों आदि की कुछ कमी है वहां कुछ स्तर पर आउटसोर्स व्यवस्था अपनाई जा रही है परन्तु नर्सों की नियुक्ति को पूर्णतः आउटसोर्स व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है और भविष्य में सभी नर्सों की नियुक्तियां केवल टैस्ट के माध्यम से ही की जाएंगी। अगले चार-पांच महीनों में सभी मेडिकल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। लगभग 40 वर्षों से

चली आ रही व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से नए रिफॉर्म्स लागू कर रहे हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक ऑक्सीजन प्लांट का प्रश्न है, यदि नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए तो उसमें छह से आठ महीने का समय लग सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए आउटसोर्स व्यवस्था अपनाई जाती है। ...(व्यवधान) आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। यदि वहां दो ऑपरेटरों की आवश्यकता है तो उनकी सेवाएं आउटसोर्स आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। **जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती या प्लांट का संचालन किसी एजेंसी को नहीं सौंपा जाता तब तक हम वहां दो व्यक्तियों को आउटसोर्स आधार पर रख देंगे।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा यह होनी चाहिए कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए लेकिन आपने पूरे प्रदेश में उससे भी अधिक ठेकेदार खड़े कर दिए हैं। आपने आउटसोर्सिंग में विभिन्न एजेंसियों का एम्पैनलमैंट किया है। जिन बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था उनके स्थान पर कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक तथा चुनाव लड़ चुके लोग उन एजेंसियों के ठेकेदार बने हुए हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1115/बी.एस./ए.जी.-1

प्रश्न संख्याः 3698 क्रमांगत...**श्री जय राम ठाकुर जारी...**

मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपके पौने चार वर्ष के कार्यकाल में आपने कितनी नई आउटसोर्स एजेंसियों को कांट्रैक्टर के माध्यम से एम्पैनल किया है उनकी तफसील और डिटेल्स भी सदन में शेयर की जाए।

दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एम्पैनलमैंट के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? यह मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने शायद इस पर स्टे दिया है कि जो ग्राउंड्स आपने एम्पैनलमैंट के लिए दिए हैं वे भी क्लीयर नहीं हैं तथा जिनका आपने एम्पैनलमैंट रिजेक्ट किया है वे भी क्लीयर नहीं हैं।

यह जो सारा काम चल रहा है वह धक्के से चल रहा है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, यह भी सच्चाई है कि इस प्रकार के तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि जो बेरोजगार रोजगार हासिल करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से अर्जी लगाते हैं उनसे पहले ही आउटसोर्स एजेंसी यानी जो ठेकेदार आपने अपने कार्यकाल में रजिस्टर और एम्पैनल किए हैं वे पहले ही अपना हिसाब-किताब कर लेते हैं। क्या ये सब बातें आपके ध्यान में है? एक तो वे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के साथ-साथ उन बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे बाद में होते हैं लेकिन उससे पहले उनसे हिसाब-किताब किया जाता है। क्या यह सब आपकी जानकारी में है? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आने वाले समय में यह इन्वेस्टिगेशन और जांच का बहुत बड़ा विषय बनेगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में जिस बात को लेकर यह मामला गया है कि एम्पैनलमैंट के ग्राउंड्स क्या हैं और जिनकी आपने एम्पैनलमैंट की है तथा उसके बाद जिनका एम्पैनलमैंट कैंसल किया है क्या उनकी डिटेल भी आप शेयर करेंगे? क्या इस संबंध में भी आप सदन को जानकारी देंगे?

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार के दौरान आउटसोर्स में जो लोग लगे थे और जिन बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया था उनमें से कितने लोगों को आपने घर बिठा दिया क्योंकि वे

25.08.2026/1115/बी.एस./ए.जी.-2

भारतीय जनता पार्टी के समय में लगे थे? जैसा माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों ने अपनी जिंदगी को संकट में डालकर इलाज किया था और अंतिम संस्कार भी किया क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया था। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, हम उस दौर से गुजरे हैं उनको भी आपने नौकरी से निकाल दिया? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को आउटसोर्स पर तुरंत नौकरी देंगे? क्या आप यह सुनिश्चित करके हमें बताएंगे? धन्यवाद।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न का पहले विस्तार से उत्तर दे दिया है फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न आउटसोर्स से रिलेटेड नहीं है फिर भी आप विपक्ष के नेता हैं और आपने कुछ सवाल पैदा किए हैं। मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूं।

आप गुस्सा मत कीजिए, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यह क्वैश्चन प्रश्न से रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि आप कांट्रैक्टर और एम्पैनलमैंट की बात कर रहे हैं। प्रश्न तो आउटसोर्स की पॉलिसी और आउटसोर्स से संबंधित है लेकिन फिर भी आप हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं इसलिए मैं आपको जवाब देता हूं।

अपको एक ठेकेदार से परेशानी है। यह ठीक है कि वह बेचारा आपके विधान सभा क्षेत्र का है और आपकी विधान सभा क्षेत्र में काम ले रहा है तो इनको परेशानी होगी लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको परेशान न करे। आपसे जरूर पूछ ले और जहां तक आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो एम्पैनलमैंट होती है वह एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होती है।

जो एम्पैनलमैंट होती है किसी भी इलैक्ट्रॉनिक्स एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होती है और इसके बाद जो कंडिशन्ज़ होती हैं वे अखबार में आती हैं अखबार में आने के बाद उनका एम्पैनलमैंट होता है। इनके विधान सभा क्षेत्र की एजेंसी का भी एम्पैनलमैंट हुआ। इनके विधान सभा क्षेत्र के जिस आदमी ने एम्पैनलमैंट किया था मैंने

25.08.2026/1115/बी.एस./ए.जी.-3

उनसे पूछा तो इन्होंने एक बार यह बात कही थी, मैं पक्का अगली बार सुनिश्चित करूंगा कि 10-20 आदमी इनके भी लगा देना सारे अपने ही न लगाना।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि हाईकोर्ट में जब मैटर सब-ज्यूडिस होता है और

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1120/DT/AS-1

प्रश्न संख्याः 3698 जारी.....मुख्य मंत्री जारी...

एक पक्ष हाई कोर्ट में जाता है और अगर कहीं गलत हुआ होता है तो उसके खिलाफ वह अपील करता है। उसका रिप्लाई सरकार फाइल करती है कि इन नियमों के अनुसार यह कार्य किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कोई स्टे माननीय न्यायालय से नहीं यह संस्थान हमारे समय से एम्पैनलमेंट नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एम्पैनलमेंट के जो नियम हैं उसमें अगर हमने थोड़ा बदलाव किया होगा। लेकिन जो नियम स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में हैं उसी नियम के साथ एम्पैनलमेंट की गई है। पूर्व भाजपा सरकार के समय में यह हुआ है। तभी तो मैं कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तनाव में रहते हैं।

तीसरी बात इन्होंने कोविड काल के दौरान की कही। मैंने उस प्रश्न का जवाब दे दिया है कि कोविड काल के दौरान जो लोग आउटसोर्स में लगे थे पहले उनको निकाला गया था लेकिन बाद में हमने उनको दोबारा रख लिया है, क्योंकि कोविड के कठिन समय में उन्होंने अपनी सर्विसिज दी है इसलिए हम उनको दोबारा रखेंगे। मैंने यह भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं में मैं आउटसोर्स बिल्कुल बंद करने जा रहा हूं क्योंकि उन सेवाओं को हम सिफारश पर रखते हैं। मेरा प्रयास है कि हैल्थ में जो भी भर्तियां हों वे सिर्फ रिटन टेस्ट के थ्रू होनी चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टाफ नर्सीज को आउटसोर्स में रखना शत-प्रतिशत बंद कर दिया जाए। रेडियोग्राफर, ओ0टी0ए0 और एनेस्थेटिजिया वाले हैं, क्योंकि उनकी पोस्टें कम हैं, तो उसका उत्तर जब हैल्थ में हो रही चर्चा है उसके रिप्लाई में दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम रेडियोग्राफर, ओ0टी0ए0 और एनेस्थेटिजिया इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये सब राज्य छोड़कर यहां से जा रहे हैं। मैंने इनकी पे आउटसोर्स पर पे भी 25 हजार रुपये कर दी है। पिछले 23 वर्ष से यहां पर केवल 18 पोस्टें थीं और आई0जी0एम0सी0 और टांडा में इन

लोगों की ट्रेनिंग होती थी। मतलब सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा। हमने इन सीटों को बढ़ाकर 50 किया है। अब वर्ष 2028 में 50 लोगों का बैच पास आउट होकर निकलेगा। जो हेल्थ सर्विसेज हमारी पिछले कई वर्षों से डिटरिओरेट हुई हैं उनको ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

26.08.2026/1120/DT/AS-2

प्रशंसा तो कम-से-कम दूर की बात है, विपक्ष हमारे लिए दो अच्छे शब्द ही कह भी दे तो भी अच्छा होगा। हमने आपकी सरकार के समय कोरोनाकाल में रखे गये आउटसोर्स कर्मचारी सभी रखे हैं। अगर आपका कोई साथी कोरोना के कारण रह गया होगा, जिसको आप सोचते हैं कि वह बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो मैं उसको भी रख लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष : डॉ0 हंस राज जी नियम 61 में आप पूछ लेना जो पूछना है, अच्छा चलो आप पूछ लो।

श्री डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय आपका, धन्यवाद। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि क्या यह सत्य नहीं है कि आउटसोर्स पॉलिसी है वह संविधान की मूल भावना पर आघात नहीं है? जिस सम्मानता की बात हम लोग करते हैं या जिस opportunity for all and equality for all की बात करते हैं उसमें हमने देखा है और पाया है कि इस आउटसोर्स पॉलिसी में इसकी व्यवस्था नहीं है। एक तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स में रहे हों चाहे वह एक्स-सर्विसमैन हैं, चाहे वह एस0सी0 हैं, एस0टी0 हैं या ओ0बी0सी0 हैं, उसमें कहीं प्रावधान नहीं दिखता है कि इन वर्गों के लोगों को एम्प्लॉयमैंट में अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो।

सर, आपके माध्यम से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जितने ठेकेदार या जो कम्पनियां आउटसोर्स पर मेन-पॉवर उपलब्ध करवाते हैं, उनकी पॉलिसी में भी हमें कहीं इस तरह

का प्रावधान नहीं दिखता। जैसे हम लोग चंबा से आते हैं तो चंबा से कोई हमें आउटसोर्स की कंपनी का ओनर या ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा या चुराह से कोई नहीं मिलेगा। तो क्या यह संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ बहुत बड़ा आघात नहीं हो रहा है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

दूसरा यह है कि जब हम पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं तो इस पर पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते। कैसे बनाएंगे आप? पॉलिसी जब बनाएंगे तब बन सकती है। यह मैटर तो कोर्ट में भी सब ज्यूडिस हो जाएगा। साथ ही साथ संविधान ने में मूल बात दर्शायी गई हैं और प्रीएंबल में ही लिखा हुआ है उसकी अगर भावना को देखें तो हम एक तरह से एक वर्ग विशेष के साथ या जिनको संविधान ने आगे रखा हुआ है या सम्मानता की बात कही गई है,

26.08.2026/1120/DT/AS-3

हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एन्श्योर करेंगे कि आगे चाहे वह आउटसोर्स करने के लिए कंपनियां हायर करे जिनको ठेका देना हो या फिर वह आगे आउटसोर्स में भर्तियां करें तो क्या ये एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और जो स्पोर्ट्स कोटे में निकले हुए लोग हैं या एक्स-सर्विसमैन हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हुआ है उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे?

Speaker : Hon'ble Chief Minister, he asking about the reservation roster in outsourced service.

मुख्य मंत्री : महोदय, हमारी सरकार मेरिट से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। जो भी चुनकर आएगा, रोस्टर भी लगेगा, वो सब राज्य चयन आयोग से मेरिट पर आएगा। कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, जिसमें आप हेराफेरी कर सकते हैं, यह हमारी सरकार ने तय किया है। आउटसोर्स भर्तीयों को मैं कम करने जा रहा हूँ । आपने मेरिटोरियस की बात की? किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री यानी कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। रिटन टेस्ट जो पास करेगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और वह पात्र होगा तो उसे नौकरी लग जाएगी। ये हमने तय किया है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1125/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3698.........जारी-------मुख्य मंत्री.......... जारी

सिफ़ारिश नहीं चलेगी, जो रिटन क्लियर करके आएगा और डॉक्यूमैंट्स चैक करवाएगा, वह नौकरी लग जाएगा। यह हमारी सरकार ने तय किया है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी पूर्व मुख्य मंत्री व मंत्री की सिफ़ारिश नहीं चलेगी। जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, वे ही आगे आएंगे।...(व्यवधान) इसमें स्पीकर साहब की भी सिफ़ारिश नहीं चलेगी। यह तो मैं अभी तय कर देता हूं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, मैं तो सिफ़ारिश करता ही नहीं हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बच्चे पूरे-पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे मैरिट पर आएंगे, उन्हें हम सिलैक्ट करेंगे।...(व्यवधान) हमने उल्टा करने का स्कोप रखा ही नहीं है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। अगर आप (विपक्ष के लिए कहा) भी सरकार में आएंगे तो आप भी उल्टा नहीं कर पाएंगे और अगर आप करेंगे भी तो हम हल्ला करेंगे। मेरा कहना है कि कोई भी बच्चा रिटन टैस्ट व अन्य औपचारिकताएं पास करे और उसके बाद बच्चे के पास सीधा नियुक्ति प्रमाण पत्र होगा।

Speaker : He is asking about the reservation roaster in outsource.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आउटसोर्स पर बात कर रहे हैं तो मैंने इन्हें अनेक बार कहा है कि सर्विसिज़ आउटसोर्स हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, इनका कहना है कि इसमें रोस्टर लगना है या नहीं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें सर्विसिज़ आउटसोर्स हैं और संविधान की जो भी मूल भावना है, हम उसे इम्पलिमैंट करते हैं। यदि आउटसोर्स सर्विसिज़ के संदर्भ में संविधान की मूल भावना में कहीं पर भी रोस्टर के बारे में लिखा होगा तो उसे इम्पलिमैंट करने में हमें कोई एतराज नहीं है।

26.08.2026/1125/ए.एस.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या - 3924 (स्थगित)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है।

(माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राणा द्वारा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया।)

प्रश्न संख्या - 4456

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो CBSE टीचर्स आपने रखे हैं, इनको 10 महीने का वेतन देना तय हुआ है। तो क्या सरकार विचार करेगी कि सरकार अन्य जो अपॉइंटमैंट्स करती है, जिनमें 12 महीने का वेतन मिलता है, तो क्या इनको भी 12 महीने का वेतन दिया जाएगा?

दूसरा, इसमें कंप्यूटर टीचर्स की भी अपॉइंटमैंट हुई है। तो यहां पर जो पहले आउटसोर्स पर कंप्यूटर टीचर रखे हुए थे, उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

तीसरा, ये जो सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमैंट हुई है, तो जिस तरह से अन्य अपॉइंटमैंट्स सर्विस कमीशन/चयन आयोग करता है और दो साल की अवधि के बाद वे रेगुलराइज हो जाते हैं। तो क्या ये जो टीचर रखे गए हैं, इनकी रेगुलराइजेशन का प्रबंध भी सरकार उसी मापदंड पर करेगी?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की क्वालिटी एजुकेशन के प्रति वचनबद्धता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए CBSE के साथ स्कूलों को एफिलिएट करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी शुरुआत माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2025 को की गई घोषणा से हुई थी। उसके उपरांत शिक्षा विभाग ने इसके बारे में अपनी आगे की कार्रवाई की है। इसमें चयन आयोग के माध्यम से रिक्रूटमैंट्स होनी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री और सभी कैबिनेट के साथियों का धन्यवाद व आभार करना चाहूंगा कि इन 147 स्कूलों में हमारी लगभग 6,000 से अधिक जो सैंक्शन पोस्टें हैं, उनके अगेंस्ट 3468 चयन आयोग के माध्यम से CBSE टीचर्स लगने हैं और उसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है।

26.08.2026/1125/ए.एस.-एन.जी./4

माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में स्कीम-बेस्ड नियुक्तियां होंगी और इन्हें 30,000/- रुपये मासिक मानदेय/वेतन मिलेगा। मैं जॉब ट्रेनीज़ के संदर्भ में देख रहा था, तो जो हमारे लेक्चरर हैं, उन्हें 25,800/- रुपये मिलते हैं और इसी प्रकार TGT जॉब ट्रेनीज़ को लगभग 23 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं। माननीय सदस्य ने भविष्य की बात की कि इनको नियमित किया जाएगा या नहीं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वर्तमान में यह हमारी स्कीम-बेस्ड योजना है। लेकिन भविष्य के गर्भ में बहुत-सी बातें छिपी होती हैं और हमें पॉजिटिव व अनुकूल रहना चाहिए। निश्चित रूप में इनकी सेवाओं को देखते हुए और सरकार की क्वालिटी एजुकेशन की कमिटमैंट को देखते हुए, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से एक इन्होंने कंप्यूटर टीचर्स

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.08.2026/1130/DC/PB/1

प्रश्न संख्याः 4456 क्रमांगत... शिक्षा मंत्री जारी...

से संबंधित प्रश्न भी पूछा है वर्तमान में जो अध्यापक वहां कार्यरत है उन्हें निश्चित रूप से एडजस्ट/समायोजित किया जाएगा।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का प्रमाणिक विवरण सदन में रखने को तैयार है कि जो भी स्कूल सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर चलाए गए हैं, वे शिक्षक-छात्र अनुपात, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और स्मार्ट शिक्षा जैसे सभी मानकों को पूरा करते हैं या नहीं? क्या यह आत्मनिर्भर शिक्षा नीति है कि बिना शिक्षक के स्कूल और बिना प्रयोगशाला के बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है? इसके साथ-साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र के केवल एक स्कूल जी0एस0एस0एस0 किलाड़ को सी0बी0एस0ई0 का दर्जा दिया गया है। उसी तर्ज पर भरमौर, होली और दरवाला में एक-एक स्कूल को सी0बी0एस0ई0 स्कूल का दर्जा दिया जाए, धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा 147 सी0बी0एस0ई0 स्कूलों के मापदंड और मानक के संबद्ध में बात की है। इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत जब वे निर्धारित नॉर्म्स तथा मापदंडों को पूरा करते थे तभी उन स्कूलों को यह मान्यता मिली है। इसमें जो थोड़े-बहुत गैप्स रह गए हैं उनको भी आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा।

इसके अलावा माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने भरमौर विधान सभा क्षेत्र का जिक्र किया है। यह प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र है और वर्तमान में वहां एक सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोला गया है तथा उसे घोषित किया गया है। लेकिन वर्तमान में विभाग का यही कहना है कि हमने प्रथम चरण में 147 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के साथ एफिलिएट किए हैं। पहले ये स्कूल प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएं उसके उपरांत ही दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी विभाग की प्राथमिकता है कि जिन 147 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 से एफिलिएट किया गया है उनका कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो

26.08.2026/1130/DC/PB/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 147 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध करने का क्या पैमाना था, इसके क्या प्रावधान थे और किस आधार पर स्कूलों का चयन हुआ है? मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री नैना देवी जी में दो स्कूल सी0बी0एस0ई0 के साथ संबद्ध किए गए हैं। हालांकि प्रश्न के उत्तर में एक स्कूल ही दर्शाया है किंतु बिलासपुर के साथ-साथ जुखाला भी मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आता है।

दूसरा, श्री नैना देवी जी विधान सभा का क्षेत्र काफी विस्तृत है और जो दो स्कूल सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध किए गए हैं वे एक ही ब्लॉक के हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के तीन ब्लॉक हैं। उनमें से दो ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें एक भी स्कूल नहीं है। वहां के बच्चे अगर सी0बी0एस0ई0 की शिक्षा लेना चाहेंगे तो क्या वे डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जाएंगे? इन विद्यालयों को खोलने में जो कमी रही है उसको कैसे दूर किया जाएगा? आपके द्वारा सी0बी0एस0ई0 से स्कूलों को संबद्ध करने के समय जनप्रतिनिधियों और हम विधायकों की कोई राय नहीं ली गई? उसके कारण जो डिस्पैरिटी आई है उसको दूर करने में क्या आप विधायकों की राय लेंगे और क्या क्षेत्र के आधार पर जो डिस्पैरिटी रही है उसको दूर करने के लिए तुरंत नए स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध करेंगे?

दूसरा, आपने 147 स्कूलों में सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम शुरू किया है। परंतु मैं देख रहा था कि अभी भी शिक्षकों के लगभग 3,494 पद खाली हैं। आपने उत्तर में लिखा है कि इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परंतु सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम शुरू करना और वह भी बिना शिक्षकों के, इससे तो अच्छा था कि हमारे प्रदेश के शिक्षा बोर्ड का ही पाठ्यक्रम चलता रहता।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या 4456 जारी .....श्री रणधीर शर्मा जारी ....

तो कब तक आप इन खाली शिक्षकों के पदों को भरेंगे, जिस से आपका सी0बी0एस0ई0 शिक्षा देने का उद्देश्य पूरा हो सके? क्या आप समयबद्ध बताएं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कहना चाहूंगा जो भाई रणधीर जी ने डिस्पैरिटी की बात कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने अपने विधान सभा क्षेत्र को भी देखा होगा। वहां दो स्कूल हैं, जिनमें जुखाला को भी आपने सम्मलित किया है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरी विधान सभा में भी लगभग यही संख्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी दो-तीन स्कूल सी0बी0एस0ई0 से अफिलिएट किए गए हैं। आपने यह प्रश्न भी किया है कि किस आधार पर इन स्कूलों का चयन किया और चयन प्रक्रिया क्या थी? मेरी समझ में इसका मुख्य आधार सी0बी0एस0ई0 के नॉर्म्स के अनुसार अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रहा है। बहुत से हमारे ऐसे स्कूल भी थे, जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। उन स्कूलों को भी हमने अनुमोदित किया था और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्ताव भेजे था लेकिन वे सी0बी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर हमारे तीन से अधिक ऐसे प्रस्ताव थे। जिन्हें सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अफिलिएशन नहीं मिली। इसका कारण यही था कि वे सी0बी0एस0ई0 के नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने डॉक्टर साहब के प्रश्न के उत्तर में भी कहा है कि भविष्य में जब ये पहले चरण के हमारे 147 स्कूल प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएंगे। जैसा आपने कहा कि वैकेंसीज़ रही हैं। वर्तमान में हमारे यहां लगभग 3,830 टीचर उपलब्ध हैं। इसके अलावा over and above मैंने जिन टीचर्स की बात की थी, उनमें लगभग 820 टीचर्स की नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। इनमें मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, फिजिक्स टीचर, बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री टीचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर शामिल हैं। अभी तक 820 टीचर्स की नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की चयन प्रक्रिया भी चयन आयोग द्वारा पूरी हो चुकी है। इनको भी फर्दर स्टेशन दिए जाएंगे। साथ ही, जो शेष श्रेणियां हैं उनको भी माननीय मुख्य मंत्री जी डे-टू-डे बेसिस पर मॉनिटर कर

रहे हैं। जैसा कहा गया है कि एक माह के भीतर जितनी भी चयन आयोग, हमीरपुर के पास पोस्टें भेजी गई हैं, उनको भरा जाएगा।

26.08.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0-02

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेशन के मध्य में ही सी0बी0एस0ई0 सिलेबस की तरफ स्विच ऑन करने की क्या जरूरत पड़ गई? आनन-फानन में, जबकि सरकार पहले चरण में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, 154 स्कूलों की नोटिफिकेशन हुई और अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 अन्य स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 में लाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 17,064 सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं जोकि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी संख्या में पब्लिक स्कूल भी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आनन-फानन में 154 स्कूलों और अब अन्य 100 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 में स्विच ऑन करने की इतनी जल्दबाजी का कारण क्या है?

दूसरा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इससे लगभग 25 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जब स्कूलों को हिमाचल बोर्ड से सी0बी0एस0ई0 बोर्ड में बदला जाएगा। जब 100 अन्य स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से जोड़ा जाएगा तो यह घाटा लगभग 45 करोड़ रुपये का हो जाएगा। यानी इस घाटे की आपूर्ति स्टेट एक्सचेकर से होगी या नहीं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि स्कूलों से जो फीस आती है, एग्जामिनेशन फीस आती है या अन्य मदों से पैसा आता है, उसी से बोर्ड संचालित होता है और चलाया जाता है। अगर इतने स्कूल हिमाचल प्रदेश बोर्ड से सी0बी0एस0ई0 में चले जाएंगे तो बोर्ड को तो लकवा मार जाएगा। वहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह और नई भर्ती पर भी रोक लग सकती है। एक तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं।

दूसरा क्या इन साढ़े तीन सालों में गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हुई है? आपने तो किसी पब्लिक मंच के माध्यम से यह भी कहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। मैं श्री जयराम ठाकुर जी से पूछ रहा था कि आप कहां पढ़े हैं। वे कहते हैं कि हमारे

समय में कहां पब्लिक स्कूल होते थे। कुल मिलाकर यहां बैठे हुए तमाम साथी, ऑनरेबल एम0एल0ए0

श्री ए0टी0 जारी.....

26.08.2026/1140/AT/HK/01

श्री विपिन सिंह परमार जारी ....

18 किलोमीटर चलते थे, जैसा कि यह कह रहे हैं। तो ये रातों-रात इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा करते। अब माननीय सुधीर शर्मा जी ने प्रश्न पूछा है कि मैथ और इंग्लिश के आप टीचर रखेंगे, पर बारह महीने की उनको सैलरी नहीं मिलेगी और दस महीनों की सैलरी दी जाएगी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन पौने चार साल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हुई है? दूसरा, जो चयन प्रक्रिया दस महीनों के लिए मैथ और इंग्लिश के अध्यापक रखे गए हैं, क्या ऐसे अध्यापकों के बारे में कोई एक ठोस योजना बनाई जाएगी?

तीसरा, अखबारों में खूब छप रहा है।...(व्यवधान) नहीं-नहीं, सुनो तो सही। जिन बच्चों ने सी0बी0एस0ई0 स्कूलों में एडमिशन ली है, उनमें अफरा-तफरी मची हुई है और बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं। एन0सी0ई0आर0टी0 का सिलेबस तय नहीं हुआ है और नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने स्कूल बदल लिए हैं और पेरेंट्स में असंतोष है। कुल मिलाकर आप ये तय करें कि जब आप कोई योजना शुरू करते हैं तो उसके लिए वहां पर फुल-प्रूफ सारी व्यवस्थाएं पहले से पूरी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्षः आप प्रश्न करिए।

श्री विपिन सिंह परमारः मैं सुझाव दे रहा हूं जी।...(व्यवधान) तो तैयारी होनी चाहिए। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका फंडिंग का प्रोविजन क्या है? भारत सरकार के

द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वित्त पोषण का क्या प्रावधान है? मंत्री जी, इन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं।

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रश्न भी बहुत हो गए।

26.08.2026/1140/AT/HK/02

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रेम भी बहुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक परमार साहब, जो हमारे सदन के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यहां पर सी0बी0एस0ई0 स्कूल से संबंधित, उनके अनुसार जो समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में बात रखी।

मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये भी शुरुआती दौर है, ट्रांजिशन पीरियड है और हमें ये निर्णय लेना पड़ा, उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट घट रही है, वह एक प्रमुख कारण है। सरकारी स्कूल चाहे आपकी सरकार रही हो, मैं पिछले पंद्रह वर्षों का ही देख रहा था। पिछले लगभग पंद्रह वर्षों में, जिसमें दो दफा आपकी सरकारें रही हैं और दूसरी हमारी सरकार चली हुई है, लगभग चार लाख के आसपास सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई है और मैं समझता हूं उसमें एक प्रमुख ट्रैक्शन जो रहती थी कहीं न कहीं, वह ये भी थी कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स अधिकतर सी0बी0एस0ई0 से अफिलिएटेड हैं। तो इस सोच के साथ भी सरकार आगे बढ़ी। जैसे मैंने कहा कि पंद्रह अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई थी और उसके उपरांत ये सारा क्रम और कार्य प्रारंभ हुआ।

निश्चित रूप से, जहां मैंने संख्या की बात की, जो इसका प्रमुख कारण था जिसके कारण ये निर्णय लिया गया साथ ही साथ इसके अलावा एक हेल्दी कंपटीशन भी आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। इसमें भी कोई दोराय नहीं कि पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बेहतर बोर्ड हैं, उनमें हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो धर्मशाला में है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीछे भी परख के द्वारा जो आपके सारे सर्वे शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, उसमें जो मॉडल बोर्ड के रूप में, टॉप टू मॉडल्स के रूप में जिनको घोषित करने की बात की जा रही है, उसमें गोवा एजुकेशन बोर्ड और दूसरा हमारा हिमाचल एजुकेशन बोर्ड है और इसमें मेरा ये भी मानना है कि हमें कॉन्शियसली इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक

अल्टरनेटिव के रूप में सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स भी हों और साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से अफिलिएटेड स्कूल हैं लगभग अगर आप बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,985 है। उसमें 147 हमने यहां कर दिए हैं। इसके अलावा भी इन टोटल लगभग 14 हजार के आसपास स्कूल हैं। लगभग

26.08.2026/1140/AT/HK/03

हम कह सकते हैं कि 95 प्रतिशत से अधिक हमारे जो स्कूल हैं, वे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास हैं, जिसको मैं बहुत अच्छा बोर्ड मानता हूं।

इसके अलावा, चाहे आप कंट्री लेवल पर जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे प्रदेश की उसको लाइन किया गया है, आपके राष्ट्रीय स्तर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें बेहतर आपकी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तैयारी की जा सकती है। नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। वहां बहुत सी एडवांटेजेस हैं। साथ ही साथ यहां पर आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की। तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है और इन साढ़े तीन-चार वर्षों में आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो NAS की रिपोर्ट थी और वो सरकार की NAS की रिपोर्ट होती है ...(व्यवधन) सुन रहे है जब उपलब्धि की बात आती है, परमार साहब, वहां भी आ रहे हैं, थोड़ा वो भी प्रेम से सुन लो आप है उस वक्त जब रैंकिंग की बात आती है, आप चिढ़ जाते हैं।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1145/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 4456------- क्रमागत------शिक्षा मंत्री------ जारी

वर्ष 2021 में हमारी रैंकिंग 21वें स्थान पर थी। ...(व्यवधान) यह एन0ए0सी0ई0 की रिपोर्ट है, यह हमारी कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। हम सभी हिमाचली हैं, उसके बाद हम बी0जे0पी0 और कांग्रेस पार्टी में हैं। हमारी गिनती टॉप फाइव स्टेट्स में हुई है। अगर हम 28 राज्यों की बात करें तो एन0ए0सी0ई0 की रिपोर्ट के अनुसार हम तीसरे नम्बर पर हैं और यदि यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो अण्डरस्टुड है कि

चण्डीगढ़ जैसी यूनियन टेरेटरी हमारे से आगे हैं तथा उसके अनुसार हमारी 6वीं रैंक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स में 28 राज्यों में हमारा रैंक थर्ड और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हम 6वें नम्बर पर हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-24 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल के बच्चों का रीडिंग और लर्निंग लैवल गोवा से भी बेहतर है। ...(व्यवधान) माननीय विपिन सिंह परमार, यह हंसने वाली बात नहीं है अपितु एक खुशी व हम सबके लिए बधाई की बात है। यह रोहित ठाकुर या हमारी सरकार की स्टेटमैंट्स नहीं है बल्कि यह केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्टेटमैंट्स हैं। पूर्व में चाहे हमारी पार्टी की सरकार रही या आपकी रही या फिर हिमाचल निर्माता डॉ0 यशवन्त सिंह परमार के समय से लेकर बात की जाए तो यहां पर शुरू से शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसके चलते हमारे प्रदेश ने 99.30 प्रतिशत लिटरेसी रेट प्राप्त किया है। यह हमारे पहाड़ी जैसे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमैंट है। हिमाचल का बहुत सारा हिस्सा पंजाब से कटकर हिमाचल में सम्मिलित हुआ था। अगर आप पंजाब की बात करे तो वहां का लिटरेसी रेट वर्तमान में 83 प्रतिशत रह चुका है। लेकिन हिमाचल में कांगड़ा, सिरमौर, चम्बा और लाहौल-स्पिति जैसे दुर्गम क्षेत्र का लिटरेसी रेट भी 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए गर्व की बात है।

हमारी सरकार ने जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित निर्णय लिए हैं, हालांकि हमारी सरकार ने और भी कई निर्णय लेने थे परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप में कई बार कहीं-न-कहीं आपका सहयोग नहीं मिलता और कभी यहां से नहीं मिलता। ...(व्यवधान) मैंने माननीय श्री जगत सिंह नेगी के लिए बोला है। कल यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर कह रहे थे, तो मेरे हिसाब से 19 बच्चों की

26.08.2026/1145/av/yk/2

एनरोलमैंट वाले कॉलेज की कोई महत्वता नहीं बनती। मैं भलई कॉलेज के बारे में देख रहा था कि आपके कार्यकाल के दौरान भी वहां पूरे पांच वर्षों में केवल 1-2 प्रोफैसर थे और हमारे कार्यकाल में भी शायद वैसा ही क्रम चलता रहेगा। जिसके कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में वे बच्चे कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो

आज समय आ चुका है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे तभी आने वाले समय में हमारा शिक्षा विभाग सुदृढ़ होगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से जवाब दे दिया है। लेकिन कुछ सवाल जो विपक्ष ने पैदा किए और जिन सवालों के बारे में इनको कुछ शंकाएं हैं, मैं उन शंकाओं को दूर करना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सी0बी0एस0ई0 का आइडिया कहां से आया या कंसीव किया गया। मैं एक स्कूल में गया जहां पर यह भिन्नता पाई गई कि एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वे सी0बी0एस0ई0 पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे एच0पी0 बोर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। उसमें प्रथम कक्षा से इंग्लिश मिडियम में पढ़ाई होती है और गवर्नमैंट स्कूल्ज में पहली कक्षा से पढ़ाई नहीं होती। वर्ष 2021 में हम क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर पहुंच गए थे। हमने यह सोचा कि उस क्वालिटी को कैसे इंम्प्रूव करना है। यहां पर शिक्षा संस्थान खोल दिए गए लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकारी स्कूल्ज में एनरोलमैंट डाउन क्यों जा रही है। इन सारी चीजों का आंकलन करने के बाद मैंने 15 अगस्त को सरकाघाट, मण्डी में घोषणा की और जैसे यहां पर श्री विपिन सिंह परमार जी बोल रहे थे कि कुछ बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति बहुत कम जगह पर है और सी0बी0एस0ई0 के कारण इस बार 24000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल्ज में एनरोल हुए हैं।

दूसरा, यहां पर कहा जाता है कि हमारे एच0पी0 बोर्ड को यह घाटा होगा या वह घाटा होगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिक्षा घाटे या फायदे के लिए नहीं होती। शिक्षा एक बच्चे को एक प्रकार से निखारने और संवारने के लिए होती है ताकि उसके मन में आत्मविश्वास पैदा हो। हमारी सरकार ऐसी शिक्षा नीति पर काम कर रही है जहां भविष्य में जो भी बच्चा स्कूल और कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके बाहर

26.08.2026/1145/av/yk/3

जाएगा तो गर्व से कहेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश से पढ़ा हूं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं; हमारी सरकार इस प्रकार की शिक्षा नीति पर काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और सी0बी0एस0ई0 स्कूल्ज में

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1150/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
प्रश्न संख्या : 4456... क्रमागत्
मुख्य मंत्री ... जारी

जहां तक सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स का प्रश्न है उनके बारे में, मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं। सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स में जितने टीचर्स हैं उनमें फिजिक्स और मैथ के टीचर्स सहित सभी विषयों के टीचर्स के प्रत्येक रिजल्ट की जानकारी मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर ले रहा हूं। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है और जिन स्कूलों में टीचर्स उपलब्ध नहीं है वहां अगले दिन पोस्टिंग कर दी जा रही है। ...(व्यवधान) टी0जी0टी0 वालों की भी पोस्टिंग की जाएगी। आप इसकी चिंता न करें।

अध्यक्ष महोदय, आज कंप्यूटर टीचर और म्यूजिक टीचर का रिजल्ट भी निकला है। सरकारी स्कूलों में म्यूजिक का सब्जैक्ट बहुत कम स्कूलों में था। यह केवल शहरों में ही था। हमने निर्णय लिया है कि बच्चों को जियोग्राफी से लेकर साइकोलॉजी तक सभी विषयों के टीचर्स सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स में उपलब्ध करवाए जाएं। मुझे खुशी है कि 30 सितंबर तक सभी सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स में ये टीचर्स रख दिए जाएंगे। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं। यदि ऐसा नहीं होता है तो दिसंबर में आप मुझसे प्रश्न पूछ लेना।

दूसरी बात यह है कि 10 महीने में किस क्वालिटी के टीचर्स आ रहे हैं। एक तरफ तो माननीय सदस्य श्री विपिन परमार जी आप एम्प्लॉयमैंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने कहा है कि 10 महीने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। मैं 10 महीने के लिए रखे गए टीचर्स की क्वालिटी के संबंध में बताना चाहता हूं...(व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको प्रश्न का जबाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष : यह इसी क्वेश्चन के संबंध में पूछी गई सप्लीमैंटरी का जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मेरे अभी दो-तीन मिनट ही हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, please take your seats. ...(Interruption)

26.08.2026/1150/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : जो टीचर्स 10 महीने के लिए लगाए गए हैं उनकी क्वालिटी के संबंध में मैं बताना चाहता हूं। जो बच्चे अपीयर हुए और उनकी क्वालिटी के संबंध में मैंने कल भी बताया था। हमने क्वालिटी कैसे इन्श्योर की है यह भी स्पष्ट किया था। यदि किसी ने टीचर इंग्लिश के पद पर नियुक्त होना है तो उसकी ग्रेजुएशन में संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में भी 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके साथ ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत अंक, एम0ए0 में 55 प्रतिशत अंक और बी0एड0 होना आवश्यक है यानी वह इसके लिए एलिजिबल है और उसकी मेरिट 80 प्रतिशत तक गई है। 80 प्रतिशत मेरिट तक के सभी अभ्यर्थी नियुक्त हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने पूछा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी0बी0एस0ई0 स्कूल नहीं खुले हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपसी समन्वय से स्कूल खोलना चाहती है। अभी 100 स्कूल और खुलने हैं। जब बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तब आपके विधान सभा क्षेत्र में भी सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोले जाएंगे। एक तरफ आप सी0बी0एस0ई0 पर क्वेश्चन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा सबसे बेहतर होने जा रही है और हम सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोलने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इन सीबीएसई स्कूल्स में 147 स्कूल हमने किए हैं। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी का स्कूल भी अवश्य खुलेगा। आप निश्चिंत रहें। इन 147 सी0बी0एस0ई0 स्कूल्स अभी कंप्यूटर लैब एस्टैब्लिश करनी है। इसके लिए मैं 80 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आज दो ही प्रश्नों में एक घंटा हो गया है और अभी भी विपक्ष के माननीय सदस्य सप्लीमैंटरी के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं। ...(व्यवधान) After the Hon'ble Chief Minister's reply and the Hon'ble Opposition's question, I think there is no chance now for further supplementaries.

26.08.2026/1150/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

मुख्य मंत्री : डॉ0 जनक राज ने आत्मनिर्भरता की बात कही ...(व्यवधान) केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं आया है और ये जो आत्मनिर्भर एजुकेशन की बात कर रहे हैं वह आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर एजुकेशन होगी।

अध्यक्ष : चलिए, प्लीज, प्लीज। Please, take your seats now. बैठिए। बैठिए। ...(व्यवधान) Please, take your seats. अभी भी विपक्ष की ओर से सप्लीमैंटरी के लिए बहुत-सारे हाथ उठ रहे हैं। ...(व्यवधान) प्लीज, प्लीज, Please, take your seats. Nothing is going on record. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister reply.

एन0एस0 द्वारा .... जारी

26-8-2026/1155/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 4456 -----क्रमागत-------

मुख्य मंत्री : ...(व्यवधान) आपको बहुत गुस्सा है। आपके छह माननीय सदस्यों ने क्वैश्चन किए हैं, क्या उनका जवाब नहीं देना है? ...(व्यवधान) अभी तो एक और है। आपके छह माननीय सदस्यों ने क्वैश्चन किए हैं क्या उनका जवाब नहीं देना है? ...(व्यवधान) आप गुस्सा न हों। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिए, चलिए, माननीय मुख्य मंत्री जी आप बोलिए। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां आत्मनिर्भर एजुकेशन की बात है...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो आत्मनिर्भर एजुकेशन की बात की है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिए, चलिए, जवाब आ गया। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जो पूछा है डॉ0 जनक राज जी ने पूछा है। आप उनको पूछिए। ...(व्यवधान) वे हां कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जोर से बोलकर किसी को थोड़ी बिठाया जा सकता है। जो सवाल पैदा करते हैं उनके उत्तर भी सुनने चाहिए। उत्तर इसलिए नहीं सुने जा रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे उत्तर आ रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इनको उत्तर सुनने में बहुत तकलीफ हो रही है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये आत्मनिर्भर शिक्षा की दिशा में फंडिंग की बात कर रहे थे। ...(व्यवधान) आप देखिए, अब इन्होंने और पूछ लिया। आप माननीय बिक्रम सिंह को चुप करवाइए। अध्यक्ष महोदय, इसका फंडिंग पैटर्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सारा पैसा वहन कर रही है। जो टीचर 10 महीने के लिए टैस्ट के थ्रू रखे गए हैं इनके संबंध में भी इन्होंने सवाल पूछा है। पहले पी0टी0ए0 और एस0एम0सी0 में टीचर्ज रखे जाते थे। **जो टीचर्ज 10 महीने के लिए टैस्ट के थ्रू रखे हैं उनके बारे में सरकार भविष्य में गंभीरता से विचार करेगी।**

26-8-2026/1155/NS-YK/2

प्रश्न संख्या : 4457

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न करूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा without prejudice to anybody. देखिए, बहुत समय लग रहा है। अभी दो प्रश्नों में पूरा टाइम एग्जॉस्ट हो गया। हमारे बहुत सारे विधायक इंतजार करते हैं कि उनके प्रश्न लगें। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि बिना तर्क के बहस न करें। जो स्पैसिफिक क्वैश्चन है वह पूछें और उसका जवाब दें। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है।

Speaker : This is my concern also but you see since nobody is likely to cooperate.

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न का उत्तर आया है। कुमारसैन पुलिस थाना वर्ष 2023 की आपदा में बिल्कुल नष्ट हो गया था। अभी वह अस्थायी रूप से अस्थायी भवन में चल रहा है और वहां टैंपोरेरी तौर पर हवालात बनाई गई है जो बिल्कुल असुरक्षित है। विभाग को एन0ओ0सी0 सौंप दी गई है। मुझे लग रहा है कि प्रक्रिया में बहुत टाइम लग रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसे समयबद्ध तरीके से जल्दी-से-जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त महोदय से एन0ओ0सी0 आना शेष है। **मैं उनको निर्देश दूंगा कि इसकी एन0ओ0सी0 शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाए।**

प्रश्न संख्या : 4458

श्री सुख राम चौधरी : उपस्थित नहीं।

26-8-2026/1155/NS-YK/3

प्रश्न संख्या : 4459

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैंने एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मामलों को लेकर यह प्रश्न किया था। चिट्टे को रोकने के लिए सरकार ने जो एस0टी0एफ0 स्थापित की है उसकी मैनपॉवर बहुत कम है जबकि चिट्टा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

26.08.2026/1200/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 4459... जारी------श्री केवल सिंह पठानिया... जारी

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसकी रोकथाम के लिए आने वाले समय में कम-से-कम 500 अतिरिक्त कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि पूरे प्रदेश में पेट्रोलिंग और सर्च अभियान चलाया जा सके। चिट्टा प्रदेश के युवाओं के लिए एक गंभीर नशे की समस्या बन चुका है? दूसरा, क्या इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक व्हीकल तथा अन्य जरूरी इक्विपमैंट्स एवं किट उपलब्ध करवाई जाएंगी? तीसरा, सरकार ने जो चिट्टे के विरुद्ध जन-आंदोलन चलाया है उसकी गूंज न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। आपने दिसंबर के बाद जो एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन आयोजित की है, क्या निकट भविष्य में अन्य जिलों में भी ऐसी एंटी-चिट्टा वॉकथॉन आयोजित की जाएंगी? इसके अतिरिक्त, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 50 जिलों को 'ए' श्रेणी में चिन्हित कर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है जबकि यहां चिट्टे की समस्या लगातार बढ़ रही है। क्या प्रदेश सरकार इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाकर हिमाचल प्रदेश के जिलों को भी 'ए' श्रेणी में शामिल करवाने का प्रयास करेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया है। निश्चित रूप से चिट्टे के विरुद्ध हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिन आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं को चिट्टे के स्मगलर चिट्टे की लत लगाने में लगे होते हैं उन आयु वर्ग के बच्चों के लिए हमने वॉकथान की जिसकी शुरुआत शिमला से हुई। हम 7 सितम्बर को ऊना में और उसके बाद मंडी में वॉकथॉन आयोजित करने जा रहे हैं ताकि चिट्टे के विरुद्ध जागरूकता अभियान को और तेजी दी जा सके। चिट्टे के कारोबार से अर्जित धन तथा उससे निर्मित संपत्तियों को हमारी सरकार ने अवैध घोषित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की है। चिट्टे के माध्यम से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। अनेक स्थानों पर

एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। **माननीय सदस्य ने एस0टी0एफ0 में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की बात की है जिस**

26.08.2026/1200/RKS/AS-2

पर सरकार विचार करेगी और आवश्यकता अनुसार पुलिस बल में वृद्धि की जाएगी। मैं यह बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमने पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए हैं कि चिट्टे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के संबंध में यदि कोई नेता, अधिकारी या कोई अन्य इन्फ्लुएंशियल पर्सन किसी प्रकार की सिफारिश करता है तो उसे स्वीकार न किया जाए। चिट्टे के स्मगलरों को कानून के अनुसार जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। जो सरकारी कर्मचारी चिट्टे के मामलों में संलिप्त पाए गए थे उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई है। चिट्टे में संलिप्त पुलिस विभाग के 21 कर्मचारियों को हमने सेवा से निकाल दिया है तथा अन्य मामलों में भी कार्रवाई जारी है। चिट्टे के विरुद्ध इस सदन की एकमत राय है। हम सभी चाहते हैं कि प्रदेश का कोई भी युवा इस नशे की चपेट में न आए। चिंता का विषय यह है कि 17 से 23 आयु वर्ग के युवाओं को इस लत में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। 23-24 आयु के बाद के युवा इसकी चपेट में कम ही आते हैं। हमें दुःख इस बात का है कि चिट्टे के कारोबार में बच्चों का उपयोग कूरियर के लिए किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। हम चाहते हैं कि माता-पिता भी इस अभियान में अपना सहयोग दें। पहली बार पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग की गई है और नॉर्थ नार्कोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की प्रशंसा नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि चिट्टे के विरुद्ध लड़ाई हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शिक्षण संस्थानों तक जहां भी चिट्टे से संबंधित कोई मामला सामने आए तो आप उसकी सूचना 1100 हैल्पलाइन नंबर पर दें और बच्चों और युवाओं को भी इस संबंध में जागरूक करें। **मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति चिट्टे की लत का शिकार है तो सरकार उसे रिहैबिलिटेशन के माध्यम से पुनर्वास प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का भी प्रयास करेगी। धन्यवाद।**

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। अब शून्य काल में विषय उठाए जाएंगे। कल भी कुछ विषय शेष रह गए थे और आज भी आठ विषय सूचीबद्ध हैं। इनमें पहला विषय श्री बिक्रम सिंह का है और वह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अब शून्य काल की कार्यवाही प्रारम्भ कर लेतें हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप क्या कहना चाहते हैं।

26.08.2026/1200/RKS/AS-3

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर बहुत लंबा दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधान सभा है, जनसभा नहीं है। यहां उत्तर के रूप में भाषण दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि स्पैसिफिक रिप्लाई ही दिया जाना चाहिए।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1205/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

यहां उत्तर के रूप में भाषण आ रहा है। सरकार की ओर से स्पैसिफिक रिप्लाई आना चाहिए।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, एक मिनट, मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। जब सप्लीमेंटरी में भाषण आना है तो फिर जवाब में भी उससे ज्यादा भाषण आना है। That is my concern. Yesterday also, I ventilated that concern. आप गुस्सा हो गए और बहुत सारे सदस्य बाहर चले गए। मेरा भी यही कंसर्न है कि मैक्सिमम क्वैश्चन लगे हैं और सप्लीमेंटरी भी अगर स्पैसिफिक हों और उसका जवाब भी स्पैसिफिक हों। आदरणीय सुधीर शर्मा जी के

अलावा कोई भी सप्लीमेंटरी स्पैसिफिक नहीं था। He was very specific in his supplementary.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय को लेकर थोड़ा-सा जरूर कहना चाहूंगा कि यह मानसून सत्र 21 अगस्त को यहां शुरू हुआ। यहां सदन में शुरू में राष्ट्रीय गान गाया गया और पूरे सम्मान के साथ गाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय गान पूरे सम्मान के साथ गाया। लेकिन एक अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि उसमें से एक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई।

मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन के अंदर कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, सदन के अन्दर नहीं, सदन के बाहर कहा।

श्री जय राम ठाकुर : सदन के अन्दर भी है और सदन के बाहर भी **कहा** है।

अध्यक्ष : यह सदन के बाहर है। There is nothing on the record as such. ...(Interruption) आपने तो वीडियो भी देख लिया है। सदन के अंदर ऐसा बयान कहां है?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार का रैफरेंस आया तो स्वाभाविक रूप से हमारा यह जानना आवश्यक बनता था कि सच्चाई क्या है? इसके लिए हमने बार-बार आपके समक्ष आग्रह किया। आपने कहा कि मैं सारी चीजों की डिटेल्स देख रहा हूं और

25.08.2026/1205/बी.एस./ए.जी.-2

उसके बाद इसके बारे में व्यवस्था दूंगा। आखिरकार आपने पिछले कल व्यवस्था दी जिसके लिए मैं आपका आभारी भी हूं।

आपने जो वीडियो उपलब्ध करवाया क्योंकि साक्ष्य के रूप में हमारे पास इस सारी चीज को वैरिफाई करने के लिए और उसको ठीक तरह से देखने के लिए वीडियो ही एकमात्र जरिया था और वीडियो ही एक माध्यम था। आपने वीडियो जारी किया और उस

वीडियो को मैंने तो कम-से-कम 10 बार देखा। 10 बार देखने के बाद हमारे माननीय सदस्यों ने भी उसको देखा और मिलकर भी देखा कि कहीं गलती से कोताही तो नहीं हुई है? अगर हुई है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। उसके लिए सजा देने की बात है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, पूरा राष्ट्रीय गान विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरे सम्मान के साथ गाया है। उसके बावजूद विधान सभा के अंदर इस विषय को लेकर प्रदर्शन किया गया। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उस बात को लेकर मीडिया में एक बार नहीं बल्कि बार-बार बाइट दी कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है।

कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला किया कि पूरे जिला स्तर पर हैडक्वार्टर्ज़ पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जब हमने साक्ष्य के रूप में वीडियो देखा तो उसमें ऐसी चीज है ही नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रिविलेज का विषय बनता है।

हम अपने दल की ओर से मुख्य मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे। उसके साथ-ही-साथ अध्यक्ष महोदय, हम हाईकोर्ट में भी मानहानि का और यह आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) का मामला बनता है। यह बहुत गंभीर विषय है राष्ट्रीय गान का अपमान न हम सुन सकते हैं और न ही बर्दाश्त कर सकते हैं।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में जो झूठ बोला गया। आपने सदन के अंदर 68 लोगों के बीच में झूठ बोला। 68 नहीं बल्कि आप 75 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे है और उन सब से झूठ बोला। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

Speaker: This is not on the record.

25.08.2026/1205/बी.एस./ए.जी.-3

श्री जय राम ठाकुर : आपने जो व्यवस्था दी और आपने जो वीडियो दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी रत्ती भर भी इस प्रकार

का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होता कि जहां राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) अभी आपने नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया परंतु यह किसी नियम के तहत नहीं था। अभी जीरो आवर की आगे कार्रवाई चलनी थी परंतु वे बीच में उठकर जीरो आवर को ही खत्म कर देते हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1210/DT/AS-1

राजस्व मंत्री जारी...

इन्होंने फिर तीन दिन पहले का मुद्दा उठा दिया गया है। अब इसमें जिस सी0डी0 और वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें इस माननीय सदन में जो कैमरा लगा है उसमें जिस व्यक्ति को आप परमिट करते हैं उसी के ऊपर फोकस होता है न कि जो बीच में इंटरप्ट करता है उस पर कैमरा आता ही नहीं है। इसलिए ये बार-बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि वीडियो की कॉपी दी जाए। मैंने भी वीडियो क्लिप के इसके लिए अप्लाई किया था और मुझे भी पता था कि क्योंकि जब आपने व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रगान शुरू होना है श्री विपिन सिंह परमार जी उस दिन पहले ही हाथ खड़े करके उसे रोकने बैठ गये। इन्होंने इसका वीडियो देख लिया इनको पहले भी पता होता है लेकिन जब आपने मुझे परमिट किया और मैं बोल रहा हूं तो कैमरा मेरे ऊपर ही है। लेकिन जो अभी ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं तो वह केमरा अभी भी इनके ऊपर नहीं है। इन्होंने जो हल्ला किया वह तो वीडियो में दिखता ही नहीं उसमें केवल आवाजें जरूर आती हैं लेकिन शक्ल दिखाई नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष और श्री विपिन सिंह परमार जी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। राष्ट्रगान गाना इस सदन का बहुत लंबे समय से प्रिसिडेंट रहा है की जिस दिन सत्र शुरू होगा उस दिन राष्ट्रगान शुरू होगा। अब राष्ट्रगान शुरू होने से पहले ही ये कह रहे थे कि राष्ट्रगीत गाओ। इसलिए यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं है तो और क्या है? कौन कर रहा था? यही लोग

राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तो उस दिन सदन में थे ही नहीं। अभी भी अगर वीडियो दिखाया जाए तो जो मुझे इंटरप्ट कर रहे थे वह उस वीडियों में आएंगे ही नहीं। इसका फायदा उठाकर ये जो इन्होंने राष्ट्रगान का इतना बड़ा अपमान किया है अब ये राष्ट्रगीत के बहाने उसके पीछे छुपना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को बार-बार उठाने के बजाय माननीय सदन में नियम-130 के तहत इस पर चर्चा करवाई जाए। हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा से दूध का दूध तथा पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बार-बार इस मुद्दे को उठाकर जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है वह राष्ट्रगीत की बात उठाकर उसके पीछे छुपना चाहते हैं। राष्ट्रगान के अपमान के लिए ये द्रोही और दोषी बन गए हैं और अब कहते हैं कि हाईकोर्ट में जाएंगे। किस मुंह से ये हाईकोर्ट में जाएंगे? हाईकोर्ट से बड़ा

26.08.2026/1210/DT/AS-2

तो यह सदन है। ये कहते हैं कि हाईकोर्ट में जाएंगे क्योंकि अपराध कर चुके हैं। देश की जनता ने देख लिया है कि बीजेपी का एजेंडा क्या था। इसलिए इस विषय पर चर्चा क्यों न की जाए?

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे-बाजी करने लगे।)

Speaker : Please take your seats, please. ...(Interruption) Please take your seats, please. ...(Interruption) Please take your seats now. Nothing will go on record except the statement of Hon'ble Revenue Minister. ...(Interruption). Nothing will go on record. No interruptions, please.

राजस्व मंत्री : सर, बीजेपी के साथ यही तो दिक्कत है। ये न संविधान को मानते हैं और न ही विधान सभा के रूल को मानते हैं। जब आपने मुझे परमिट किया है और मुझे बोलने के

लिए कहा है तो मुझे रोकने वाले ये कौन होते हैं? ये रोकने वाले कौन होते हैं? ये अपनी पार्टी का एजेंडा यहां पर चलाना चाहते हैं। ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी वालों से बात सुन नहीं सकते। बीजेपी वालों से बात सुन नहीं सकते।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। ...(Interruption) Please take your seats now please. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भाजपा वाले सच्चाई नहीं सुन सकते। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete. ...(Interruption) Please take your seats. ...(व्यवधान) आपने तो एक नई शुरूआत कर दी है। Please let him reply. ...(Interruption) Please take your seats now. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के ऊपर तो मैं क्योंकि मैं एस0टी0 शेड्यूल कास्ट का हूं, शेड्यूल ट्राइब का हूं और ये जो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं इनके ऊपर एस0टी0 एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी जुबान बंद करना चाहा रहे हैं। ये बीजेपी वाले झूठ बोलने वाले हैं। आपकी पार्टी का नाम ही बहुत ही झूठी पार्टी होना चाहिए।

26.08.2026/1210/DT/AS-3

Speaker : Please, sit down. Nothing is going on record, please. Nothing is going on record except the statement of the Hon'ble Revenue Minister.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कहते हैं कि सदन में लंबा जवाब नहीं होना चाहिए। यह खुद एक प्रश्न पूछने के लिए आठ मिनट एक लेते हैं। आठ मिनट सप्लीमेंटरी में लगाते हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1215/ए.एस.-एन.जी./1

राजस्व मंत्री.......... जारी

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार शोरगुल व नारेबाजी कर रहे हैं।)

ये लोग सप्लीमेंटरी में भी 8 मिनट लगाते हैं, तो हमारा जवाब तो कम-से-कम 20 मिनट का होगा। ये लोग करें तो रामलीला और हम करें तो रासलीला, ऐसा नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

Speaker : Please take your seats. No interruption please. ...(Interruption) No interruption please. Take your seats now. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनकी (विपक्ष के लिए कहा) विचारधारा देश के लिए घातक है। अगर इनकी यही विचारधारा रहेगी, तो संविधान खतरे में आ जाएगा क्योंकि ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। ये लोग सभी लोगों के विरोधी हैं और लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बांटते हैं। ये लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में भी बंटवारा कर रहे हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत नहीं गाया था। आज इनको 80 साल बाद याद आया कि देश में राष्ट्रीय गीत भी है। ये लोग उस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, जोकि देश के लिए घातक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री, आप बोलिए।...(व्यवधान) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats now. Parmar Sahib, please now take your seat. ...(Interruption) Take your seats now. ...(Interruption) Please take your seats now. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : बैठो, बैठो।...(व्यवधान) मुझे बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान)

Speaker : Please take your seats now. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अरे भइया, बैठो तो सही।...(व्यवधान)

26.08.2026/1215/ए.एस.-एन.जी./2

Speaker : Please take your seats now. ...(Interruption) Nothing will go on record you first take your seats, I have not permitted you. ...(Interruption) You will not dictate this, please take your seats. ...(Interruption) Please take yours seats now. ...(Interruption) Nothing is going on record. I will not accept this dictation. ...(Interruption) Please take your seats, nothing is going on record. ...(Interruption) If I given you an opportunity that doesn't mean now you start dictating everything. ...(Interruption) Please take your seats. Let the Hon'ble Chief Minister clarify. Since you have said many thing. ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) Since you have said lot of thing against the Hon'ble Chief Minister so he has a right the right to explain himself. This will not be tolerated. माननीय मुख्य मंत्री, आप आपनी बात रखिए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों को शांत रहना चाहिए।...(व्यवधान) थोड़ा-सा ठंडा पानी पियो। ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सुनो तो सही।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने दो बातें कही। पहले इन्होंने प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कहा। अभी जो आउटसोर्स पर प्रश्न लगा था, उस पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का वीडियो दिखा देना कि इन्होंने कितने मिनट का प्रश्न किया और मैंने क्या रिप्लाई दिया।

दूसरी बात, ये लोग पांच गुटो में बंटे हुए हैं और मुझे जवाब देने के लिए पांचों गुटो को समय देना पड़ता है। श्री बिक्रम सिंह जी को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और डॉ0 जनक राज जी को दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर सदन को मत बांटो। विपक्ष के लोग देश को राष्ट्रीय गान पर भी

26.08.2026/1215/ए.एस.-एन.जी./3

और राष्ट्रीय गीत पर भी बांटने लगे हैं। सवाल क्या है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इस देश में आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित थे और उसमें सभी शब्दों का व सभी स्टैंजों का सम्मान किया जाता है।...(व्यवधान)

Speaker : Please, please, Hon'ble Member Shri Jai Ram Thakurji, you are the Leader of Opposition and such a senior man of this House. Please don't speak while sitting.

मुख्य मंत्री : आप इतने अच्छे क्यों हैं? (श्री जय राम ठाकुर जी के लिए कहा।)...(व्यवधान)

उप- मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तब का मामला है, जब बी0जे0पी0 होती ही नहीं थी। (अपने स्थान से बिना अनुमति के कहा।)...(व्यवधान)

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, हम में से भी बहुत सारे इस दुनिया में नहीं थे। यह सदन भी नहीं था, जब ये सारी चीजें हुई हैं।...(व्यवधान) बैठो, बैठो। (माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह को कहा) तब यह सैंट्रलाइज असेम्बली थी।...(व्यवधान) (माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह अपने स्थान से लगातार कुछ कह रहे हैं।) मुख्य मंत्री जी ने क्या बोलना है और क्या नहीं that is his right and prerogative. ...(व्यवधान) ऐसे से क्या मतलब है?

When I said that there is a Zero Hour, you said that let the Hon'ble Leader of Opposition speak.

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग स्पीकर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। (अपने स्थान से बिना अनुमति के कहा।)

Speaker : If you have to deicide then decide yourself. Hon'ble Chief Minister please continue your statement.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये अपने गुट का अस्तित्व दिखा रहे हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहली बार देखा है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो विपक्ष के 4-5 माननीय सदस्य बोलने लग जाते हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि मुझे किनारे में जाकर पहले ही बता दिया करो कि आज मैंने बोलना है और मैं उस गुट को बोलने का मौका दूंगा। अध्यक्ष महोदय........

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.08.2026/1220/DC/PB/1

मुख्य मंत्री जारी...

ये मुझे पहले ही एक गुट बता दिया करे कि आज हमने बोलना है तो मैं उन्हें बोलने का मौका दे दूंगा।...(व्यवधान)।

अध्यक्ष : ये वही कर रहे हैं जो आप कर रहे थे।...(व्यवधान)।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारी पहचान है। ये देश की और हिन्दुस्तान के हर नागरिक की पहचान है। कोई गीत कानून द्वारा नहीं थोपा जा सकता।

वह भावनाओं से पैदा होता है। जब भावनाओं ने गीत पैदा किए तब यह देश आजाद हुआ। हममें से बहुत से लोग आजादी के समय नहीं थे।...(व्यवधान) हमने भी इस गान को अपनाया। जब हम स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ते थे तब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते थे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि 21 अगस्त को सत्र...(व्यवधान) यदि आप बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। जब आप बीच में टोकते हैं तो आप इस अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उस समय जो वीडियो था, उसपर राजस्व मंत्री जी ने भी बोला था। उस पर आपने कहा था कि राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान पर बात हुई थी। राष्ट्रगान पर सवाल पैदा करना ही इस राष्ट्रगान का अपमान है।...(व्यवधान) मैं इनके खिलाफ भी झूठ बोलने के लिए प्रिविलेज मोशन लाता हूं।...(व्यवधान) हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। जिस तरह हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है उसके बारे में हम हिमाचल प्रदेश के हर कोने में जाकर बोलेंगे कि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। आपको जिस भी कोर्ट में जाना है आप जाइए। आप राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठा रहे हैं कि सुनना पड़ेगा, नारे लगाने पड़ेंगे। यहां नारे लगाने पड़ गए तो वह नारे किस लिए लगाए गए? यहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बांटने की कोशिश की जा रही है। आज इनको (विपक्ष) माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांग लीजिए कि हमने हाथ नहीं खड़ा किया था। आपको हाथ खड़ा करने वाला वीडियो भी दे देंगे।...(व्यवधान) आप हर चीज को राजनीतिक तरीके से करते हैं। आप देश को कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रगान के नाम पर और कभी जाति के नाम पर बांटने का कार्य कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति हमेशा से इंसानियत की और इंसानियत के कद्र की रही है। हम सब लोग उस संस्कृति का

26.08.2026/1220/DC/PB/2

सम्मान करते हैं। हम संविधान की भावना का सम्मान करते हैं। हम संविधान के अनुसार काम करते हैं और हम सब लोग आपके रूल्स और बिजनेस के साथ बंधे पड़े हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं

उस समय मैं मुख्य मंत्री के तौर पर आज तक खड़ा नहीं हुआ हूं। आप इसका एक भी वीडियो क्लिप दिखा दीजिए लेकिन ये मेरे बोलने के समय में खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब क्या करना है? मेरी कोई समस्या नहीं है। समस्या तो इनकी है। हमारी पार्टी की समस्या नहीं है। जैसे-जैसे चुनाव आते जाएंगे, आप पर और दबाव पड़ता जाएगा। इसमें आपका कसूर नहीं है। आपके ग्रुपों पर दबाव पड़ता जाएगा। एक गुट बोलेगा यह करो, दूसरा गुट बोलेगा वह करो। सब अपने-अपने गुट दिखाना चाहेंगे और इस गुटबंदी में ये सब चीजें भूल जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्हें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अगर ये माफी मांगते हैं तो हम इनको माफ कर देंगे, वरना हम हर जगह यह बात उठाएंगे, धन्यवाद।

26.08.2026/1220/DC/PB/3

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल के पांच मिनट शेष है। इसमें पहला नाम माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी का है। I request Hon'ble Member Shri Bikram Singhji to raise his issue under Zero Hour .

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे शून्य काल में अपने विषय पर ही बोलना चाहिए, लेकिन यह बड़े दुःख का विषय है।

अध्यक्ष : आप अपने विषय पर बोलिए अन्यथा शून्य काल का समय समाप्त हो जाएगा।

श्री बिक्रम सिंह : मेरे लिए यह दुःख का विषय है।

Speaker: You have got very important issue under Zero Hour.

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में शून्य काल में पिछली बार भी यह विषय उठाया था कि पिछले वर्ष की बरसात में मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीरसलुही और कूना क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय, आप इस विषय में जानते होंगे क्योंकि यह क्षेत्र आपके विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता है। यहां लगभग पूरी-की-पूरी

लाइन, पीरसलुही से लेकर कूना तक पूरा-का-पूरा पहाड़ फट गया। जिससे वहां काफी लोगों के मकान गिर गए।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1225/डी0सी0/ए0पी0-01

शून्य काल जारी .....

श्री बिक्रम सिंह जारी .....

जो मकान क्षतिग्रस्त हुए है वे कूना पंचायत में श्री जगदीश चंद पुत्र श्री भानी राम, अशोक कुमार पुत्र श्री भानी राम और तिलक राज पुत्र श्री भानी राम तथा पीरसलुई पंचायत में सलीम मोहम्मद पुत्र श्री जफर मोहम्मद, मोहम्मद खलील पुत्र वकील मोहम्मद, मुस्ताक मोहम्मद, रशीद मोहम्मद पुत्र श्री तुफैल मोहम्मद और श्रीमती इंदिरा कुमारी पत्नी श्री कुशल चंद इनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि इनको आपका विशेष राहत पैकेज है, वह पूरा पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन दुःख का विषय है शायद यह घटना माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में न हो। मैंने यहां पर अनुरोध किया था और बोला भी गया था कि इस पूरे केस को हम भेजेंगे और इसके ऊपर इनको सहायता मिलेगी। लेकिन इन्हें एक लाख सत्तर हजार रुपये मिले हैं, जबकि लाखों रुपये का इनका नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि जो एक लाख सत्तर हजार रुपये वैसे दिए जाते हैं, उसके अतिरिक्त जो आपका विशेष पैकेज देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो कृपया करके यदि आप विभाग को कहेंगे तो नई जगह पर वे मकान बना लेंगे, इतनी ही मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमारे ध्यान में यह बात लाई है। अगर आपदा से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी, मैं डी0सी0 को बोलूंगा कि पूरी रिपोर्ट सबमिट करें। अगर उनके मकान बह गए हैं तो हमारी सरकार की जो नीति है। उसके अनुसार हम सात लाख रुपये एक घर बनाने के लिए देते हैं। **अगर उनका पूरा घर डैमेज हुआ होगा तो हम सात लाख रुपये देंगे और अगर आंशिक रूप से डैमेज हुआ होगा तो आंशिक रूप से जो होगा, वह देंगे। जो बिलॉन्गिंग्स घर में होती हैं, अगर वे भी डैमेज हुई होंगी तो वह भी देंगे। इसकी पूरी स्टडी करने के बाद ही हम कार्रवाई करेंगे यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।**

(IRDP सर्वे के नौवें चरण के बारे)

26.08.2026/1225/डी0सी0/ए0पी0-02

अध्यक्ष : अगला विषय माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

श्री जीत राम कटवाल: अध्यक्ष महोदय, आई0आर0डी0पी0 सर्वे का नौवां चरण चला हुआ है। अभी कल-परसों ही चिट्ठी आई है और उसमें यह बोला गया है कि जो इसकी गाइडलाइन्स हैं वे वैसी-की-वैसी ही रहेंगी और उनको मौका दिया गया है। मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी। उसमें यह लिखा था कि हजारों व्यक्तियों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम है और बिलासपुर जिला में ही लगभग सात हजार इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे। चलो धन्यवाद, थोड़ी देर बाद हुआ, पर इनको मौका मिल गया। अगर एक दिन भी किसी ने मनरेगा में काम किया तो वह आई0आर0डी0पी0 में आ सकता है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति हैं जो वाकई गरीब हैं, विधवाएं हैं। मेरे क्षेत्र में अभी तीन केस ऐसे हुए हैं, जिनमें विधवा लड़कियां 25-26 और 27 साल की हैं। उनके पास न मनरेगा है और न कोई ऐसी व्यवस्था है। इस तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं, वे छूट रहे हैं। दूसरी तरफ जो चालाक हैं, ठेकेदार हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक दिन मनरेगा में काम कर लिया। काम तो जैसे-तैसे हुआ होगा, हाजिरी

लगा ली। अब आप इसे अवेयरनेस कह लें या गलत तरीके से एंट्री करने का तरीका कह लें। वे लोग आई0आर0डी0पी0 में अपने को अंकित करवा रहे हैं। जहां तक सर्वे की बात है, जिस पंचायत में पिछले सर्वे में 150 व्यक्ति थे। लेकिन अब जो नया सर्वे हुआ उसमें कही 40 व्यक्ति हैं तो कही 35 व्यक्ति आई0आर0डी0पी0 में हैं और अगर बहुत ज्यादा हों तो कही पर 52-55 व्यक्ति आई0आर0डी0पी0 में हैं। मतलब 33 प्रतिशत लोग ही पात्र पाए जा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय और विभाग से अनुरोध रहेगा कि इन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा जांचें। इस तरह के अचानक मृत्यु वाले केस हैं और नई-नई घटनाएं जो अभी इस अंतराल के बीच में हुई हैं, उनके केस अब हमारे पास आते हैं कि हमें आई0आर0डी0पी0 में नहीं लिया जा रहा है। इसके बारे में गौर करें और इसको तर्कसंगत बनाने के लिए जो वास्तविक तरीके से पात्र हैं, उनको शामिल करने के लिए गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन में बदलाव करें, धन्यवाद।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.08.2026/1230/AT/HK/01

ग्रामीण विकास एवं **पंचायती राज मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा कि बी0पी0एल0 का जो सर्वे हुआ है, वह मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत हो रहा है। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बी0पी0एल0 की जो पहली लिस्ट है, उसमें जो लोग हैं, उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में अति निर्धन लोगों जो हैं हम सभी जनप्रतिनिधियों के पास शिकायतें आती हैं कि कुछ प्रधानगण, सभी नहीं, लेकिन कुछ प्रधान अपनी मनमानी करते हैं और पात्र व्यक्ति को इसमें आने नहीं देते हैं तथा वोटों की राजनीति करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले बी0डी0ओ0 और एस0डी0एम0 की कमेटी

बनाई है। अभी पंचायत प्रधान या पंचायत सेक्रेटरी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह डिसाइड करे या जनरल हाउस डिसाइड करे कि कौन इसमें रहेगा। इसके लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की लिस्ट बनाई गई है।

हमारे विभाग के पास भी काफी शिकायतें आई हैं कि अभी कुछ लोग रह गए हैं। कुछ लोग इनकम सर्टिफिकेट के कारण रह गए हैं, क्योंकि उनके इनकम सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाए और एक दिन के मनरेगा के काम को लेकर भी आप कह रहे हैं। इसलिए हमने नाइन्थ फेज लॉन्च किया है, जो 20 सितंबर तक चलेगा।

पिछले कल ही मैंने सभी बी0डी0ओ0 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्लियरिटी दी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन का काम अनिवार्य है तो आपको मनरेगा में एक दिन का काम करना ही पड़ेगा तभी आप इसके पात्र होंगे। इसमें जो इंक्लूजन लिस्ट है उसमें 75,000 रुपये की इनकम रखी गई है। जिसकी इनकम 75,000 रुपये से कम है चाहे उसने मनरेगा में काम किया हो या नहीं किया हो, वह पात्र हो सकता है।

26.08.2026/1230/AT/HK/02

इसमें सात पॉइंट इंक्लूजन के हैं और पांच पॉइंट एक्सक्लूजन के हैं। एक्सक्लूजन की कॉपियाँ सदन के बाद आपको भी दे रहा हूं। पांच पॉइंट में यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में है तो उसका चयन नहीं होगा। इसी तरह, जिसकी इनकम 75,000 रुपये से अधिक है वह पात्र नहीं होगा। मैं लंच टाइम के बाद, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की कॉपियाँ सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। कल भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई अपात्र व्यक्ति या सिफारिशी व्यक्ति अगर इसमें लिया गया तो हम बी0डी0ओ0 और एस0डी0एम0 के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। डी0सी0 यानी डिप्टी कमिश्नर्स को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कई शिकायतें मुझे यह भी मिली हैं कि इनकम सर्टिफिकेट समय पर नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कुछ तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। इसलिए सभी डी0सी0 को हमने पिछले कल ही शाम को चिट्ठी ड्राफ्ट कर दी थी, जो आज सुबह हमारे डायरेक्टोरेट से चली गई होगी। उनको यह निर्देश दिए गए हैं कि आप भी वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एस0डी0एम0 और बी0डी0ओ0 से इसकी जानकारी लें कि कितने पात्र व्यक्ति हैं और 20 तारीख तक हम कितने पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल कर सकते हैं। यह मैं पूरी सदन को बताना चाहूंगा।

शून्य काल समाप्त।

26.08.2026/1230/AT/HK/02

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीयूसी-ए03/4/2023-ईडीयू-सी(152585), दिनांक द्वारा 11.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.06.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

26.08.2026/1230/AT/HK/03

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का **165वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **96वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;

2. समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **202वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **मत्स्य पालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

3. समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के **260वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है।

26.08.2026/1230/AT/HK/04

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का **36वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) पर बने समिति के **53वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1235/av/hk/1

सदन की समितियों के प्रतिवेदन जारी---

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति (वर्ष 2026-27), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति (वर्ष 2026-27) का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2026-27), समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2026-27) के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

(1) समिति का 36वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
(2) समिति का 37वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

26.08.2026/1235/av/hk/2

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2026-27), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति (वर्ष 2026-27) का 21वां मूल प्रतिवेदन जोकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2026-27), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2026-27) का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि उद्यान विभाग के कार्यों/गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

26.08.2026/1235/av/hk/3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। पहला प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राम कुमार का है जोकि अनुपस्थित हैं और अगला प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल का है। इसलिए अब श्री राकेश जम्वाल जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय लोक निर्माण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल, यदि आप चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भूस्खलन के कारण तत्तापानी-सलापड़ मार्ग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्गम क्षेत्र तत्तापानी से सलापड़ सड़क के लिए वर्ष 2018 में भारत सरकार से सी0आर0एफ0 के तहत 219.43 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। उसका निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है और यह सड़क डबल लेन बन रही है। यह सड़क तत्तापानी से करला तक पहले से बनी हुई थी और इस पर शिमला से करला और सुन्दरनगर से करला बसिज भी चलती हैं। भूस्खलन के कारण बालीकैंची के पास यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज लगभग 4 महीने हो चुके हैं लेकिन उस सड़क का कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरे उस क्षेत्र की धनयारा, हाड़ाबोई और सौजा पंचायतों के हजारों लोग उस सड़क के कारण प्रभावित हो रहे हैं। वहां से बच्चे कॉलेज और आई0टी0आई0 निहरी या सुन्नी जाते हैं। मगर जहां पर यह सड़क भूस्खलन के कारण

प्रभावित हुई है, वहां पर बच्चों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और निजी गाड़ी वाले जहां यह सड़क टूटी है, लोगों को आधे रास्ते तक मनमाने दाम पर लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। मैंने इस सड़क के बारे में लोक निर्माण विभाग को व्यक्तिगत तौर पर भी कहा और उस क्षेत्र के डेपूटेशन्ज भी लोक निर्माण विभाग और एस0डी0एम0 से मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक उस सड़क को बहाल नहीं किया गया है।

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1240/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
श्री राकेश जम्वाल. जारी

इस सड़क के लिए भारत सरकार द्वारा सी0आर0एफ0 के अंतर्गत 219.43 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह राशि हमारी उक्त सड़क के लिए प्रदान की है लेकिन इसके बावजूद सड़क बहाल नहीं हो रही है जबकि एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस भी प्राप्त हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र-से-शीघ्र आदेश देकर इस सड़क को बहाल करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक पी0आई0एल0 हाईकोर्ट में हुई थी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईकोर्ट में जो जवाब दिया गया है उसमें हमारी एक वैकल्पिक सड़क चुनीकर से हाढ़ाबोई तक है जिसको हम बटाड़ी से कमैल भी कहते हैं। यह सड़क लगभग सवा तीन किलोमीटर लंबी है। इस सड़क की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग और एच0आर0टी0सी0 विभाग ने दे दी है तथा इस मार्ग को बस चलाने के लिए पास कर दिया गया है। इस पर भी बस चलनी चाहिए थी। उप-मुख्य मंत्री जी यहां माननीय सदन में उपस्थित हैं। दिनांक 28 जुलाई, 2026 को इस सड़क को पास करके विभाग द्वारा हाईकोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट दे दी है लेकिन यह सड़क अभी भी अवरुद्ध है। इस वैकल्पिक मार्ग पर जो बस सुंदरनगर से करला आती है और शिमला से करला जाती है उसे चलाया जाए। मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए यदि कोई उद्घाटन अथवा

औपचारिकता आवश्यक हो तो आप शिमला से ही हरी झंडी दिखा कर आदेश दे दें ताकि यह बस चल पड़े तथा मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे या तो निहरी आना पड़ता है या सुन्नी जाना पड़ता है अथवा तत्तापानी जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से भी निवेदन है कि भूस्खलन के कारण जो सड़क अवरुद्ध हुई है उसे शीघ्र-से-शीघ्र ठीक करवाया जाए। अभी स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर अपनी जे0सी0बी0 मशीन लगाकर छोटी गाड़ियों के लिए वहां से

26.08.2026/1240/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

निकलने की व्यवस्था की है। मुझे इसकी जानकारी पिछले कल वहां से आए बी0डी0सी0 सदस्य और प्रधान ने दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर जीपेबल कार निकालने की कुछ व्यवस्था की है लेकिन इसमें कोई हादसा न हो जाए इसकी आशंका बनी हुई है। इसलिए लोक निर्माण विभाग इस सड़क को ठीक प्रकार से ठीक करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं उप-मुख्य मंत्री जी से भी आश्वासन चाहता हूं कि जिस सड़क को आपके विभाग ने पास किया है उस पर बस चला दी जाए। लोक निर्माण विभाग और एच0आर0टी0सी0 का जॉइंट इंस्पेक्शन भी हो चुका है। बस चलाने के संबंध में इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी दे दी गई है। मेरा निवेदन है कि औपचारिकता न करते हुए यदि आवश्यक हो तो आप यहीं से आदेश दें ताकि बस चल पड़े और मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2026/1240/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री राकेश जम्वाल जी ने नियम 62 के अंतर्गत तत्तापानी-सलापड़ मार्ग के लगभग पांच माह से भूस्खलन के कारण बंद होने से उत्पन्न गंभीर जन-समस्या से इस सदन को अवगत करवाया है। मैं इसमें सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि यह कार्य सी0आर0एफ0 के तहत हो रहा है और इन्होंने कहा है कि यह विशेष राशि हमें दी गई है। सबसे पहले मैं इस पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सी0आर0एफ0 में प्रदेश को जो पैसा मिलता है वह पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले सैस के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश को दिया जाता है। इसलिए यह कोई सौगात नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। हमारे प्रदेश में जितना कंजम्प्शन हो रहा है उसके एवज में यह पैसा प्रदेश को मिलता है और मिला है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन this is not a Sogaat. This is the right of the people of Himachal Pradesh and we have been able to secure these funds from the Central Government.

दूसरी बात यह है कि इस सड़क को पूरा करवाना हमारी वचनबद्धता है और सरकार की भी वचनबद्धता है। सलापड़-तत्तापानी सड़क की कुल लंबाई 61 किलोमीटर 600 मीटर है। जैसा मैंने कहा कि इसका कार्य सी0आर0एफ0 के अंतर्गत करवाया जा रहा है। किलोमीटर 0 से 17 गांव ऐन तक सड़क बस योग्य है तथा इस भाग में नियमित रूप से बस सेवा चल रही है। किलोमीटर 17 ऐन से 31 नेरी तक सड़क का भाग वर्तमान में बस योग्य नहीं है। इस भाग में निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारी वर्षा के कारण हो रहे भूस्खलन जो आपका लैंडस्लाइड तथा निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण इस भाग में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही वर्तमान में बंद है। इस भाग के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा आगामी 15 दिनों में छोटे वाहनों के लिए इसे खोलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही किलोमीटर 31 से 61 तक यानी नेरी से आगे तत्तापानी तक सड़क के जिस भाग से मेरे विधान सभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण का संपर्क जुड़ता है उसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

26-8-2026/1245/NS-YK/1

लोक निर्माण मंत्री ------जारी

सड़क का उक्त भाग बस योग्य पास है। इस भाग पर दिनांक 9 अप्रैल, 2026 तक बसों सहित अन्य यातायात नियमित रूप से सुचारू चल रहा है परन्तु कोल डैम की झील में अत्यधिक जल प्रभाव के कारण दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पहाड़ी का एक हिस्सा धंस गया है जिस कारण उक्त सड़क का भाग 52 किलोमीटर से 53 किलोमीटर तक गांव बली तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य भू-विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस भाग में अब किसी भी प्रकार का पुनर्बहाली अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हम इसमें ऑल्टरनेट रोड बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैं स्वयं एक दिन वहां से गुजरा था और पूरे-का-पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड होकर नीचे की ओर आ रहा है including the road. वहां तीन-चार हेयरपिन बैंडज यानी कैंचियां हैं। **इसलिए हम आने वाले समय में वहां ऑल्टरनेट रोड बनाने का प्रयास करेंगे।** मुख्य सड़क के एक क्षतिग्रस्त भाग के कारण विभाग द्वारा बटाली-कमेल वैकल्पिक सड़क आर0डी0 0-3200 को बहाल किया गया है। दिनांक 28 जुलाई, 2026 को संयुक्त फिटनेस समिति द्वारा उक्त सड़क को बड़े वाहनों एवं बसों के आवागमन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। वर्तमान में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन इसी वैकल्पिक मार्ग अर्थात ऑल्टरनेट रूट से करवाया जा रहा है। इस वैकल्पिक मार्ग के कारण आम जनता को लगभग पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। मैं मानता हूं कि यह मार्ग थोड़ा लंबा है but as soon as possible we will try to restore the original road. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और उनको स्वयं भी इसकी जानकारी है कि तीन हिस्सों में अर्थात तीन पैकेजिज में यह काम हुआ है। हमें अंतिम एफ0सी0ए0 अभी कुछ ही समय पहले मिली है। वहां कटिंग का कार्य चला हुआ है और कटिंग की वजह से बीच-बीच में रोड भी बंद हो जाता है। इसमें जो हेयरपिन बैंड है तो उससे यह रोड लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और वहां आवाजाही बंद हो गई थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा एक नई वैकल्पिक सड़क का सर्वे भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में एफ0आर0ए0 प्रकरण आगामी संयुक्त निरीक्षण हेतु वन मंडलाधिकारी, सुकेत के कार्यालय में प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क द्वारा मुख्य सड़क के क्षतिग्रस्त भाग को बाइपास किया जाएगा।

26-8-2026/1245/NS-YK/2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय श्री राकेश जम्वाल जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सड़क हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण, रामपुर, आनी और किन्नौर तक के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। आने वाले समय में जब यह सड़क पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगी तो शिमला जिले के सतलुज वैली वाले पूरे हिस्से को यह एक शॉर्टकट उपलब्ध करवाएगी जो नीचे एम्स, बिलासपुर, सलापड़ और आगे पंजाब तथा चंडीगढ़ के लिए भी उपयोगी होगी। This is a matter of prime importance for the Government of Himachal Pradesh, for the PWD Department and we will try an expedite this work as soon as possible, ताकि आने वाले समय में इसे पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि हमने इसके लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है और हम इसे पी0एम0 गति शक्ति योजना के तहत भी लाना चाह रहे हैं। हम इसे सलापड़ से लेकर लूहरी तक करना चाह रहे हैं क्योंकि अब केंद्र सरकार द्वारा नए एन0एच0 घोषित नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए इसे ऑल्टरनेट रूप से पी0एम0 गति शक्ति योजना के तहत डाला जाएगा ताकि यह सड़क strategically also, not only from the orchardists point of view or from the industrial point of view, but also from the strategic point of view, because this road leads further to Kinnaur जो चीन के साथ लगता हमारा बॉर्डर है वहां तक हो जाए। इसलिए from strategic point of view also this road is very important for us. हम इसे उस दृष्टि से भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे और जहां पर भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसके बारे में चीफ इंजीनियर व एस0ई0, मण्डी से बात करूंगा और इसे शीघ्र पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। Thank you very much.

अध्यक्ष : माननीय राकेश जम्वाल जी मंत्री जी ने सारा तो बता दिया, अब आप क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं?

श्री राकेश जम्वाल------आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

26.08.2026/1250/RKS/Aजी-1

श्री राकेश जम्वालः मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और श्री जय राम ठाकुर मुख्य मंत्री बने। उसके लगभग 15 दिनों के भीतर मैं मुख्य मंत्री जी के साथ दिल्ली गया तथा केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिला। इस सड़क के विषय में वहां विस्तृत चर्चा हुई क्योंकि इसकी PIL हुई थी और इसे एन0एच0 घोषित किया जा रहा था क्योंकि 219 करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ा अमाउंट है जो किसी एक विधान सभा क्षेत्र की सड़क के लिए स्वीकृत की जा रही थी। जब मैं अपने सांसद स्वर्गीय श्री रामस्वरूप शर्मा और मुख्य मंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री जी से मिला तब मैंने मुख्य मंत्री जी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। यह केवल एक विधान सभा क्षेत्र की सड़क नहीं है बल्कि ततापानी और सुन्नी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार इसका उल्लेख किया तो माननीय मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह सड़क सौगात है। एक सड़क के लिए भारत सरकार से 219 करोड़ रुपये स्वीकृति करवाना बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, श्री नितिन गडकरी और श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कार्य में मेरा भी प्रयास रहा है। ...(व्यवधान) आप बाद में मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है वह स्वाभाविक रूप से विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई होगी। मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं और वहां निरंतर दौरा करता रहता हूं। आपने वैकल्पिक मार्ग की बात कही और यह भी कहा कि एग्जिस्टिंग सड़क को ठीक नहीं किया जा सकता। आपने यह भी कहा कि इसे छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कल स्थानीय लोगों ने स्वयं उस सड़क को खोल दिया है जबकि विभाग द्वारा वहां कोई कार्य नहीं किया गया था। हमारे स्थानीय लोगों ने उस सड़क को खोल दिया है। आपने जो वैकल्पिक सड़क का जिक्र किया है उसके संबंध में माननीय उप-मुख्य मंत्री जी

को बताना चाहता हूं कि जो वह मार्ग लंबा है जिसके कारण किराया भी अधिक लगेगा लेकिन फिर भी लोगों को सुविधा तो मिलेगी। उस क्षेत्र की तीन पंचायतों में न कोई बाजार है और न ही कोई हॉस्पिटल है। लोगों को मूलभूत चीजों के लिए निहरी जाना पड़ता है या फिर तत्तापानी जाना पड़ता है। इसलिए जब सड़क की फिटनेस हो गई,

26.08.2026/1250/RKS/Aजी-2

वहां पर संयुक्त निरीक्षण हो गया, बस का संचालन स्वीकृत हो गया तो एक माह बीत जाने के बाद भी उस मार्ग पर बस सेवा क्यों प्रारम्भ नहीं हुई है? माननीय उप-मुख्य मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए आदेश जारी करें ताकि उस मार्ग पर बस सेवा शीघ्र शुरु हो सके। मेरा दूसरा निवेदन माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से है। करला-दोघरी क्षेत्र से कोल डैम होते हुए जो सड़क जाती है वह पहले छोटी गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुली रहती थी। करला से सलापड़ जाने वाले लोग उसी मार्ग का उपयोग करते थे। अब लोक निर्माण विभाग द्वारा टैंडर आवंटित किए जाने के बाद कांट्रैक्टर तथा विभाग ने वहां छोटी गाड़ियों की आवाजाही भी बंद कर दी है। अगर उस क्षेत्र के लोगों को सुन्दरनगर जाना होता है तो उस रूट से वे एक-डेढ़ घंटे में सुन्दरनगर पहुंच जाते हैं। मेरा निवेदन है कि दिन के समय 10 बजे से सायं 5 बजे तक कटिंग कार्य के लिए उस सड़क को बंद रखा जाए लेकिन सुबह-शाम के समय छोटी गाड़ियों की आवाजाही के लिए उस सड़क को खोल दिया जाए। विशेषतौर पर मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इस तरह के जनहित के कार्य के लिए आदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मेरे क्षेत्र के हजारों लोग इस वजह से काफी परेशान हैं। जैसा मैंने कहा कि बटारी-कमैहल मार्ग की फिटनेस हो चुकी है, उस पर बस सेवा शीघ्र प्रारम्भ करवाई जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय लोक निर्माण मंत्री महोदय से संबंधित है लेकिन आपने अपनी मर्जी से इसमें और विषय भी जोड़ दिए हैं जिसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता। This is very specific. When you have raised an issue under Rule 62, that is very specific, and only the Minister concerned was informed about this issue. The

other Hon'ble Minister was not informed about the issue. When you start seeking everything without the permission of the Chair, I cannot allow that. Only the PWD Minister will reply to this proposition/clarification. ...(Interruption) He is travelling beyond the pleadings, he cannot.

26.08.2026/1250/RKS/Aजी-3

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर तथ्य बता रहा हूं कि इसकी हेयरपिन बेंड की वजह से समस्या आ रही है। ....(व्यवधान) जैसा मुझे विभाग ने भी बताया और मैं सही तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि वैकल्पिक मार्ग लगभग 5 किलोमीटर अतिरिक्त पड़ता है किंतु वह सड़क ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। जहां तक बस सेवा का प्रश्न है क्योंकि यह एक वैकल्पिक सड़क है और इसमें बस तभी चलेगी जब उसकी पासिंग होगी। ...(व्यवधान) मैंने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। हमें इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह विभाग द्वारा तैयार किया गया एक टैम्परेरी सोल्यूशन है ।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1255/बी.एस./ए.जी.-1

Public Works Minister Continues. . .

अगर उस रूट पर अंतरिम अवधि के लिए बस पासिंग की अनुमति हुई है तो निश्चित तौर पर हम इस मामले को कंसर्न्ड डिपार्टमैंट के साथ और उप-मुख्य मंत्री जी के साथ टेक अप करेंगे। We will try that bus should ply from that route till time the main road is not opened for traffic. That is No. 1.

दूसरा, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आपके भावना हो सकती है कि आपको यह सौगात मिली है। यह अच्छी बात है। मगर मैं फिर से इस बात को रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि केंद्र से सी0आर0एफ0 के तहत हिमाचल प्रदेश को जो भी पैसा मिलता है

उसमें हम भी अपने वर्तमान कार्यकाल में करोड़ों रुपये लेकर आए हैं। मगर पेट्रोल और डीजल का सेस जो हमारे राज्य से लिया जाता है उसके एवज में हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों को यह राशि दी जाती है। इसलिए यह हमारा अधिकार है। यह हिमाचल के 75 लाख लोगों का अधिकार है।

अब उस अधिकार को अगर कोई सौगात के रूप में देखना चाहता है । That is their interpretation, but I am only stating the facts. We will continue to raise the voice of the people of Himachal Pradesh. I am happy to state that we have continuously raised the issues of road construction with the Central Government. We have secured almost Rs. 7,500/- crores in the last three years under the leadership of the Hon'ble Chief Minister. That is our right. That is the right of the State Government. We have been proactively making DPRs. We have been proactively taking up the issues of Himachal Pradesh and we will continue to do so and raise the voice of the people of Himachal Pradesh. We will ensure that regional connectivity and remote connectivity in the farthest areas and unconnected habitations of the State is done. That is our responsibility. We will continue to do so. यह बात मैं आदरणीय विधायक जी को कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : Shri Rakesh Jamwal, only clarification to the PWD.

25.08.2026/1255/बी.एस./ए.जी.-2

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि नियम- 62 में मैंने स्पैसिफिक विषय रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं यहां पर कोई भाषण के लिए इस विषय को लेकर नहीं आया हूं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस समस्या का समाधान हो। इसीलिए यह ज्वलंत मुद्दा है और नियम- 62 का मतलब यही है कि यह ज्वलंत मुद्दा है, मेरे क्षेत्र के हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। सड़क बंद पड़ी है और अगर रिप्लाई चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री दें चाहे उप-मुख्य मंत्री जी दें लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता जो प्रभावित हो रही है मैं

चाहता हूं कि समस्या का समाधान हो जाए। इसीलिए मैंने सदन में यह विषय उठाया है ना कि यहां कोई भाषण के लिए। आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप एलाऊ करेंगे क्योंकि आप बड़े दिल के साथ एलाऊ करेंगे तो इस समस्या का मेरे क्षेत्र में समाधान हो जाएगा। उप-मुख्य मंत्री जी इसमें मुझे आश्वासन दे सकते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे नहीं पता कि माननीय उप-मुख्य मंत्री तैयार हैं या नहीं हैं।। will request the Hon'ble Deputy Chief Minister, in any case, if he wants to intervene, definitely he can.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बस का मसला यहां पर रखा है उसमें अगर पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री हमें यह क्लियरेंस दे देंगे कि यहां बस चल सकती है या नहीं, क्योंकि यह ऑल्टरनेट रूट इन्होंने यहां पर मुझे दिखाया है और मेन रूट तो शायद बंद है। अगर ऑल्टरनेट रूट पर पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री हमें कह देंगे कि यहां बस चल सकती है तो हम इनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक बस शुरू करवा देंगे।

लेकिन लोगों के जीवन का सवाल है और पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री ने सिर्फ यह कहा है कि वहां छोटी गाड़ी चल सकती है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां बस चलानी है इसलिए इसको एग्जामिन करके अगर बस चल सकती है तो निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Speaker: Hon'ble Deputy Chief Minister will be examining this. This is what he has said.

25.08.2026/1255/बी.एस./ए.जी.-3

उप-मुख्य मंत्री : अगर रोड फिटनेस का दस्तावेज हमारे पास आ जाएगा उसको देखकर हम बस चलाएंगे। लेकिन एक बार पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री हमें यह तो कह दे कि आप बस चला सकते हैं।

Speaker: Now, the House adjourned for the lunchbreak. We will reassemble at 2 o'clock.

26.08.2026/1405/DT/AS-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02:05 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। यह विषय 24 अगस्त से चर्चा में है। अभी तक मेरे पास दोनों दलों की ओर से नौ माननीय सदस्यों के नाम आए हैं। यहां से पांच और वहां से चार माननीय सदस्यों के नाम आए हैं। लगभग पांच घंटे दस मिनट इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आगे भी बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं और अभी कुछ महत्वपूर्ण इश्यू लिस्ट होने को हैं इसलिए आप कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक बात कहने का प्रयास करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस की तरफ से लास्ट स्पीकर श्री चंद्र शेखर जी थे। अब मेरे पास जो रिवाइज्ड लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है उसमें श्री त्रिलोक जम्वाल नंबर एक पर हैं। माननीय सदस्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आपको जहां कमियां नजर आ रही हैं, पोलिसी में कहीं एनोमलिज हैं उन्हें आप without any political aspersion अंकित करें।

श्री त्रिलोक जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम- 130 के तहत माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी जो हैल्थ के ऊपर चर्चा लाए हैं, इस चर्चा में मैं भी अपने आप को सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष जी, हैल्थ डिपार्टमेंट प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है । यही कारण है कि इस विषय पर हर सत्र में चर्चा होती है और अब भी यह चर्चा चल रही है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब हाउस के अंदर हम चर्चा में पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार का जवाब सुनते हैं तो ये

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1410/ए.एस.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल.......... जारी

लगता है कि प्रदेश में इससे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो सकतीं। प्रदेश में क्या, पूरे देश में भी नहीं हो सकतीं। कई बार तो जब सरकार की ओर से वक्तव्य आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे विकसित देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, वैसे हमारे हाउस के अंदर उसकी कल्पना कर दी जाती है। लेकिन हम लोग वास्तविकता और यथार्थ से कितने दूर हैं, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। कई बार जब वक्तव्य आते हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पब्लिक के ऐसे-ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं, जब अखबारों में खबरें छपती हैं, जब लोग घेराव करते हैं, तब समझ आता है कि हम अपने हिमाचलवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर रोबोटिक सर्जरी की बात हुई। यह बहुत अच्छी बात है और रोबोटिक सर्जरी होनी भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में डवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश की ओ0पी0डी0 कितनी है और उस ओ0पी0डी0 के अनुपात में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या कितनी है? हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ कितना है? हमारे स्वास्थ्य संस्थानों के हालात क्या हैं? उनके ऊपर भी एक नजर दौड़ानी चाहिए। कई जगह तो इतनी बुरे हालात हैं कि आप हेल्थ सब-सेंटर या पी0एच0सी0 के अंदर जाने से पहले भी दो बार सोचेंगे। लेकिन हाउस के अंदर जब चर्चा होती है, तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, कल यहां विषय आया था और उस विषय में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारा आई0जी0एम0सी0 व चमियाना, AIIMS बिलासपुर से भी अच्छे स्वास्थ्य संस्थान हैं और हम उनसे अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं

26.08.2026/1410/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अभी चंद दिन पहले हमारे सांसद (राज्यसभा) को CTO प्वाइंट पर हार्ट में कोई दिक्कत हुई या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई। वे आई0जी0एम0सी0 में उपचार के लिए गए तो वहां की लिफ्ट नहीं चल रही थी। उनको स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ा। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भी वहां पर मौजूद थे और ये भी स्ट्रेचर को उठाने लगे थे। दूसरे या तीसरे फ्लोर में जाने के लिए जिस हॉस्पिटल की लिफ्ट नहीं चलती, उसमें ऐसा कौन-सा व्यवस्था परिवर्तन हो गया कि उसे एम्ज़ से बेहतर हॉस्पिटल कह रहे हैं? यदि सांसद का यह हाल है तो आमजन का क्या होगा?...(व्यवधान) उसके उपरांत, अध्यक्ष जी, दिनांक 21 फरवरी, 2026 को चमियाना की...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, चमियाणा, जिसको कहा कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहां पर जाने के लिए सड़क नहीं है। चार सालों में लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार लैंड एक्वायर कर पाती तो हमारी गाड़ी ठीक ढंग से नीचे तक चली जाती। दिनांक 21 फरवरी, 2026 को इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा अमानवीय कार्य क्या हो सकता है, जब एक कुत्ता एक व्यक्ति की, जिसकी टांग कटी थी, उसको लेकर हॉस्पिटल के परिसर में घूम रहा था? क्या यह हमारी विश्वस्तरीय व्यवस्था है? क्या यह स्वास्थ्य संस्थान AIIMS से अच्छा है? बाद में उस घटना के ऊपर स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग ने एक कमेटी कंस्टीट्यूट कर दी। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? किसको दिलासा दे रहे हैं? क्यों हाउस के अंदर झूठ बोल रहे हैं? जहां सुधार करना चाहिए, वहां सुधार होना भी चाहिए।

26.08.2026/1410/ए.एस.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल का कांगड़ा का वीडियो ही देख लीजिए। वहां पर एक व्यक्ति हिमकेयर कार्ड न चलने के कारण और उसके पास पैसे न होने के कारण बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देता है। पूरे सोशल मीडिया में वह वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं तो इतनी अच्छी हैं कि इनकी तुलना विश्व-स्तरीय सुविधाओं से भी नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, कल हमारे मित्र श्री आर0एस0 बाली जी कह रहे थे और रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे थे। ये स्वयं कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा ओ0पी0डी0 है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि 6 लाख की ओ0पी0डी0 में से अगर 341 ऑपरेशन रोबोट के माध्यम से हुए हैं तो वे जरूर होने चाहिएं। लेकिन 6 लाख लोग अगर स्वास्थ्य सुविधाएं लेने आते हैं तो उन सबको रोबोटिक सर्जरी नहीं चाहिए। उनको तो मूलभूत सुविधाएं चाहिएं। उसको कौन प्रोवाइड करेगा? उसके बारे में चिंता कौन करेगा?

अध्यक्ष महोदय, हमारे दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में शुगर-बी0पी0 जैसी दवाइयां 3rd ग्रेड हैं और डॉक्टर कहता है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.08.2026/1415/DC/PB/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

कि दवाई अंदर से न लें बल्कि बाहर से लें तभी फर्क पड़ेगा। लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है। हम किसे दिलासा दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जोनल अस्पताल बिलासपुर की बात करता हूं। इस जोनल अस्पताल में एक भी डेड बॉडी वैन नहीं है। अस्पताल में केवल एक एम्बुलैंस है और वह भी वी0आई0पी0 ड्यूटी के लिए है। जिस अस्पताल की ओ0पी0डी0 800 से ऊपर हो उस अस्पताल में अगर एक ही एम्बुलैंस हो और वह भी वी0आई0पी ड्यूटी में हो तो हम क्या करेंगे?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चार वर्षों से केवल सैंक्शन ही हो रही है। पूरे जिला बिलासपुर में रेडियोग्राफी के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है और पूरे जिला में हमारे पास एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? एक एक्स-रे टेक्नीशियन तक नहीं है और ये यहां बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मेरे जोनल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट पिछले छह महीनों से खराब पड़ा है। हम प्राइवेट वेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं लेकिन क्यों और किसके कहने पर और किसे फायदा देने के लिए ले रहे हैं? पिछले छह महीनों से ऑक्सीजन प्लांट ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अस्पताल की लिफ्ट पिछले छह महीनों से खराब है। इस मामले में हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और हिमाचल प्रदेश में कितनी जगहों पर लिफ्टें खराब हैं इस बारे में भी ऑर्डर किया। उसके बाद इसके लिए कुछ पैसे सैंक्शन हुए हैं। जिस हॉस्पिटल में छह महीने से लिफ्ट नहीं चलती हो उस हॉस्पिटल का क्या हाल होगा?

अध्यक्ष महोदय, आज डायलिसिस की हर चौथे आदमी को जरूरत है लेकिन मेरे जोनल हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं होता है। हमारे यहां एक हंस संस्था है जो यह सुविधा देती है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा नहीं है। हम हंस संस्था के माध्यम से डायलिसिस करवाते हैं और उस संस्था ने पूरे वर्ष में केवल 61 लोगों का ही डायलिसिस किया है।

26.08.2026/1415/DC/PB/2

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों हॉस्पिटल गया था और वहां के कुछ डॉक्टर्ज से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि मूलभूत सुविधाओं में क्या दिक्कतें आ रही है। उन्होंने मुझे बताया कि बी0पी0 नापने की मशीन वर्ष 2000-01 में ली हुई है। अब आप समझिए कि जिस हॉस्पिटल में बी0पी0 नापने की मशीन तक उचित स्थिति में न हो और डॉक्टर्ज को मूलभूत व छोटी-छोटी दिक्कतें आ रही हों उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी?

अध्यक्ष महोदय, मेरे जोनल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के जितने भी केस आते हैं उनमें से 80 प्रतिशत एम्स के लिए रेफर होते हैं। मेरा जोनल हॉस्पिटल केवल रेफरल यूनिट बनकर रह गया है। प्रदेश सरकार बड़े-बड़े दावे करती है। अध्यक्ष महोदय, आप सोचिए कि मेमोग्राफी की मशीन आए हुए दो वर्ष हो गए हैं लेकिन प्रिंटर नहीं है।..(व्यवधान) आप टर्मिनोलोजी देख लीजिए। मेमोग्राफी कैंसर के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर की जांच हेतु महत्वपूर्ण है। यह इतना बड़ा मामला है और प्रदेश सरकार एक प्रिंटर तक नहीं दे पा रही है। सरकार कहती है कि हम अस्पतालों में रोबोट लाए हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मरीज ओ0पी0डी0 में आएगा क्या उसे रोबोट अपने आप ठीक कर देगा? हमारे पास कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर के जोनल हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि कुछ दिन पहले जब बारिश हुई तो ऊपर की मंजिल से मरीज हटाने पड़े क्योंकि उसकी सारी छत टपक रही थी। यह जोनल हॉस्पिटल की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, दावे तो बड़े-बड़े हो रहे हैं। सहारा योजना के तहत जून, 2025 से 3300 मरीजों में से किसी भी मरीज को एक भी रुपया नहीं मिला है। क्यों आज तक एक पैसा नहीं मिला? ये कैसी सुविधाएं हैं?

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे विधान सभा के पंजगाईं क्षेत्र में गए थे। वहां सी0एच0सी0 तो थी लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं था। मैंने पिछली बार भी सदन में यह मामला उठाया था तब जाकर इस सी0एच0सी0 को एक डॉक्टर मिला। वह डॉक्टर भी कब आता है और कब नहीं आता है, मैं यह इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वह

महिला है इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सी0एच0सी0 तो है लेकिन बरमाणा में आपने पी0एच0सी0 बंद कर दी है। इस

26.08.2026/1415/DC/PB/3

सी0एच0सी0 में तीन डॉक्टरों की जगह केवल एक डॉक्टर है। जब इसे बनाने की बात आई तो इसके लिए वर्ष 2021-22 से 3.66 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है लेकिन आज तक सरकार इसका टेंडर नहीं कर पाई है। आपने पंजगाईं और कुठेड़ा सी0एच0सी0 का पैसा डाइवर्ट किया। आप हॉस्पिटल नहीं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1420/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी .....

आप इन सी0एस0सी0 को, चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी0एस0सी0 पंजगाईं हो या सी0एस0सी0 कुठेड़ा हो आप इन दोनों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे हरलॉग में सी0एस0सी0 हैं लेकिन उनमें भी डॉक्टर नहीं हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है। कसोल में भी 90 प्रतिशत पी0एच0सी0 का काम कम्प्लीट हो चुका है लेकिन पिछले चार सालों से उसके आगे एक ईंट भी नहीं लगी है। क्या कसोल में लोग नहीं रहते? क्या मसौर में लोग नहीं रहते? सरकार ही अगर इन कामों को कम्प्लीट न कर सके तो आप ही बताए की इनमें लोग इलाज के लिए कैसे जाएंगे? पी0एच0सी0 हरलॉग, पी0एच0सी0 बरमाणा और सब सेंटर जबल्याणा की भी यही स्थिति है। सब सेंटर जबल्याणा को तो बंद ही कर दिया गया है। जबल्याणा को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है लेकिन इस संस्थान के लिए लोगों ने छत में एक कमरा डोनेट किया है। सिरिंज लगाने के लिए बेड भी वहां पर लोगों ने डोनेट किया है। लोगों ने 46 हजार रुपये इक्ट्ठा कर के दिये हैं। बेंच पर जहां इंजेक्शन लगते हों, वही हिमाचल आदर्श स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाएगा। ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्दशा है। लेकिन यहां तो दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि शायद सब कुछ बहुत अलग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एम्स के बारे में

कहा। मैं उसके ऊपर एक ही बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ये तो नेहरू जी की सोच थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि नेहरू जी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे और वर्ष 1964 में वे हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन एम्स बिलासपुर की फाउंडेशन दिनांक 3 अक्टूबर, 2017 को हुई और दिनांक 5 अक्टूबर, 2022 को यह फंक्शनल हुआ था। पांच साल में रिकॉर्ड टाइम में एम्स बनकर तैयार हो गया। कल माननीय सदस्य श्री नीरज नय्यर जी कह रहे थे कि नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है? उसमें मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। एम्स बिलासपुर के लिए 1500 करोड़ रुपये मिले, जिससे एम्स बना और पांच साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। आज प्रदेश के युवाओं और प्रदेश के लोगों को उससे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पिछले साल एम्स में 6 लाख 80 हजार ओ0पी0डी0 हुई थी और 752 आई0पी0डी0 भी हुई हैं, इमरजेंसी में लगभग 300 बेड हैं और लगभग 1,000 बेड की फैसिलिटी भी है। इसके साथ-साथ मेरे मेडिकल कॉलेजों के लिए भी 547 करोड़

26.08.2026/1420/डी0सी0/ए0पी0-02

रुपये मिले हैं। चाहे चंबा हो, नाहन हो या हमीरपुर हो। इसके अलावा पी0जी0आई0 सैटेलाइट सेंटर ऊना के लिए 495 करोड़ रुपये और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसे शिमला के चमियाना में बनाया गया है उसके लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जाइका के प्रोजेक्ट के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी दिनांक 22 मई, 2025 को दिल्ली में मिले थे। केंद्र सरकार ने दिनांक 30 जून, 2025 को 1422 करोड़ रुपये की स्कीम अप्रूव कर की थी, जिसमें 90 प्रतिशत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद करती है। अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए ये बड़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं लेकिन हिमाचल को इतना बड़ा लाभ मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रदेश सरकार के बारे में एक चीज कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूर्व में वक्ता कह रहे थे कि पीएम-एभीम में हमें वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2026 तक 360 करोड़ रुपये मिले हैं। यह बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें 15 क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने थे और इसमें से केवल एक यूनिट कम्प्लीट हुआ है और 14 इनकम्प्लीट हैं। इसके साथ-साथ 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बननी थीं लेकिन केवल एक कम्प्लीट हुई है। पैसा लैप्स होने

जा रहा है वर्ष 2026 जारी है। प्रदेश सरकार क्या कर रही है? हमारे 73 ब्लॉक में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने थे हैं, उनमें से अभी एक भी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का काम कम्प्लीट नहीं है और जो हमारा 15वां वित्त आयोग था जिसके तहत हमें 521 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी, उसमें केवल 52 प्रतिशत खर्च हुआ और 48 प्रतिशत लैप्स हो गया है। यही इस सरकार की उपलब्धि है? 48 प्रतिशत बजट जहां लैप्स हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग फार्मा मिला है। सम्माननीय उप-मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। बल्क ड्रग फार्मा हमें दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 को मिला लेकिन उसकी क्लियरेंस दिनांक 25 सितंबर, 2025 को कम्प्लीट हुई और उसके बाद काम शुरू हुआ। तीन साल केवल क्लियरेंस करने में लगे हैं। वहीं हमने पांच साल में बिलासपुर में एम्स बनाकर स्थापित कर दिया और लोगों के लिए लोकार्पण कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें से 225 करोड़ रुपये की

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.08.2026/1425/AT/HK/01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी....

ग्रांट-इन-एड हम लोगों को मिल गई है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है। मैं सबसे बड़ी बात, जिसके ऊपर सुबह भी चर्चा हुई, वह चिट्टे से प्रभावित लोगों को है, चिट्टे का जो कुप्रभाव है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैंने तब भी आपसे विनती की थी, निवेदन किया था कि अस्पतालों में विशेषकर जोनल अस्पतालों में चार-चार कमरे कर दीजिए। नहीं तो बड़ी मुश्किल है उनको कहां एडमिट करेंगे। यह आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दे। यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। I would request the Hon'ble Member Shri Sanjay Rattan jee to come to the dais to preside over.

(सभापति महोदय श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, नियम 130, जिसको माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी लेकर आए हैं, मैं उस प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा हैं। ऐसे मुद्दे के ऊपर इस माननीय सदन के अंदर विचार किया जाना अपने आप में एक बड़ा सराहनीय कार्य है ताकि पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों और इनमें जो कुछ कमियां हों, उनके ऊपर यह सदन विचार करे।

26.08.2026/1425/AT/HK/02

अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो यह एक छोटा-सा पहाड़ी राज्य है, जिसकी कुल आबादी 75 लाख है। इस छोटे राज्य में अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो छोटे और बड़े मिलाकर हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 3 जोनल हॉस्पिटल हैं, 9 रीजनल हॉस्पिटल हैं और 91 सिविल हॉस्पिटल हैं। इसी तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब-सेंटर को मिलाकर लगभग 3,000 के करीब स्वास्थ्य संस्थान इस वक्त प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। इसी तरीके से अगर हम मेडिकल स्टाफ की बात करें तो हमारे पास लगभग 3,000 मेडिकल ऑफिसर इस वक्त कार्यरत हैं, जिनमें 650 स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस समय कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 5,000 पैरामेडिकल स्टाफ पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर, स्वास्थ्य

सुविधाओं का जो मूलभूत ढांचा होना चाहिए, वह हिमाचल प्रदेश में सुदृढ़ है। अब जरूरत है इस ढांचे को आधुनिक करने की और इसे और ज्यादा मजबूत करने की। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। इससे प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का रास्ता खुला है।

आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य विभाग को दो शाखाओं में बांटा था। इसमें एक डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को दो भागों में बांटा गया।

सभापति महोदय इसमें पहले हमारे पास एक ही विभाग होने की वजह से जो क्वालिफाइड डॉक्टर थे, जो स्पेशलिस्ट थे, वे भी इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1430/av/hk/1

श्री सुरेश कुमार-------जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित छोटे होस्पिटल्ज में अपनी पोस्टिंग ले लेते थे जबकि उनकी ज्यादा जरूरत बड़े अस्पतालों में होती है। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ की भी इसी प्रकार की च्वाइसिज रहती थीं। इसके मद्देनज़र माननीय मुख्य मंत्री ने एक स्पष्ट नीति बनाई है जिसमें यह बताया गया है कि हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज, प्रोफैसर्ज, एसिस्टेंट प्रोफैसर्ज और फील्ड के स्टाफ की पोस्टिंग कहां-कहां होनी है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श चिकित्सा संस्थान का कॉन्सेप्ट लाया और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज लगभग सभी 68 विधान

सभा क्षेत्रों में एक-एक आदर्श चिकित्सा संस्थान खोलने का काम आरम्भ हुआ है। इसी के चलते माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे भोरंज विधान सभा क्षेत्र को भी एक आदर्श चिकित्सा संस्थान दिया है जिसके कारण उस अस्पताल में आज वे सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो वहां पर पहले नहीं मिल रही थीं। यह पहली बार हुआ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के आदर्श चिकित्सा संस्थानों में स्पेशलिस्ट्स आए हैं जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अगर मैं अपने भोरंज होस्पिटल की बात करूं तो यह होस्पिटल सन् 1980 के दशक में बना था। उस समय से लेकर मेरे विधायक बनने तक वहां पर वही पुरानी बिल्डिंग, स्टाफ, बैड और इंफ्रास्ट्रक्चर था। वहां किसी एक भी चीज में परिवर्तन या वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले उसी होस्पिटल में बी0एम0ओ0 थे। उनके पिता जी इस माननीय सदन के सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे चुके थे। अगर वे चाहते तो भोरंज होस्पिटल को और ज्यादा बेहतर बना सकते थे। लेकिन उस संस्थान की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज उस बिल्डिंग को उखाड़ कर एक नई बिल्डिंग बनाने का कार्य आरम्भ हुआ है। उसका एक ब्लॉक बनकर तैयार हो चुका है तथा दूसरे ब्लॉक का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री ने हमें वहां पर एक क्रीटिकल केयर यूनिट दी है जोकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उसका टेंडर हो गया है और काम भी आरम्भ कर दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में

26.08.2026/1430/av/hk/2

अब वे तमाम सुविधाएं मिल रही हैं जोकि शहरी क्षेत्र के एक अच्छे होस्पिटल में मिलती हैं। वहां पर पहले केवल चार डॉक्टर्ज हुआ करते थे जबकि वर्तमान में वहां पर 12 डॉक्टर्ज काम कर रहे हैं जिनमें से 6 डॉक्टर्ज अलग-अलग बीमारियों के विशेषज्ञ हैं जोकि वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वहां पर सी0टी0 स्कैन, नयी एक्स-रे मशीन, डायलिसिज और न्यू बोर्न चाइल्ड केयर यूनिट इत्यादि की सुविधाएं मिल रही हैं तथा लोग उनका लाभ उठा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें हमीरपुर

जिला में एक मेडिकल कॉलेज दिया और मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रगति पर है। वह मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी नये भवन में सुचारू रूप से आरम्भ हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के साथ माननीय मुख्य मंत्री ने हमीरपुर के लिए एक कैंसर रिसर्च इन्स्टिच्यूट, गवर्नमैंट डेंटल कॉलेज और गवर्नमैंट नर्सिंग कॉलेज दिया। हमारी सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान हमें हमीरपुर में ये सारी सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ ही

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1435/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
श्री सुरेश कुमार .... जारी

जब हम देखते हैं कि यह मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया तो इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और इस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने के प्रयास में ये सारे लोग जुट गए। लेकिन जब हमने इसकी सच्चाई दस्तावेजों के साथ सदन के समक्ष रखी तो लोगों को इसकी वास्तविकता समझ आई।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो छह मेडिकल कॉलेज हैं आप इनके नामों को ही देख लें। हमारा आई0जी0एम0सी0 अर्थात इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। हमारे पास टांडा मेडिकल कॉलेज है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से है। हमारे पास चंबा मेडिकल कॉलेज है जो जवाहर लाल नेहरू जी के नाम से है। हमारा हमीरपुर का कॉलेज डॉ0 राधा कृष्ण जी के नाम से है। नेर चौक का मेडिकल कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है और नाहन का मेडिकल कॉलेज डॉ0 वाई0एस0 परमार जी के नाम से है। ये सभी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम पर हैं जिससे यह इंगित होता है कि इनको बनाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है और कांग्रेस सरकारों का हाथ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका झूठा श्रेय लेने का प्रयास न करें। यह सच्चाई अब जगजाहिर हो चुकी है।

सभापति महोदय, आज जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमें कभी दिल्ली एम्स या फोर्टीज में देखने और सुनने को मिलती थीं वही सुविधाएं आज हिमाचल प्रदेश में लोगों को

मिल रही हैं। आज रोबोटिक सर्जरी की चर्चा यहां हो रही है। सही बात है कि आलोचना करनी चाहिए लेकिन जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उन अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो पी0एस0सीज0 हैं उनमें पैरासिटामोल तक नहीं मिल रही है। सही बात है कि दवाइयों की भी जरूरत है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें हम कार्य न करें। हमें जहां ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों में सुविधाएं देनी हैं, वहीं नई तकनीक भी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है और इस दिशा में मुख्य मंत्री जी रोबोटिक्स सर्जरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज जो रोबोटिक सर्जरी दिल्ली के अंदर एम्स में होती है, उसी स्तर की रोबोटिक सर्जरी के

26.08.2026/1435/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

माध्यम से आज हमारे आई0जी0एम0सी0, तांडा और मंडी सहित अन्य मेडिकल इंस्टिट्यूट में ऑपरेशन हो रहे हैं। अब इस बात के लिए जहां आप लोगों को सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए वहीं आप इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप इस बात को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने यहां कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। इस प्रकार की बातें करके आप स्वयं को लोगों के समक्ष बेनकाब कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे जो पुराने मेडिकल इंस्टिट्यूट थे उनमें 20-20 वर्ष पुरानी मशीनरी थी। चाहे एक्स-रे मशीन हो या अल्ट्रासाउंड मशीन हो या दूसरे उपकरण हों उनमें से कई उपकरण 20-20 तथा 15-15 वर्ष पुराने थे। आज इन सभी उपकरणों को बदलकर नये उपकरण लगाए गए हैं। यह मुख्य मंत्री जी की सोच है और इसके चलते पैट स्कैन मशीनें जो यहां बड़ी दुर्लभ होती थीं उनकी सुविधा आज हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हो रही है। टेस्ला एम0आर0आई0 जैसी बहुत लेटेस्ट टेस्ला मशीनरी आज हिमाचल प्रदेश के इन संस्थानों में देखने को मिल रही है। सी0टी0 स्कैन और एक्स-रे मशीन जैसे नए उपकरण आज सभी मेडिकल कॉलेजों में लगाए जा रहे हैं। इन उपकरणों के माध्यम से जहां लोगों को फायदा हो रहा है वहीं बीमारी की दर में भी गिरावट हुई है और इसके आंकड़े भी मुख्य मंत्री जी सदन पटल पर रखेंगे।

सभापति महोदय, अभी हिमकेयर की भी यहां बात की गई। यह सही है कि हिमकेयर लाने का जो इरादा पिछली सरकारों का भी था वह लोगों को सुविधाएं देने का था लेकिन इसमें भारी चूक हुई है और इस बात को भी मानना चाहिए। आप लोगों को (विपक्ष) यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हिमकेयर के पीछे एक बड़ा घोटाला भी यहां सामने आया है और हमने उन बातों को भी उजागर किया है तथा अब उसकी परतें खुल रही हैं। ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल इंपैनल कर दिए गए जिनके पास सर्जरी की सुविधा भी नहीं थी लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये के ऑपरेशन कर दिए। पिछली सरकार ने हिमकेयर के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की जो देनदारी छोड़ी थी, वह वर्तमान सरकार

एन0एस0 द्वारा ... जारी

26.08.2026/1440/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री सुरेश कुमार ------जारी

के ऊपर थोपी है। जिनमें से हम 500 करोड़ रुपये दे चुके हैं लेकिन अभी भी लगभग 450 करोड़ रुपये की देनदारियां ऐसे हॉस्पिटलों की हैं जिनमें गुणवत्ता नहीं है और जिनका कोई पता नहीं है। ऐसे-ऐसे संस्थान हिमकेयर योजना में इम्पैनल्ड कर दिए गए थे। ये सारे विषय इन्क्वायरी के हैं और ये सभी तथ्य जांच में सामने आएंगे। एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला वाकया भी सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की बच्चेदानी के भी ऑपरेशन देखने को मिले हैं। इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं?

सभापति महोदय, आज यहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हो रही थी। मैं माननीय सदस्य जम्वाल जी का भाषण भी सुन रहा था। वे कह रहे थे कि हमारे पास दिल्ली से से इतना पैसा आ गया और इतना पैसा वापस हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई पैसा वापस हुआ होगा तो वह भी केंद्र सरकार की वजह से ही हुआ होगा या उसकी एन0ओ0सी0 नहीं मिली होगी या उसमें समय पर पैसा नहीं आया होगा अन्यथा हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मामला नहीं है कि केंद्र से पैसा आया हो और खर्च न हुआ हो। यहां पर एम्स की बात कर रहे हैं। एम्स में यदि स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं तो मैं आपको एम्स के बारे

में भी बताना चाहता हूं कि आप एम्स का श्रेय भी झूठा ले रहे हैं। एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान हुई थी। उस समय केंद्र सरकार का निर्णय था कि पूरे देश में प्रत्येक राज्य में एक एम्स, एक आई0आई0टी0 और एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। यह केंद्र सरकार का उस वक्त का निर्णय था। अब देर हो गई और यह आपके पास पहुंच गया तो आपने भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर ली है। जहां तक आप बिलासपुर के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और आप नड्डा जी का गुणगान कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि आप उनका गुणगान कीजिए लेकिन यदि नड्डा जी एम्स के लिए इतने पैसे दे रहे हैं जितनी आप गिनती कर रहे हैं तो वे बिलासपुर के हॉस्पिटल के लिए भी पैसे दे देते वह भी उनका ही हॉस्पिटल है और वे भी बिलासपुर से ही संबंध रखते हैं। आज आप कह रहे हैं कि वहां बी0पी0 नापने का भी उपकरण नहीं है। ...(व्यवधान) यह तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए शर्म की बात होनी चाहिए और आप यहां उस बात को इतना उठा रहे हैं।

26.08.2026/1440/एन0एस0-वाई0के0/2

मैं कहना चाहता हूं कि आप विरोध कीजिए। यह अच्छी बात है क्योंकि विरोध करना विपक्ष का कार्य है लेकिन विरोध सकारात्मक होना चाहिए और आपको सही बातें करनी चाहिए। आप इस तरीके की बातें कहते हैं कि किसी को मंगलसूत्र बेचकर इलाज करवाना पड़ रहा है। कल हमारे एक साथी भी कह रहे थे कि किसी को मंगलसूत्र बेचकर इलाज करवाना पड़ रहा है। यदि आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है कि कोई व्यक्ति मंगलसूत्र बेचकर इलाज करवा रहा है तो सबसे पहले यह आपके लिए शर्म की बात है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। आपको भी यहां से पैसे मिलते हैं, आप अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से उनका इलाज करवा देते। यदि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ऐसी कोई बात होती तो मैं ऐसा नहीं होने देता। मैं किसी का मंगलसूत्र बिकने नहीं देता। हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। जिस किसी को इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो हम उसकी सहायता करते हैं। इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वाली भ्रामक बातें इस माननीय सदन में न रखें। जो तथ्य हैं और जो सही बातें हैं उन्हें लेकर

आएं। अगर कोई कमियां हैं तो आप उन्हें जरूर उजागर कर सकते हैं। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी सरकार ने जो बदलाव किए हैं उनके जब नतीजे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश बेहतर और अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। मुझे यही कहना था।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र शौरी -----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

26.08.2026/1445/RKS/Ag-1

श्री सुरेन्द्र शौरी : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार और अन्य विधायक साथियों ने नियम-130 के अंतर्गत जो प्रदेश की वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मैं भी चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हम प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध केवल डॉक्टरों और अस्पतालों से नहीं है बल्कि प्रत्येक परिवार के जीवन और भविष्य से जुड़ा है। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य केवल बीमार होने के बाद उसका इलाज करवाना है या बीमारी को गंभीर होने से पहले उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है? सभापति महोदय, जब बीमारी छोटी होती है तो उसका इलाज सस्ता होता है लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसका उपचार महंगा और कठिन हो जाता है। जब बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है तो कई बार पैसा भी जीवन वापस नहीं ला सकता। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। आज प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है। कभी

रोबोटिक सर्जरी की घोषणा की जाती है, कभी आधुनिक मशीनों की बात की जाती है और कभी नई-नई तकनीकों के दावे किए जा रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि प्रदेश का आम आदमी आज छोटी-सी बीमारी की दवाई के लिए भी परेशान है। जब प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को आवश्यक दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो रही हैं तब उनके लिए रोबोटिक सर्जरी किस काम की है? जिस गरीब व्यक्ति के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं उसकी पहली आवश्यकता रोबोटिक सर्जरी नहीं है। उसकी पहली जरूरत यह है कि उसे अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हो, दवाई उपलब्ध हो और सामान्य टैस्ट करवाने के लिए लैब तकनीशियन उपलब्ध हो। आज हम देख रहे हैं कि हिमकेयर योजना मरीज और अस्पताल के बीच एक बड़ी समस्या बनकर रह गई है तथा इससे प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति परेशान दिखाई दे रहा है। आम व्यक्ति यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर हिमकेयर योजना की व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हो गई है जिसके कारण प्रदेश के सैंकड़ों मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस सरकार का ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ओर बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी आज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देख रहे हैं। मैं अपने बंजार विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां लगभग एक लाख की आबादी है लेकिन वहां पर इस पूरी आबादी के लिए मात्र 6 स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध हैं। वहां एक सिविल अस्पताल बंजार, दो सी0एच0सीज0, सैंज एवं

26.08.2026/1445/RKS/Ag-2

गड़सा में और तीन पी0एच0सीज0 स्थापित हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस सरकार ने बंजार विधान सभा क्षेत्र के साथ घोर अन्याय किया है। इस सरकार ने एक साथ हमारे 10 स्वास्थ्य संस्थानों को डी-नोटिफाई कर दिया है। मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यदि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी विधान सभा क्षेत्रों का आकलन किया जाए और पी0एच0सी0 से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक के आंकड़े देखे जाएं तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम 40, 50 या 100 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत होंगे किन्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र में मात्र 12 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं। इनमें से 6 सिविल हॉस्पिटल बंजार में, 2 सी0एच0सी0 सैंज में,

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1450/बी.एस./ए.जी-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

बैठते हैं। एक गडसर की सी0एस0सी0 में है, एक थाटीबीड़, एक गुशैणी और एक न्यूली में है। यानी एक लाख की आबादी पर मात्र 12 मेडिकल ऑफिसर हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने जो मेडिकल ऑफिसरों की अन्य 22 पोस्टें क्रिएट की थीं उनको सारी-की-सारी को डिनोटिफाई कर दिया। आज क्या स्थिति है? आज एक मरीज को टैस्ट के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जिस विधान सभा क्षेत्र में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है कि ठीक से किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या डिपार्टमैंट सर्वे करता है कि कहां संस्थान की जरूरत है और कहां संस्थान खोला जाना चाहिए और कहां कितनी पॉपुलेशन है? यानी एक लाख की आबादी पर मेरी विधान सभा के अंदर मात्र बीस बैड हैं।

अध्यक्ष महोदय, मात्र 20 बैड में एक लाख लोगों का इलाज होता है। यह एक मात्र सिविल हॉस्पिटल बंजार में है। बाकी पूरी विधान सभा के अंदर कहीं भी मरीज एडमिट नहीं होता है न नाइट सर्विस है। एक बंजार के सिविल हॉस्पिटल को छोड़कर यह आज धरातल की सच्चाई है जिसे यह सरकार नहीं समझ पा रही है। एक साथ 10 संस्थान डिनोटिफाई करना बहुत बड़ा अन्याय है।

मेरी विधान सभा की भौगोलिक स्थिति बहुत विषम है। यह दुर्गम क्षेत्र है। अगर हम एक छोर से दूसरे छोर की बात करें तो डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पड़ती है और इसके अंदर 5-6 वैलियां हैं। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार ने जो घोर अन्याय मेरी विधान सभा के साथ किया है मुझे लगता है कि वह सहन करने लायक नहीं है।

हमने पांच पी0एस0सीज0 जगह- जगह खोली थी ताकि लोगों को घर-द्वार में सुविधा मिले। लेकिन वे पांचों की पांचों पी0एस0सीज0 बंद कर दी गई। गाड़ागुशैणी के पास दीमन चाहड़ी की पी0एस0सी0 बंद कर दी गई। जिभ्भी में पी0एस0सी0 खोली थी। वहां पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं। चार- पांच सौ होमस्टे वहां पर हैं और

25.08.2026/1450/बी.एस./ए.जी-2

होटल भी हैं। सौझा, बाहू और तांदी का क्षेत्र है। लेकिन सुविधा देने के लिए एक भी डॉक्टर वहां नहीं है और वे पी0एस0सीज0 बंद कर दी गई।

तिर्थन घाटी और बठाड़ का दुर्गम क्षेत्र है। वहां पर पी0एस0सी0 खोली थी। वह डिनोटिफाई कर दी गई। चार पंचायतों का केंद्र देवटा है। वहां की पी0एस0सी0 डिनोटिफाई कर दी गई। सैंज का दुर्गम क्षेत्र देवरी है वह पी0एस0सी0 डिनोटिफाई कर दी गई है। ऊह का स्वास्थ्य केंद्र डिनोटिफाई कर दिया गया।

सिविल हॉस्पिटल बंजार को हमने50 से 100 बैडिड किया था लेकिन वहां 20 बैड ही लगे हैं। उसको भी डिनोटिफाई करके उसमें 50 बेड रखे गए। हमने वहां मेडिकल ऑफिसरों की पोस्टें 6 से बढ़ाकर 14 कर दी थी। इस सरकार ने उनको डिनोटिफाई करके 6 की 6 पोस्टें रखी हैं

हमने सैंज के अंदर नाइट सर्विस की बात की थी। वहां चार मेडिकल ऑफिसर बैठने चाहिए। उस हॉस्पिटल को डिनोटिफाई कर दिया गया जहां सैंज की पॉपुलेशन के साथ बाकी 16-17 पंचायतें भी हैं और वहां लगभग 25-30 हजार की आबादी है। वहां नाइट सर्विस नहीं है। 30 हजार की आबादी पर एक पेशेंट भी वहां एडमिट नहीं होता जिसे नाइट में सर्विस मिल सके।

हमारी गड़सा की पूरी वैली है। वहां मात्र एक डॉक्टर बैठता है। वह सुबह 9:00 बजे आता है और 5:00 बजे चला जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है।

बंजार के अस्पताल का भवन वर्ष 2022 के अंदर जब हमारी सरकार थी तब 80 प्रतिशत बन चुका था लेकिन इन चार वर्षों के अंदर यह सरकार उसको कम्प्लीट नहीं कर पाई है। हमने अपने कार्यकाल के अंदर जमीन की व्यवस्था भी की थी। वहां ट्रांसफर लगा था उसको हटाया अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वर्ष 2020 में उसका काम शुरू किया और वर्ष 2022 में 80 प्रतिशत काम पूरा कर दिया था लेकिन आज वर्ष 2026 में चार वर्ष बाद भी वह हॉस्पिटल उसी अवस्था में है। ...(घंटी)...

25.08.2026/1450/बी.एस./ए.जी-3

अध्यक्ष महोदय, यह धरातल की सच्चाई है। आज जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहां न फीमेल हेल्थ वर्कर है न मेल हेल्थ वर्कर है और न हर उप स्वास्थ्य केंद्र में सी0एच0ओ0 है।

आप रोबोटिक सर्जरी की बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन क्या सभी पेशेंट रोबोटिक सर्जरी के लिए यहां पहुंचेंगे? मैंने पहले कहा कि अगर बीमारी को शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए तो रोबोटिक सर्जरी के लिए बहुत कम लोग पहुंचेंगे।

लेकिन हम धरातल की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनिंग करने के लिए निचले स्तर का लो लेवल स्टाफ नहीं है और न ही संस्थान हैं। अच्छा होता कि 30-30 करोड़ रुपये की जो रोबोटिक सर्जरी की मशीनें आप खरीद रहे हैं यदि एक- दो रोबोटिक सर्जरी से काम चल पड़ता है तो भारी मात्रा में रोबोटिक सर्जरी की मशीनें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि धरातल पर 10 हजार की आबादी पर एक पी0एस0सी0 होनी चाहिए जहां पर प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और वहां पर एक गरीब आदमी को अपनी बीमारी के बारे में पता लगे

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1455/DT/AS-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

वहां पर लैब टेक्नीशियन हो और वहां पर उसके सभी टेस्ट हों। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी विधान सभा के अंदर स्वास्त्थ्य सेवाओं के जो हाल हैं वे बताए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने चार वर्ष के अंदर एक भी नया संस्थान नहीं खोला। जो दस संस्थान डिनोटिफाई किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि वे संस्थान पुनः खोले जाएं। बंजार अस्पताल का दर्जा बढ़ाया जाए। सैंज और गड़सा के स्वास्थ्य संस्थानों में नाइट सर्विस शुरू की जाए ताकि हमारे लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। आज एक लाख की आबादी के अनुपात को हम लें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बंजार हास्पिटल में मात्र 20 बेड लगे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इसलिए सभापति महोदय यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात हो रही है उसमें हिमकेयर की बात भी कहीं गई। मैं कहना चाहूंगा कि पहले हिमकेयर योजना में 5 लाख रुपये तक उपचार करवाने की सुविधा लोगों को थी आज वह सुविधा उन्हें नहीं मिल रही। आज कुल्लू जिले या मंडी जिले में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आस-पास के हस्पतालों में इसके उपचार की सुविधा नहीं है, इसके लिए एक मात्र प्राइवेट हॉस्पिटल मांडव सिटी हार्ट गुटकर में है। वहां पर लोग अपने हार्ट संबंधि बीमारी के उपचार के लिए आते हैं। माननीय सदस्य श्री सुरेश जी कह रहे हैं कि सरकारी हस्पतालों में पैसा नहीं देना पड़ता। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि वहां पर हिमकेयर योजना का कार्ड भी नहीं चल रहा है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहा है। वहां पर रोज 10 से 15 ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन का दो से ढाई लाख रुपये खर्च आता है और किसी को स्टंट डलवाना पड़ जाए तो खर्च और बड़ जाता है। इसलिए मैं सभापति महोदय से कहना चाहूंगा कि क्या कारण है इसकी जांच की जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि यहां पर आयुष्मान कार्ड चले तथा उस गुटकर के मांडव अस्पताल में हमारा हिमकेयर कार्ड भी चले। इसलिए सभापति महोदय आज हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों मेरे कुल्लू अस्पताल के अंदर मंजू शर्मा की दुखद मृत्यु हुई। उनकी डिलीवरी हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई। वह घटना अपने आप में ही अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है और वहां पर कैसी व्यवस्था है, उसकी पोल खोलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंजू शर्मा की मृत्यु की उच्च स्तर पर जांच की जाए ताकि

जो-जो कमियां रही हैं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हस्पताल में क्या - कया कमिया रहीं किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई उसकी पूरी जांच होनी चाहिए

26.08.2026/1455/DT/AS-2

ताकि भविष्य में किसी अस्पताल में ऐसी घटना न हो और मरीजों के साथ ऐसी स्थिति में दुर्व्यवहार भी न हो। इसीलिए मैं माननीय सदन में यह बात रख रहा हूं।

माननीय सभापति, मैंने अपनी विधान सभा का जो जिक्र आपके समक्ष किया है उससे मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूरी उम्मीद है कि जो संस्थान डिनोटिफाई किए हैं और जो डॉक्टरों के पद डिनोटिफाई किए गए हैं उन पर आप पुनः विचार करेंगे तथा वहां के हस्पताल में पर्याप्त स्टाफ हो उसके लिए ठोस और समयबद्ध रूप से कुछ कदम उठाएंगे। बंजार हस्पताल को वर्तमान सरकार ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा तो कर दी इस संस्थान में कहा सुवधिाएं बढ़नी चाहिए थी इसके विपरीत वहां की सुविधाएं छीन ली गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस पर आप जरूर गौर करें।

बड़े अस्पतालों के अंदर जहां तक केंद्र सरकार के सहयोग की बात है मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के बिना स्वास्थ्य व्यवस्था में एक पल भी सांस नहीं सकती। आज प्रदेश के अंदर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वह केंद्र सरकार के सहयोग से ही मिल रही हैं। एम्स बिलासपुर, चाहे वह दो हजार करोड़ रुपये का इंस्टिट्यूट बना है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है और नेशनल स्वास्थ्य मिशन जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जायका द्वारा प्रायोजित 1,422 करोड़ रुपये के एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश को मिल रहा है उसी से प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सांस ले रहा है और जिसके लोन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार चुकाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के सहयोग के लिए हमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय श्री जे.पी. नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एम्स जैसा संस्थान बिलासपुर में प्रदेश को को दिया है जो कुल्लू, मंडी, बिलासपुर इन

सभी क्षेत्रों को कवर करता है। इस लिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय आप प्रदेश की बिगड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्था पर अवश्य गौर करें तथा धरातल के अंदर लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1500/ए.एस.-एन.जी./1

श्री सुरेन्द्र शौरी के पश्चात.......... जारी

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री मलेन्द्र राजन भाग लेंगे।

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी ने जो प्रस्ताव लाया है, वह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का जो दौर मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया, उसमें चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और ये बहुत ही तजुर्बेकार हैं तथा काफी वर्षों तक इन्होंने प्रदेश और देश में अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

सभापति महोदय, जहां तक स्वास्थ्य का विषय है, तो मैं समझता हूं कि यह केवल एक विषय नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। जिस मंशा के साथ माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी इस प्रस्ताव को लेकर आए, मैं

समझता हूं कि हमारे विपक्ष के कुछ साथी उस विषय से भटक गए और राजनीति की तरफ ज्यादा चल पड़े। अच्छा होता कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां इनको नजर आ रही हैं, उन्हें यहां पर बताते। इसके अलावा अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के अंदर अगर इनको कोई कमी नजर आ रही है, तो उन्हें भी यहां पर बताते। लेकिन इन्होंने उन कमियों को उजागर न करते हुए इस विषय पर भी राजनीति शुरू कर दी।

26.08.2026/1500/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है या शिक्षा का क्षेत्र, प्रदेश सरकार व माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लगातार मजबूत प्रयास इन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। मैं अपने इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो सिविल अस्पताल हैं—एक, सिविल अस्पताल इंदौरा और दूसरा, सिविल अस्पताल गंगथ। सिविल अस्पताल इंदौरा को प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा भी दिया गया है। पिछली सरकार में वहां पर डॉक्टरों की कमी थी, एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज सिविल अस्पताल इंदौरा में आठ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनमें से पांच स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का धन्यवाद करता हूं। पिछले साल जब शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा था, तब हमने मंत्री जी के साथ कुछ समस्याओं का जिक्र किया था। वे समस्याएं हमारे स्वास्थ्य विभाग से और हमारे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं। इन्होंने स्वयं हमारे दोनों अस्पतालों का, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल गंगथ हो या सिविल हॉस्पिटल इंदौरा, इन्होंने वहां पर स्वयं जाकर निरीक्षण किया। वहां पर जो कमियां थीं, उनको देखा और उन कमियों को काफी हद तक दूर भी किया।

सभापति महोदय, अगर मैं वर्ष 2022 की बात करूं तो सिविल हॉस्पिटल गंगथ में केवल एक डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा था। इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की सामान्य जनता के आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना, तब मेरे सामने उस गंगथ क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि सिविल हॉस्पिटल गंगथ में सिर्फ एक ही डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.08.2026/1505/DC/PB/1

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

मैं प्रदेश सरकार तथा मुख्य मंत्री जी और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज गंगथ के हमारे सिविल अस्पताल में छह डॉक्टर्ज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को वहां आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं।

इसके अतिरिक्त, इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी पी0एस0सी0 हैं वहां भी डॉक्टर्ज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिविल अस्पताल इन्दौरा के भवन के निर्माण कार्य की बात करें तो उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा यह अस्पताल उद्घाटन के लिए तैयार है इसलिए शीघ्र इसका उद्घाटन करवाया जाए। इसके साथ ही वहां की छोटी-मोटी कमियों को दूर किया जाए। पूरे प्रदेश में सिविल अस्पतालों में जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उसी प्रकार इस अस्पताल में भी जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

सभापति महोदय, इसी विषय पर एक शेर कहना चाहूंगा—

बदल रही है तस्वीर, बदल रहा है हिमाचल,
बदल रही है तस्वीर, बदल रहा है हिमाचल,

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हिमाचल।
मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं हमारा,
मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं हमारा,
हर मरीज को मिले बेहतर इलाज, यही संकल्प है हमारा।

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार तथा मुख्य मंत्री जी इसी विषय पर काम कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो प्रदेश सरकार का मकसद केवल नए संस्थान खोलना नहीं है। पुरानी व्यवस्था तथा पुराने संस्थानों को कैसे मजबूत किया जाए और उनमें कैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और कार्य कर रही है।

26.08.2026/1505/DC/PB/2

आज प्रदेश में चाहे रोबोटिक सर्जरी की बात हो, चाहे थ्री टेस्ला एम0आर0आई0 की सुविधा मिलनी शुरू हुई हो, चाहे हाई-एंड मेडिकल उपकरणों की सुविधा हो, चाहे कैंसर उपचार के लिए विशेष सुविधाएं हों तथा प्रत्येक क्षेत्र में मेडिकल स्पेशलिस्ट की नियुक्तियां और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जा रही हों, ये सभी कार्य प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री जी की एक सोच को दर्शाते हैं।

सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम राजनीति के लिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टर्ज, डॉक्टर्ज तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के सदस्यों पर उंगली उठाकर उनकी कारगुजारी पर सवाल न उठाएं और उनका हौसला तोड़ने का काम न करें। ये लोग दिन-रात प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं और मरीजों के उपचार में लगे हुए हैं। इसलिए हम विधान सभा में विभिन्न विषयों पर टीका-टिप्पणी करके उनका हौसला तोड़ने का काम न करें।

सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी प्रदेश में कुछ अच्छे कार्य होने पर यह कहते हैं कि ये केंद्र सरकार ने दिया है। मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक है केंद्र में इस समय भाजपा की सरकार है तो हर उस बात का श्रेय केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश भी केंद्र सरकार की देन है। यदि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है और आज हम इस सदन में अपनी बात रख पा रहे हैं तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है तथा उस समय की केंद्र सरकार की देन है। इसी वजह से हम लोग यहां इकट्ठे बैठकर अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए हर बात को केवल राजनीतिक मकसद से यह कह देना

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1510/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री मलेन्द्र राजन जारी .....

कि यह केंद्र सरकार की देन है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी देन अगर हिमाचल प्रदेश को है तो वह यह है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया। यह बात प्रत्येक हिमाचलवासियों को नहीं भूलनी चाहिए। इसके अलावा बहुत-सी योजनाएं केंद्र में जब यू0पी0ए0 की सरकार थी, उस समय राइट-टू-एजुकेशन, राइट-टू-हेल्थ, राइट-टू-इनफॉर्मेशन जैसी बहुत-सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। मैं समझता हूं कि हमारे भाजपा के नेता, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हों या शिक्षा के क्षेत्र से, इनको आजकल सत्ता में आने की जल्दी है। अहंकार के नशे में कुछ नेता इतने चूर हैं। मैं सभी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ नेता अहंकार में आज चूर हैं कि उनको सत्ता में आने की बहुत जल्दी लगी है। वे यह भूल गए हैं कि सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता के वोट के साथ ही वे सत्ता में आ सकते हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। यहां पर कई बातों का जिक्र आया है, चाहे मैं अपने

इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। यहां पर हिमकेयर योजना के बारे में भी कहा गया कि हिमकेयर योजना को बंद कर दिया गया है। हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके बारे में बार-बार इस सदन में कहा है कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है। इस योजना में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किए जा रहा है। इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको दूर करने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हिमकेयर का लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रहा है। लेकिन बार-बार कुछ विपक्ष के साथी इस बात को उठा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, जिन्होंने हिमकेयर योजना में करोड़ों रुपये कमाए हैं, उनके दबाव में ये विपक्ष के साथी बार-बार हिमकेयर योजना को सामने लेकर आते हैं ताकि उनकी दुकानदारी फिर से चले सके।

26.08.2026/1510/डी0सी0/ए0पी0-02

विपक्ष के कुछ साथियों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है। मैं अपनी बात को एक शेयर के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा :-

"मंजिल हमारी साफ है, इरादों में विश्वास है,

स्वस्थ हिमाचल, सशक्त हिमाचल, यही सुक्खू सरकार का विश्वास है।"

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तथा प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव लाने की आपकी सोच है, हम आपकी उस सोच को नमन करते हैं। हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर हमारे विपक्ष के साथियों ने जो सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उन पर अमल किया जाए और जिन्होंने राजनीतिक तौर पर इस विषय को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए हम 70 लाख हिमाचलियों के हित के लिए आने वाले समय में कार्य करें। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं सभापति महोदय का दिल से

धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद।

26.08.2026/1510/डी0सी0/ए0पी0-03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य के विषय पर जो चर्चा माननीय सदन में चली हुई है, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.08.2026/1515/AT/HK/01

श्री प्रकाश राणा जारी....

अब हमारे साइड के भी लोग चाहते हैं कि हम भी इनके साथ बदले का काम करें। मुझे आपका जवाब देना ही पड़ेगा, एक तो आप साथ में ही बैठते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हेल्थ की चर्चा हर बार होती है। कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसमें हेल्थ पर चर्चा न हुई हो। लेकिन चर्चा करते-करते जब हम वही पुरानी बातें रखते हैं, तो हमें भी थोड़ा शर्म आती है आपनी बात रखने में। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, पांच बार हुआ, यानी आठ-दस बार हो गया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अब बात तो रखनी पड़ती है सर, लेकिन शर्म आती है हमें कैसे हम हर बार एक ही बात रखें?

अब हो क्या रहा है यहां पर? हमारे सत्तापक्ष के भी माननीय भाई लोग हैं, वे यह बात रखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि हमारे चुनव क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, ये दोनों अलग-अलग विषय हैं। अब किसको हम सही मानें?

एक बात मैं कहना चाहता हूं। अब हाउस चलता है, माननीय स्पीकर साहब, और इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सत्तापक्ष का काम है कि वह प्रदेश को चलाए और हमारा काम है कि अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसमें बात उठाएं। लेकिन अब अगर दोनों काम आप ही करेंगे, तो हमारा क्या काम रह गया यहां पर? सत्तापक्ष का भी आप कर रहे हैं और विपक्ष की भी भूमिका आप निभाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? यह तो हमें भी कोई काम होना चाहिए यहां पर।

मुझे लगता है कि इसके रूल-रेगुलेशन को हमें समझना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि यह नहीं है, तब आप बोलते हैं कि पहले भी ऐसा ही था। आप फिर पीछे पांच साल की बात घुमा देते हैं कि यह तो तुम्हारे समय का है। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हाउस को चलाना है, तो बात स्पष्ट होनी चाहिए। आपका काम प्रदेश सरकार को चलाना है और साथ ही हाउस भी चलाना है। यह आपकी ड्यूटी बनती है।

26.08.2026/1515/AT/HK/02

अगर हम कोई बात करते हैं, तो आप प्लीज़ यह न बोलें कि पांच साल पहले भी यही था। अगर पांच साल पहले यही था, इसलिए तो हम में विपक्ष में बैठे हैं, यह जनता डिसाइड करती है। अगर आपको जनादेश हिमाचल की जनता ने दिया है, तो आप अपनी भूमिका निभाएं। आप हमारे जवाब हमें क्यों दे रहे हैं?

सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब है, अगर बात चाहे हम कम करें यहां पर, लेकिन स्पष्ट बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं सत्तापक्ष वालों से यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी भूमिका न निभाएं, विपक्ष की नहीं, आप रूलिंग की भूमिका निभाएं।

दूसरी बात है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। जब से सरकार आई है, अब मैं सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर की बात करता हूं। वहां पर 19 पोस्टें हैं पर डॉक्टर अभी भी सात-

आठ ही बचे हैं। जोगिंदरनगर में यह हाल है। एक ही सिविल हॉस्पिटल बड़ा है हमारे पास, लडभड़ोल सिविल हॉस्पिटल है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी जब मुख्य मंत्री बने, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल बनाया और पोस्टें भी छह-सात हैं वहां पर।

लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज लगभग चार साल होने को आ गए हैं। जितनी बार भी चर्चा हुई है हमने बात बोली है और वह सारा विधान सभा में रिकॉर्डेड है। अगर इसमें कोई शक है तो दोबारा आप देख सकते हैं।

सिविल हॉस्पिटल लडभड़ोल में तकरीबन 24-25 पंचायतें उसमें डिपेंड हैं और वहां पर एक डॉक्टर है। पहले तो एक भी नहीं था अब वहां पर एक डॉक्टर डिप्यूटेशन पर आता है। 24 घंटे सिविल हॉस्पिटल चलता है। तो अब बताइए, एक डॉक्टर वहां पर होगा तो उस हॉस्पिटल का सिविल हॉस्पिटल फिर नाम क्यों है? अगर उस को बंद करना सही है तो बंद कर दो तब ही अच्छा रहेगा। है क्योंकि जब हॉस्पिटल चलना नहीं है तो बंद करो।

लेकिन एक डॉक्टर जो है, वह चौबीस घंटे कैसे काम करेगा वहां पर? सिविल हॉस्पिटल डे-नाइट चलता है। यह सोचने का विषय है। अब जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री

26.08.2026/1515/AT/HK/03

कल बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय ऑक्यूपेंसी यहाँ पर 35 परसेंट थी और हमने इसको 65 परसेंट किया। फिर जब 65 परसेंट किया, तो जहां सात पोस्टें हैं,

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1520/av/hk/1

श्री प्रकाश राणा-------जारी

वहां तीन-चार वर्षों से एक ही डॉक्टर है। बीच में एक-आध या दो महीनों के लिए दो-दो डॉक्टर्ज हुए मगर बाद में फिर एक ही रह गया। आप खुद बताइए कि एक सिविल होस्पिटल में केवल एक ही डॉक्टर से कैसे काम चल सकता है। यहां तक कि कई बार एक भी नहीं था और होस्पिटल बिल्कुल खाली हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके 65 प्रतिशत डॉक्टर कैसे बने जब वर्ष में केवल एक ही डॉक्टर है तो उसकी सिर्फ 14-15 प्रतिशतता बनती है। यहां पर सरकार द्वारा कहा जाता है कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। आप लोग कहने से पहले कम-से-कम धरातल पर तो देख लिया कीजिए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? माननीय मंत्री, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड होगा? वहां सिविल होस्पिटल में केवल एक डॉक्टर है, वह भी एक वर्ष या दो वर्ष नहीं बल्कि पिछले चार वर्षों से एक ही है। वहां पर नर्स रात को मरीज को देखकर रैफर करती है। ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुःख होता है, अगर इसका किसी के पास जवाब है तो मुझे बताइए? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप अभी प्रदेश की जनता को साधारण बीमारियों के इलाज की सुविधाएं तो दीजिए।

सभापति महोदय, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप कम-से-कम यह देख लिया कीजिए कि कौन-सा निर्वाचन क्षेत्र कितने-कितने वर्ग मीटर्ज तक फैला हुआ है। आप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को उस हिसाब से पैसा, डॉक्टर्ज और दूसरी सुविधाएं दीजिए। अभी मुख्य मंत्री जी बैठे नहीं है और मुझे लगता है कि इनका पूरा हमीरपुर जिला इतना बड़ा नहीं है जितना जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र अकेला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कम-से-कम निर्वाचन क्षेत्र के एरिया के हिसाब से काम कीजिए यानी जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना पैसा व सुविधाएं दी जाएं। अब आप कहते हैं कि सबको बराबर दिया जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि वैसा भी नहीं हो रहा।

यहां और भी माननीय सदस्य होंगे जिनके निर्वाचन क्षेत्रों के सिविल होस्पिटल्ज में केवल एक-एक डॉक्टर है। ...(व्यवधान) मेरे पीछे बैठे श्री दलीप ठाकुर के यहां भी यही स्थिति है।

26.08.2026/1520/av/hk/2

माननीय मंत्री, हम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे। हमें अभी पता चला है कि वहां के लिए एक डॉक्टर का स्थानांतरण हुआ है और वहां पर अब दो डॉक्टर्ज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि सत्र शुरू होने पर दो डॉक्टर्ज कर दिए जाते हैं और सत्र की समाप्ति के बाद वहां पर दोबारा से एक ही डॉक्टर रह जाता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 35 सब-सेंटर्ज हैं जिनमें 19-20 रिक्त चले हुए हैं। उनमें फिमेल हैल्थ वर्कर्ज नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 15-16 आयुर्वैदिक संस्थान हैं जिनमें से 8-10 खाली चले हुए हैं। मैंने जैसे कहा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्द्रनगर एरियावाइज काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे केवल 5-6 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनका एरिया काफी वर्ग किलोमीटर्ज तक फैला हुआ है। आपने अगर बाकी निर्वाचन क्षेत्र के सिविल होस्पिटल्ज में 65 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दी है तो हमें क्यों नहीं दी, हमारा क्या कसूर है? मंत्री जी, मैंने इस बारे में आपसे अनुरोध भी किया था और आपने भी अपनी तरफ से कोशिश की है जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे पास जहां डॉक्टर्ज की 19 सैंक्शन्ड पोस्ट्स थीं वहां आपने 15 कर दिए थे। मगर वे केवल एक-दो महीने ही रहे, उसके बाद एक-एक करके अब दोबारा से वहां पर केवल 7-8 डॉक्टर्ज ही रह गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंतड़ा की बात करना चाहता हूं। इस बारे में एक प्रश्न भी लगा है। वहां पर केवल एक डॉक्टर है जबकि वह काफी पोपुलेटिड एरिया है। वहां की एक वर्ष की ओ0पी0डी0 24-25 हजार बताई गई है। अगर देखा जाए तो एक महीने की एवरेज 25-26 सौ आती है। अब आप खुद सोचिए कि एक डॉक्टर एक दिन में 100-150 मरीज कैसे देखेगा क्योंकि काम तो महीने के 25-26 दिन ही होता है। उसके बावजूद वे डॉक्टर काम चला रहे हैं परंतु आप खुद ही बताइए कि क्या एक डॉक्टर एक दिन में इतने मरीज देख सकता है? मान लीजिए, किसी दिन देख भी लिए परंतु रोज़ाना

नहीं देख सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का सिस्टम सही हो जाए तो हमारा प्रदेश काफी आगे जा सकता है। इसलिए इन दोनों सिस्टम्ज पर ध्यान दिया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग बहुत परेशान हैं। ...(घण्टी) सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी। आप जब दूसरों को 30-30 मिनट्स देते हैं तो हमने भी क्या बुरा किया है, हमें भी पूरा समय दीजिए।

26.08.2026/1520/av/hk/1

सभापति : माननीय सदस्य, यह फर्स्ट वॉर्निंग है।

श्री प्रकाशा राणा : सभापति महोदय, ठीक है। इसका मतलब अभी तीन और आएगी।

सभापति : जी।

श्री प्रकाश राणा ---**टी सी द्वारा जारी**

26.08.2026/1525/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री प्रकाश राणाः...(व्यवधान) सभापति महोदय, हिमकेयर के संबंध में मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बंद न किया जाए। जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं तब मरीजों को रैफर ही किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कम-से-कम हिमकेयर की सुविधा तो उपलब्ध रहनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी चौंतड़ा पंचायत का 15 दिन पहले का मामला है। वहां के प्रताप सिंह, मटरू नामक पंचायत के गरीब मरीज को टांडा में एडमिट किया गया। उनसे अस्पताल में हिमकेयर कार्ड लिया और फॉर्म भी भर लिया गया तथा वह ओके हो गया। जब उनका इलाज हो गया और ऑपरेशन आदि हो गया तथा उन्हें डिस्चार्ज करने की स्थिति आई तो उनका लगभग 1.36 लाख रुपये का बिल बन गया। उस समय अस्पताल की ओर से कहा गया कि अब यह कार्ड नहीं चलता। जब पहले फॉर्म भरकर उन्हें एडमिट किया गया था तो बाद में यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? मैंने इस संबंध में हॉस्पिटल के प्रिंसिपल

से भी बात की और पूछा कि यदि हिमकेयर कार्ड नहीं चल रहा था तो पहले फॉर्म भरवाकर मरीज को एडमिट क्यों किया गया? उनका कहना था कि उस समय सिस्टम ठीक था और अब सिस्टम नहीं चल रहा है। यदि सिस्टम दो-तीन दिन पहले ठीक था तो यह अब कैसे खराब हो गया और इसका खामियाजा गरीब मरीज को क्यों भुगतना पड़ रहा है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था और लोगों से पैसा इकट्ठा करके लगभग 1.36 लाख रुपये जमा करने के बाद उनका डिस्चार्ज हो सका। ये अस्पतालों की स्थिति है।

सभापति महोदय, हम कल की भी एक न्यूज देख रहे थे। नगरोटा-बगवां के पास पालमपुर के एक व्यक्ति की रास्ते में मृत्यु हो गई। वह सुलह क्षेत्र में मनरेगा में दिहाड़ी करता था और उसकी उम्र 60 वर्ष थी। जब उसको अटैक पड़ा तो पहले पालमपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां बताया गया कि इलाज पर लगभग एक लाख रुपये से अधिक का खर्च आएगा। गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्हें टांडा ले जाया जा रहा था। नगरोटा के पास रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। यदि उस समय

26.08.2026/1525/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

हिमकेयर कार्ड चलता और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाता तो संभव था कि उनकी जान बच जाती।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हिमकेयर एक अच्छी योजना थी जिसे पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर द्वार शुरू किया गया था। यदि सरकार को लगता है कि इसका नाम ठीक नहीं है तो नाम बदल दें लेकिन इसे बंद न किया जाए। इसे बंद करने से पूरे क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों की स्थिति भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जोगिन्द्रनगर में मेडिकल ऑफिसर की 19 पोस्टें हैं जिनमें से केवल सात डॉक्टर हैं और 12 पद अभी खाली हैं। रेडियोग्राफर के दो पद हैं और दोनों पद खाली हैं। पैरा मेडिकल की एक पोस्ट है लेकिन उस पर भी कोई कर्मचारी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन चार वर्ष से बंद पड़ी है क्योंकि वहां इसे संचालित करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद वहां यह स्थिति है। मैं

तो कहता हूं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट मण्डी में शायद ही किसी अस्पताल में यह सुविधा चल रही होगी। इसके बाद घटासनी और गुम्मा से लेकर नौली-ब्यूं नोल तक दूर-दूर से लोग वहां इलाज करवाने के लिए आते हैं लेकिन जब वहां इलाज की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो उनके आने का क्या लाभ?

सभापति महोदय, अब सिविल हॉस्पिटल तड़भड़ोल की बात करता हूं। वहां छह पोस्टें हैं जिनमें केवल एक डॉक्टर है। वहां सिर्फ बी0एम0ओ0 की पोस्ट भरी हुई है। स्वीपर के दो पद हैं लेकिन दोनों-के-दोनों खाली हैं। जोगिन्द्रनगर में स्वीपर के पांच पद हैं लेकिन एक भी स्वीपर नहीं है। यह स्थिति सिविल हॉस्पिटल की है। इसके बाद चौंतड़ा की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में तीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और दो सिविल हॉस्पिटल हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सभी पद पूरे भर दें। आप सिर्फ 50 प्रतिशत पद ही भर दें। हम आपसे 65 प्रतिशत की भी मांग नहीं कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने ही 65 प्रतिशत की बात रखी थी लेकिन आप हमारे कम-से-कम 50 प्रतिशत पद ही दें। हम आपसे कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, न हम नया हॉस्पिटल मांग रहे हैं और

26.08.2026/1525/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

न प्राइमरी हैल्थ सेंटर मांग रहे हैं। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि जो पुराना सिस्टम था उसे ही चला दिया जाए।

सभापति महोदय, इससे अधिक अब क्या मांगें? जब मिलना ही कुछ नहीं है तो मांगना क्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि दस बार कहने के बाद भी सिविल हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर रहता है तो क्या हमें 11वीं बार भी यह विषय उठाना चाहिए? यदि इस विषय को बोलने से कोई फायदा नहीं होना है तो फिर हमारे बोलने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा चल रही है। मैंने अपने क्षेत्र के संबंध में कहा कि यदि डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हैं तो मरीजों को रैफर ही किया जाता रहेगा। यदि डॉक्टरों के पद भरे जा सकते हैं तो आगे की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो मरीज इसी प्रकार रैफर होते रहेंगे। आप हमें सदन में बुलाते हैं और हम अपनी बात रखते जाते हैं। अब वैसे सरकार का समय नजदीक ही है जब चार साल में नहीं भरे तो एक साल और देख लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वैस्ट

एन0एस0 द्वारा ... जारी

26.08.2026/1530/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री प्रकाश राणा------जारी

है कि हम सब मिलजुल कर सदन को चलाएं और कम-से-कम अपनी बात यहां रखें। हमारा मैसेज बाहर गलत जा रहा है। यह केवल मेरा नहीं, आपका भी मैसेज बाहर गलत जा रहा है। जनता ने हमें यहां सदन चलाने के लिए चुनकर भेजा है इसलिए हमें इस माननीय सदन को ढंग से चलाना चाहिए। हमें सदन को इस प्रकार नहीं चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाए और हमें अपनी भूमिका निभाने दें तथा हमारा काम मत छीनें।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2026/1530/एन0एस0-वाई0के0/2

सभापति : अब श्री विनोद सुल्तानपुरी जी इस चर्चा में भाग लेंगे। अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी फोन बाहर जाकर सुनें।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं पर नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है उसमे मैं अपने कुछ इश्यूज रखना चाहूंगा। मैं इस चर्चा की शुरुआत माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए करना चाहता हूं। ये कर्नल भी हैं

और डॉक्टर भी हैं। 86 वर्ष की उम्र में हमारे युवा स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। इस प्रदेश को ऐसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पहली बार मिले हैं। इससे पहले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किस तरह की चीजों में लिप्त थे उसकी सभी को जानकारी है। जो सच्चा और पक्का होता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमें कर्नल साहब के ऊपर और इनकी कार्यप्रणाली पर गर्व है। आप हिमाचल के शाइनिंग स्टार हैं।

सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के परवाणू स्थित ई0एस0आई0 हॉस्पिटल से शुरुआत करूंगा। वहां इससे पहले कभी भी 8 से अधिक डॉक्टर नहीं थे। हालांकि, वहां से पूर्व सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी थे। आज वहां 16 डॉक्टर अपनी सर्विसिज दे रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वहां अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लग चुकी है और उसका पूरा उपयोग हो रहा है। ई0एस0आई0 हॉस्पिटल कसौली में भी है और वहां हमें कुछ दिक्कतें आई हैं। उसकी रिपेयर के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। मैंने उसके लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से लगभग 5 लाख रुपये दिए हैं परन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें और राशि लगनी है तो आप उसके लिए हमारी मदद करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चामिया हॉस्पिटल के लिए मंत्री जी ने पैसा दिया था। उसकी लोकेशन ठीक नहीं थी और लगभग 15 वर्ष हो गए परन्तु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जब फ्लड्स आए तो हमें पता चला कि वहां जो स्थान चुना गया था वह गलत चुना गया था। मैं मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने तुरन्त कार्रवाई करते हुए हमें नया स्थान चुनने में सहयोग दिया। वहां 5 बीघे जमीन है और फ्यूचर को देखते हुए हमें बहुत बढ़िया स्थान दिया गया है। उसमें केवल एफ0आर0ए0 के लिए 10 लाख रुपये की राशि लगनी है और इसमें एफ0आर0ए0 का जो

26.08.2026/1530/एन0एस0-वाई0के0/3

प्रोविजन है, पेड़ कटने हैं और उसका यू0सी0 भी है। हालांकि, मैं मानता हूं कि यदि इस प्रकार के संस्थान खुलने हैं तो सरकार के भीतर जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 को परमिशन

मिल जाती है उसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं और एजुकेशन के लिए भी वही व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें सरकार को पैसे नहीं देने पड़ें। मेरा मतलब है कि यदि एफ0आर0ए0 सरकारी बिल्डिंग की है तो इसमें बिना पैसे के भी परमिशन आ जानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीले हो रहा है। यदि आप इसे दुरुस्त करेंगे और इसमें राशि सैंक्शन की जाएगी तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में धर्मपुर हॉस्पिटल है। उस समय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का पड़ोस में हॉस्पिटल था। उन्होंने इसका उद्घाटन भी कर लिया और शिलान्यास भी कर लिया परन्तु वहां पर न तो कोई काम हुआ और न ही कोई पैसा दिया गया। अंतिम वर्ष में 10 लाख रुपये दे दिए। आज मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उस हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपये दिए हैं और मैं चाहता हूं कि उसका शिलान्यास व उद्घाटन भी आप ही करें। आज धर्मपुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन भी लग गई है। हमने वहां 50 बैडिड हॉस्पिटल बनाने का जो सपना संजोया है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और वहां एक मॉडल हॉस्पिटल बनेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को उनके युवा समय में ले जाना चाहूंगा

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

26.08.2026/1535/RKS/Ag-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी....

आप सबाथू में पढ़ाई करते थे। सबाथू मेरी कांस्टिच्यूएंसी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैंने इस संबंध में विधान सभा में एक प्रश्न भी लगाया था और अनुरोध किया था कि वहां स्थित पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में स्तरोन्नत किया जाए। विभाग से प्राप्त उत्तर में यह कहा गया कि वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है कि वहां सी0एच0सी0 खोल दी जाए। परंतु मैं

आपको यह अवगत करवाना चाहूंगा कि सबाथू अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है। आपको वहां के सभी गांवों के नाम मालूम हैं। चाहे सबाथू, रडियाना, ककड़हट्टी, रोड़ी, हरिपुर, पनूह, देलगी, भारती, गंबरपुल, गमजून, जाबली और शरियाना इत्यादि अनेक गांव एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। यदि इस स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत किया जाता है तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपका स्कूल टाइम भी वहीं व्यतीत हुआ है। जब हम गोगामाड़ी मेले में वहां गए थे तब आपने हमारी इस बात को माना था। आप उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस विषय को कंसीडर करने की कृपा करें। इसके साथ ही हमारा एक दयोठी अस्पताल भी महत्वपूर्ण है। यह अस्पताल राजनीतिक कारणों से प्रभावित रहा है। एक डॉ0 साहब सोलन से आते थे जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे और पी0पी0ई0 किट के होनहार चैंपियन थे। उनकी कार्यप्रणाली पर राणा जी को ध्यान देना चाहिए था कि उन्होंने किस तरह के काम किए हैं। उन्होंने यह कार्य तब किया जब पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से ग्रस्त था। ऐसे लोग आज हमें दुहाई देते हैं लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाएं काफी आगे बढ़ी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि दयोठी अस्पताल का निर्माण आपके प्रयासों से ही हुआ है परंतु इसके लिए जिस स्थान का चयन किया गया वहां एंबुलैंस मार्ग की गंभीर समस्या है। देयोठी क्षेत्र के लोगों ने लगभग पांच बीघा भूमि इस अस्पताल के लिए उपलब्ध करवाई थी किंतु राजनीतिक कारणों से इस पूरे अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया। उसी स्थान पर एक सरकारी विद्यालय भी स्थित है। शिक्षा मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। आपने वहां साइंस लैब के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। मेरा सुझाव है कि वर्तमान अस्पताल भवन का डिज़ाइन साइंस लैब के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय से शिक्षा विभाग को प्राप्त धनराशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दें तो हम 1.50 करोड़ रुपये में रोड साइड में नया

26.08.2026/1535/RKS/Ag-2

अस्पताल निर्मित कर सकते हैं ताकि वहां पर एम्बुलेंस के लिए रोड की आवश्यकता न हो। लोगों ने जो हमें जमीन उपलब्ध करवाई है उसके ऊपर हम अच्छा होस्पिटल बना सकते हैं

ताकि वहां ड्राइव-इन पार्किंग सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कोटबेजा अस्पताल है। यह अस्पताल चंडी डिवीजन के अधीन आता है। मेरा आग्रह है कि कसौली कांस्टिच्यूएंसी के सभी अस्पतालों का प्रशासनिक नियंत्रण धर्मपुर से किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई चिकित्सक डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है तो उसे चंडी जाना पड़ता है। यदि अस्पतालों का संचालन कांस्टिच्यूएंसी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा तथा लोगों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह नरियाल में भी एक अस्पताल है जो परवाणू क्षेत्र के साथ सटा हुआ है। हम देख रहे हैं कि हाल ही में डायलिसिस से संबंधित अनेक समस्याएं सामने आई हैं। आपने ई0एस0आई0 अस्पतालों में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं। मेरा आग्रह है कि नरियाल अस्पताल को विशेष रूप से डायलिसिस सेवाओं के लिए विकसित करने पर विचार किया जाए ताकि डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को उपचार पूर्ण होने तक पर्याप्त बैड तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मेरा आग्रह है कि उस अस्पताल को डायलिसिस के लिए असाइन किया जाए ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। इसी प्रकार पट्टाबरौरी में भी स्टाफ की कुछ कमी आ रही है। जंगेशु में हमारा एक हॉस्पिटल है जिसका कार्य अभी पूर्ण होना शेष है। उसके लिए आपने एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बहुत महंगाई कर दी गई है जिसके चलते चिन्नी, तेल और हर चीजें महंगी हो गई हैं। इसके साथ कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी बहुत महंगा हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो दिल्ली से महंगाई बढ़ाई गई है उसे काउंटर करने के लिए

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1540/बी.एस./ए.जी.-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी...

मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें पैसा दें ताकि हमारा जो जंगेशु का हॉस्पिटल है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ...(घंटी)...

सर, जो लेप्रेसेरियम है उसमें भी अभी हमें बड़ी दिक्कतें आने लगी हैं। उसको रिपेयर्स करने के लिए थोड़ा पैसा सैंक्शन करेंगे क्योंकि वहां बहुत लिमिटेड पेशेंट्स हैं। उनको जो सुविधाएं हैं और वहां पानी की जो समस्या है उसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से थोड़ा ध्यान दिया जाए।

जो हमारा धर्मपुर में टी0बी0 सैनिटोरियम है वहां ओवर स्टाफ्ड है। मैं मानता हूं कि वहां जो नर्सिंग स्टाफ है वह बहुत ज्यादा प्लेस्ड है। इसके ऊपर आप कैसे उनको शफल कर सकते हैं क्योंकि वहां जो टी0बी0 के पेशेंट्स हैं वे बहुत लिमिटेड हैं। ओवर स्टाफ्ड होने के बाद हमारे दूसरे एरियाज में जो स्पेसिफिकली नर्सिंग स्टाफ है उसको हम वहां से लिमिटेड करें ताकि बदली के लिए जो इधर-उधर चलते रहते हैं उससे हम अपने एरिया को बचा सकें।

सर, अब बात आती है फेल्योर एम्ज हॉस्पिटल की। हमारे पास कई ऐसे मामले आए हैं। हमारा बिलासपुर हॉस्पिटल है वहां कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो वहां से मरीज रैफर होकर हमारे यहां आई0जी0एम0सी0 आए। आदरणीय जनारथा जी यहां बैठे हैं। ये बता सकते हैं कि किस तरह की वहां मिसमैनेजमैंट हुई है और उसके बाद यहां उनका जो पेशेंट आया उनकी लाइफ ही खत्म हो गई।

बिलासपुर में जो हमारा एम्ज हॉस्पिटल है वहां पार्किंग तक नहीं है। आप वहां कैंटीन में जाएंगे तो पानी की जो कीमत है वह 100-100 रुपये की बोतल है। आज हम 1,500 करोड़ रुपये की बात करते हैं पर इतनी सी बेसिक रिक्वायरमैंट जो लोगों की है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया है।

25.08.2026/1540/बी.एस./ए.जी.-2

अगर हमारी बात यहां से माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली को जाती है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो चंडीगढ़ का हमारा पी0जी0आई0 है उसे और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करें उसे और बढ़िया बेहतर करने के लिए प्रयास करें क्योंकि हिमाचल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग चंडीगढ़ जाते हैं। अगर इस सदन से हम उन तक यह बात पहुंचाते हैं तो मैं समझता हूं कि वह इसके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे।

ऐसे इश्यूज बहुत हैं। हमारा जो टोकन सिस्टम है उसकी रिक्वायरमैंट है। जो अस्पतालों में लाइनें लग रही हैं उनमें से अधिकांश लाइनें मैंने जोनल हॉस्पिटल सोलन में देखी हैं। अगर आप परवाणू जाएंगे सर, वहां टोकन सिस्टम है और बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन हो जाता है कि पेशेंट को कहां जाना है किस डॉक्टर के पास जाना है और कितने टाइम में उनको बुला लिया जाएगा।

मरीज पूरा-का-पूरा दिन दो-दो बजे तक वे वेट करते रहते हैं। यह एक गंभीर मसला है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में सुबह आया है तो कम-से-कम 11.00 बजे से पहले-पहले उसका एलोकेशन हो जाए ताकि उसी दिन उसके टैस्ट हो जाएं और उसका इलाज शुरू हो जाए।

यह हमारी जो डैप्यूटेशन बेस्ड पोस्टिंग है इसको बंद करना होगा। जो गांव में हॉस्पिटल हैं वहां डैप्यूटेशन नहीं होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। जब डॉक्टर वहां से मिसिंग हो जाता है तो पूरा का पूरा गांव और इलाका प्रभावित होता है।

आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि प्राथा में मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर मिसिंग हो गया। सर, हुआ क्या कि उसने आपके साथ एग्रीमैंट किया उसके बाद वह विदेश भाग गया। अब पता चला है कि उसके ऊपर जो आपने एक्शन लिया है क्योंकि आपने जो नया तरीका रियल टाइम ऑन स्पॉट प्रणाली अपनाई है कि कौन डॉक्टर अपने कैंपस से कितना दूर है उससे वह ट्रेस हुआ। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि उस बैकवर्ड एरिया को कोई देखता ही नहीं था। हमारे एक दोस्त हैं उनकी बिटिया को एक सांप ने काट लिया। एंटी

25.08.2026/1540/बी.एस./ए.जी.-3

स्नेक वेनम की दवाई न होने की वजह से उस बच्ची का निधन हो गया। यह बड़ी दुखद बात है और उसका नाम यशपाल है। सर, इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले थी। आज आपने स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडर्नाइजेशन का जो काम किया है और रोबोटिक सर्जरी में जो पहल की है वह सराहनीय है।

ये वही लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। जब कंप्यूटरीकरण होने वाला था तो उस समय ये रथों और घोड़ों पर कैसे-कैसे आ रहे थे। आज हमारे कई साथी कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। हमारा जो नुकसान हुआ था सर, वह भी कंप्यूटर न होने की वजह से हुआ था।

आज हमारे युवा साथी जेन ज़ी ने रियलाइज कर लिया है कि कौन गलत है और कौन सही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पूरे हिमाचल को आपने आशीर्वाद के रूप में जो काम किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पूर्ण हिमाचल की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे हमारे सच्चे - पक्के कर्नल साहब यहां बैठे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1545/DT/AS-1

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र कुमार।

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, हमारे आदरणीय नेता श्री विपिन सिंह परमार, डॉ0 जनक राज जी, श्री पवन कुमार काजल जी तथा श्री नीरज नैय्यर जी जो नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करूंगा कि इस विधान सभा सदन के अंदर हम 68 लोग हैं जो चुनकर आए हैं, इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो दलों के सदस्य हैं। सभी लोग गरीब और सीमांत किसान परिवारों से निकलकर आए हैं तथा हिमाचल की हर परिस्थिति को जानते हैं। हम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में रही है और जो लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। यहां बैठे सभी लोग यह समझते हैं कि प्रदेश की स्थिति कैसी थी, कैसी हो रही है और कैसी जा रही है, यह दुर्भाग्य हमारा है। मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूं और जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि सत्तापक्ष के लोग पूरे प्रदेश में एक फॉल्स प्रोपेगंडा सेटअप करने के लिए या एक नैरेटिव सेट करने के लिए हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अभी मेरे बड़े भाई श्री विनोद सुल्तानपुरी जी बोल रहे थे। युवा वर्ग में हम लोग आते हैं और जो हमारा तरुण वर्ग है यानी वे बच्चे जो अभी बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज जाएंगे, इनकी तरुण अवस्था है, वे समझ चुके हैं औरवे सब जानते हैं। प्रदेश में जो इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं,उनमें से कितने ही लोगों के अकाउंट सरकार के द्वारा बंद कर दिए गये हैं, क्योंकि वे सच बोल रहे हैं। कल हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी कि इनके नजदीक मत रहिए, यह मत कीजिए या वह मत कीजिए।

सभापति : माननीय सदस्य आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही बोलिए।

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। क्योंकि अगर हैल्थ पर बोलूंगा तो कही हमारी ऊपर भी इन्क्वायरी बैठा दी जाए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे पक्ष से सदस्य ने बोलना शुरू किया जैसे यहां पर डॉ0 जनक राज जी हैं, उन्होंने बोला। सदन की विडंबना देखिए। मैंने छात्र राजनीति की है तथा पंचायती राज के अंदर भी कार्य किया है और मैं जानता

26.08.2026/1545/DT/AS-2

हूं कि सदन के नेता जब विपक्ष में थे उस समय किस तरीके से विपक्ष में बातें उठाई जाती थीं, क्या बातें होती थीं? आम जन की बातें, आम लोगों की बातें, आम किसान की बातें और आम मजदूर की बातें। आज ये बातें कहां गईं? आज एक व्यक्ति जो भरमौर से निकलकर

आए, सर्जन बने, हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थान आई0जी0एम0सी0 में एम0एस0 रहे, आज उनके ऊपर आप प्रश्नचिन्ह् लगाने की कोशिश की है। हमारे साथी अगर सरकार के विरूद्ध कुछ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ विजिलेंस इन्क्वायरी करवा जा रही है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जो उनके साथ गए हैं उनके ऊपर भी इन्क्वायरी बैठायेंगे।

सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन बातों को बेस बनाकर कोई भी व्यक्ति हम 68 लोगों चुनकर इस सदन में पहुंचे हैं, जिस बात को बेस बनाकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में या अपने विधान सभा के लोगों के बीच गये, वे बातें हमें यहां आकर नहीं बोलनी चाहिए। सत्ता पक्ष के साथी इस सदन में जैसी बातें कर रहे हैं उसके ऊपर मैं एक शेर के जरीए कुछ बात कहना चाहूंगाः

बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं।
चमन फूलों से खाली कर रहे है, जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी,
वही सब अब (***) कर रहे हैं।छ

माननीय सभापति महोदय मेरा विधान सभा क्षेत्र

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्रीमती पी0बी0द्वारा जारी..

26.08.2026/1550/AS/PB/1

श्री लोकेन्द्र कुमार जारी...

सभापति महोदय, मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र आरक्षित विधान सभा क्षेत्र है। यह शिमला से 123 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर है। हमें विधायक बने हुए चार वर्ष हो गए हैं। सदन में स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चर्चाएं और प्रश्न हुए हैं उनमें हम एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर्ज की मांग करते रहे हैं। आज मैं फिर से वही बातें यहां विधान सभा में रख रहा हूं। आनी के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में एक्स-रे की सुविधा लाई गई है। मैंने पहले भी सदन में यह बात रिकॉर्ड पर रखी थी कि हमारे पास वहां सर्जन, गाइनेकोलोजिस्ट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे। एनेस्थीसिया के डॉक्टर को ट्रांसफर करके चमियाणा ले आया गया और आनी खाली हो गया। वहां सर्जन को बैठाकर क्या करेंगे? वहां बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है और अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। केवल बड़े-बड़े अक्षरों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लिख दिया गया है। मैं हाथ जोड़कर अपनी पूरी जनता की तरफ से एक बार फिर विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय मेरे आनी और निरमंड में स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी हुई है। मेरा विधान सभा क्षेत्र में निरमंड एक आकांक्षी ब्लॉक है और वहां के हालात भी आप देखें। वहां डॉक्टर नहीं है। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आप दो दिन का समय निकालकर एक दिन आनी और एक दिन निरमंड का दौरा करें तथा दोनों जगहों पर जाकर देखें कि स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय, हमें एक्स-रे करवाने के लिए रामपुर पहुंचना पड़ता है। एक मोबाइल एक्स-रे मशीन वहां लाई गई है लेकिन उससे स्पाइन के एक्स-रे नहीं होते हैं तथा कमर से नीचे के एक्स-रे भी नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद आपने बहुत बड़ी-बड़ी सुविधाएं देने की बात कही है। मैं भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए आपको कह रहा हूं कि मैं यहां जो भी बात कह रहा हूं वह पूरी ईमानदारी के साथ रख रहा हूं। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के पड़ोसी विधायक श्री दीप राज जी के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं की यही स्थिति है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उनकी भी पांच-छह पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आनी आते हैं। नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी के विधान सभा क्षेत्र से भी लोग स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आनी आते हैं लेकिन वहां भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। सभापति महोदय,

26.08.2026/1550/AS/PB/2

मैं आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं कि हमारे पिछड़े विधान सभा क्षेत्र और हमारी आरक्षित सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भेदभाव करते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है और ये हमें जाति के आधार पर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये हमसे बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। सरकार के यह हालात है। ...(व्यवधान) मैंने कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की है। हमारे फोन नहीं उठाए जाते हैं। ये 68 लोगों के फोन ही उठा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैं धन्यवाद करता हूं और जिनसे बहुत सारी बातें होती हैं। ...(व्यवधान) मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं वे अपने आप से पूछें और दिल से पूछें कि क्या यह उचित है? मैं और श्री दीप राज जी विधायक चुनकर आए हैं और हमारे साथ अन्य लोग भी चुनकर आए हैं। हम युवा हैं और जोश में कई बार कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन आप यह देखें कि ये लोग क्या करते हैं और कहां जाते हैं। इनके इन्क्वायरी करवाई जाए। यह प्रदेश बदले की भावना के साथ काम करके आगे नहीं बढ़ेगा। हमें यह देखना होगा कि प्रदेश को किस तरीके से आगे ले जाना है।

सभापति महोदय, आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की हालत भी देखिए। यहां मशीनों के बारे में चर्चा की जा रही है कि हमने मशीनें उपलब्ध करवा दी है, यह कर दिया और वह कर दिया है। लेकिन आनी अस्पताल में पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिल रही थी और निरमंड अस्पताल में भी नहीं थी। आर0के0एस0 से दवाइयां खरीदी गई हैं। मैं माफी चाहूंगा लेकिन बोलना मेरा दायित्व है और मैं बोलूंगा चाहे किसी को बुरा लगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें बुरा मानने की बात है। हम प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए यहां चुन कर आए हैं। आनी की जनता के लिए यहां अपनी बात रखना मेरा दायित्व है। मैं चार वर्षों से अपनी बात रख भी रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और कोई बातचीत नहीं की जा रही है। मुझे नहीं पता है कि कौन लोग आ जाते हैं और उनके कहने पर डाक्टर्ज को ट्रांस्फर कर दिया जाता है। डॉक्टर्ज को डेपुटेशन पर कुल्लू भेज दिया जाता है और कभी कहीं डेपुटेशन लगा दी जाती है। मेरे यहां श्री जय राम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र से लगती हुई एक पंचायत है। सरहैगार में पी0एच0सी0 खोली गई थी, जिससे

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1555/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री लोकेन्दर कुमार जारी .....

वहां की पंचायतों के लोगों को भी इसका फायदा मिलता था। आदरणीय जय राम ठाकुर जी के क्षेत्र के लोग भी वहां चेकअप के लिए आते थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। जबकि वहां 50-से-100 तक की ओ0पी0डी0 होती थी। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको दोबारा नोटिफाई करें। हमारे कई सब-सेंटर हैं। दोगराह में सब-सेंटर खुला, रोहड़ीधार में सब-सेंटर खुला, डीम में सब-सेंटर खुला, दूगा शिघाण में सब-सेंटर खुला और टिकरीदढ़ में भी सब-सेंटर खोला गया। ये सभी सब-सेंटर आदरणीय जय राम ठाकुर जी के समय में हमें मिले थे। परन्तु जैसे ही सरकार आई इन सब-सेंटरों को बंद कर दिया गया। डीम मेरी आखिरी पंचायत और आखिरी गांव भी डीम में ही है। वहां सब-सेंटर इसलिए खोला गया था कि लोगों को जुकाम-बुखार होने पर दवाइयां मिल सकें, लेकिन वह भी बंद कर दिया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे सब-सेंटर और पी0एच0सी0 को बहाल करें, उनको नोटिफाई करें। साथ ही जो मेरे आनी अस्पताल की दुर्दशा है, उसको भी सुधारा जाए क्योंकि वह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि निरमंड, जिसमें 34 पंचायतें हैं और जो एक नगर पंचायत है। निरमंड ब्लॉक के अंदर हमारी जो सी0एच0सी0 है उसको भी सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दे ताकि वहां भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही, अरसू का क्षेत्र भी निरमंड के अंदर आता है। वहां जो पी0एच0सी0 है उसमें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नित्थर भी हमारे पास है। मैंने पहले भी सदन में कहा है कि 35 साल आदरणीय ईश्वर दास जी ने इस सदन के अंदर आप लोगों के साथ काम किया है। आज भी नित्थर के अंदर स्वास्थ्य की बहुत दुर्दशा है। मैं चाहूंगा कि नित्थर के स्वास्थ्य संस्थान, पी0एच0सी0 को भी दुरुस्त किया जाए। वहां दवाइयां मिलें, डॉक्टर बैठें और हर चीज की सुविधा वहां उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा दलाश का अस्पताल है। दलाश अस्पताल की बिल्डिंग हमारी तैयार हुई है, वहां भी हमें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पिछली सरकार में आदरणीय

जय राम ठाकुर जी ने 66 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से हमारे अस्पताल का कार्य शुरू करवाया था। उसमें 16 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं। 16 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाई है। साथ ही मौजूदा सरकार ने 6 करोड़ रुपये

26.08.2026/1555/डी0सी0/ए0पी0-02

अधिकारियों और कर्मचारियों के रेजिडेंस बनाने के लिए दे दिए हैं, जबकि अस्पताल की बिल्डिंग अभी पूरी नहीं बनी है। मैं माननीय सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उस बिल्डिंग का काम समय रहते पूरा करें। जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी आए थे तो बहुत सारी बिल्डिंग के उद्घाटन हुए। मेरी एक आई0टी0आई0 की बिल्डिंग है जिसमें आज तक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि रंग रोगन हो चुका है, अगर दौरें होंगे तो उद्घाटन भी होंगे, पट्टिकाएं भी लगनी चाहिए। ऐसी पट्टिका न लेगे कि वहां न मरीज जा पाए, न अटेंडेंट जा पाए और न डॉक्टर रह पाए। सभापति महोदय, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं। यह दिनांक 7-8-2026 की नोटिफिकेशन और ऑफिस ऑर्डर है। ये डॉक्टर कुणाल शर्मा जी हैं, जिनको चमियाणा में 34 हजार रुपये नौकरी पर रखा गया है। करोड़ों रुपये खर्च करके माता-पिता, जो किसान परिवारों और मजदूर परिवारों से आते हैं, अपने बच्चों को एम0बी0बी0एस0 करवाते हैं। मेहनत करके वे डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, बड़े डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद यह व्यवस्था परिवर्तन की सरकार 34 हजार रुपये महीने पर डॉक्टर रख रही है। इस सरकार के हालात और देखिए। पहले किसी आई0एफ0एस0 अफसर को दूध के क्षेत्र में काम करने के लिए लगा दिया और अब हमारे अच्छे अधिकारी हैं, जिनके पास सचिव का कार्यभार है, उनके ऊपर एडवाइजर आई0एफ0एस0 अधिकारी रख दिए गए हैं। जंगल का काम स्वास्थय देखेंगे, स्वास्थ्य का काम जंगल वाले देखेंगे और दूध का काम पुलिस वाले देखेंगे। इस तरह के हालात हैं, यही है व्यवस्था परिवर्तन है। यह सरकार की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन है। माननीय सभापति महोदय, निरमंड में अस्पताल है। बात करते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा या कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि निरमंड अस्पताल के पीछे डंगे का काम चल रहा है। लगभग 90 लाख रुपये का काम आपका विभाग करवा रहा है। कहा गया था कि वहां मेंटेनेंस होगी, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो गई है। अभी दो-चार

दिन पहले बारिश हुई। डंगा लगे हुए दस दिन भी नहीं हुए थे और वह गिर गया। अभी उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है। जो आगे डॉक्टर रेजिडेंस है और वहां कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए पूरा खतरा बन गया है। निरमंड अस्पताल में थर्ड क्लास एम्प्लॉयी भी नहीं हैं। सब लोगों को खुद ही काम करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन सबसे पहले मैं आपको न्यौता देना चाहता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.08.2026/1600/AT/DC/01

श्री लोकेन्दर कुमार जारी....

कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में आएं और वहां की हालत देखें कि हम किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे हैं। बड़े-बड़े साथी सब बात कर रहे हैं कि हमारा यह अच्छा हो गया, यह वैसा हो गया, यहां हमारे डॉक्टर आ गए, यहां हमारा सी0टी0 स्कैन हो रहा है, यहां हमारे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, यहां हमारे रोबोट आ गए हैं, यहां हमारे ये काम हो रहे हैं।

आप मुझे बताइए, आनी विधान सभा क्षेत्र यहां से दूर नहीं है, यहां से केवल तीन घंटे का रास्ता है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी वहां आएं हैं और उनहोंने वहां की हालत देखी कि क्या है। तीन घंटे की दूरी पर जो अस्पताल हैं, उनकी हालत क्या है अभी भी बोल रहे थे कि आप हमें प्रूफ देंगे कि मंगलसूत्र किसने बेचा। मुझे कल मेरे विधान सभा क्षेत्र से फोन आया कि वहां एक महिला एडमिट थी और उसका एमकेयर कार्ड नहीं चल रहा था। जितनी मेरी ओर से मदद हो सकती थी, मैंने की। यहां सुरेश जी नहीं हैं, हम भी सब लोग मदद करते हैं केवल वे ही नहीं मदद करते हैं और यहां बैठे विपक्ष के लोग भी मदद करते हैं और जितनी हो सकती है उतनी मदद करते हैं।

सुबह डॉक्टर जनक जी के माध्यम से हमने फिर एंबुलेंस भेजी। पंद्रह किलोमीटर पर रुपये के इसाहब से एंबुलेंस जाती है। उन्हें थोड़ा सा कंबल रेट कर के एंबुलेंस भेजी।

Chairman: Hon'ble Member, please windup.

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र का दर्द बयां कर रहा हूं। हमें चार साल से बोलते-बोलते थक गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि युवा और तरुण, जब बोलना शुरू कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर दिए हैं और आगे हमारे अकाउंट बंद करेंगे, हमारे फेसबुक पेज बंद करेंगे। ये हालात हैं सरकार के, जो दावा कर रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया है। पर सच्चाई यह है कि जो गरीब है, किसान है, मजदूर है और जो

26.08.2026/1600/AT/DC/02

गाय पालकर मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके इलाज के लिए आज एमकेयर कार्ड नहीं चल रहा है, आयुशमान कार्ड नहीं चल रहा है।

सभापति महोदय, इसलिए मैंने अपने निरमंड, अरसो, निथर, आनी, दलाश और जो सब-सेंटर हमारे बंद हुए हैं, मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से मुख्य मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्थान आपने डिनोटिफाई किए हैं, उनको नोटिफाई करें और जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आनी को बनाया गया है, उसमें पूरी सुविधाएं दें। अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी दें, डॉक्टर भी भेजें और रेडियोलॉजिस्ट भी भेजें। ये सब चीजें करें। निरमंड का जो हमारा अस्पताल हैं, उनको भी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के लिए घोषित करें । यह कौन अंदर आएगा, कौन बापिस जाएगा,...(व्यवधान)

Chairman: Hon'ble Member, please windup.

श्री लोकेन्दर कुमार: ये डॉक्टर की सैलरी 34 हजार रुपये है, सर, इसके ऊपर भी थोड़ा देखें। करोड़ों रुपये मां-बाप ने लगाए हैं।

मैं एक और बात बोल देता हूं और हमारे पास कागज भी है। पी0जी0आई0 के अंदर चार लोग आपने हिमकेयर के लिए बिठा रखे हैं। हम जानते हैं कि कौन लोग बिठाए हैं आपने। 90-90 हजार रुपये की सैलरी पर बिठाए हैं और हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन है।

सभापति महोदय, बोलने को बहुत सारी बातें हैं। मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग भी मेहनत करने के बाद यहां पहुंचे हैं, लोगों की लड़ाई लड़कर यहां पहुंचे हैं। जनता की लड़ाई के लिए आगे भी सबसे आगे खड़े रहेंगे, तब यहां पहुंचेंगे। यह सत्तापक्ष के लोग तय नहीं करेंगे कि हम कैसे यहां आएंगे।

मैंने पहले कहा कि हम सब लोग और यहां बैठे 68 लोग आम गरीब निम्न परिवारों से निकलकर आए हैं। अपने आप को यहां पहुंचकर यह न समझें कि जनता पूछने वाली नहीं है। जनता पूछेगी कि क्या हालात हैं। इसलिए, सभापति महोदय, चंद लाइनों के साथ

26.08.2026/1600/AT/DC/03

तू कर संग्राम, ऐ साथी, तू कर संग्राम, ऐ साथी,
घड़ी संकट की आई है।
न फौजों की, न सरहद की,
ये हिमाचल प्रदेश को कांग्रेसियों से बचाने की लड़ाई है।छ

धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय आनी। धन्यवाद।

सभापति : जो माननीय सदस्य ने पिछला शेर बोला था और उसमें बोला था कि (***)कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।

अब माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा जी इस चर्चा में भाग लेंगे ।

26.08.2026/1600/AT/DC/04

श्री विवेक शर्मा : माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव विपिन सिंह परमार जी द्वारा लाया गया है, मैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तीन दिन से लगातार चर्चा चल रही है और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने यहां पर अपने-अपने विचार रखे है। मैं, सभापति महोदय, एक चीज कहना

चाहूंगा कि आज जो सरकार काम कर रही है और इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी काम किया होगा। मगर एक चीज जरूर है कि अगर विपक्ष के समय में आज हेल्थ के ऊपर बात की जा रही है और जो आज काम यहां पर हुए हैं, उनके ऊपर जब चर्चा की जा रही है

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1605/av/hk/1

श्री विवेक शर्मा (विक्कू)-------जारी

उनके ऊपर जब चर्चा की जा रही है तो विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि पिछली बार सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार थी। उस समय अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं तो आज हमें शायद इतना जोर-जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए मैं भी अपने ही निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहकर बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार 32 वर्षों तक केवल एक ही राजनीतिक विचारधारा का नेतृत्व रहा। वहां पर बी0एम0ओ0 ऑफिस मेरे पिता जी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985-90 के बीच में बना था। वहां थानाकलां में बी0एम0ओ0 ऑफिस था। वहां 32 वर्षों में हमने केवल धरने-प्रदर्शन किए। पहले वहां पर एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर से ऊपर कोई डॉक्टर तैनात नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त वहां पर ब्लड टैस्टिंग मशीन, एक्स-रे मशीन और दूसरे इक्विपमैंट्स इत्यादि कुछ नहीं होता था। मगर मैं आज माननीय मुख्य मंत्री सहित माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया। वहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर्ज की नियुक्ति करने के बाद उस होस्पिटल में ब्लड टैस्टिंग मशीन, एक्स-रे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई। मैं सदन के समक्ष यह भी बताना चाहूंगा कि अभी 15 अगस्त को हमारे उस होस्पिटल में नियुक्त डॉक्टर को अवार्ड भी दिया गया क्योंकि वहां पर चार महीनों में 2000 से ज्यादा

अल्ट्रासाउंड किए गए। इसलिए सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया गया। अभी थानाकलां में भी अल्ट्रासाउंड और ब्लड टैस्टिंग की मशीन्ज लगाई गईं। मगर हैरानी तब होती है जब होस्पिटल्ज में डॉक्टर्ज की नियुक्ति लगातार हो रही है और विपक्ष की ओर से इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। सरकार की ओर से 590 डॉक्टर्ज रखे गए तथा 416 अगले क्रम में रखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पिछले तीन-साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर लगभग 4600 लोगों को नियुक्ति दी गई। यहां पर बार-बार बात की जा रही है कि डॉक्टर्ज और मशीन्ज नहीं हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीजें क्या पिछले तीन वर्षों में हुई हैं? तीन वर्ष से पहले जो यहां पर सरकारें रहीं, उनके कार्यकाल में यहां पर कितने-कितने डॉक्टर्ज रखे गए, विपक्ष के लोगों को उसका जवाब भी देना चाहिए। यहां पर

26.08.2026/1605/av/hk/2

जिनके माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया है, वे इस प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपने समय में परिवर्तन करने की कोशिश की होगी। मगर 590 डॉक्टर्ज जो हमारी सरकार के तीन-साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में लगे हैं, ये भी हमारे प्रदेश में ही लगे हैं, कहीं दूसरे राज्य में तो नहीं लगे हैं। यह भी सही है कि यहां सदन में बैठे माननीय सदस्यों के बच्चे भी डॉक्टर होंगे। आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक डॉक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वे आगे एम0डी0 या एम0एस0 करने के लिए जाते हैं जिसकी वजह से किसी होस्पिटल में यदि आज 5-6 डॉक्टर्ज हैं तो वे आगे दो भी रह जाते हैं। मगर डॉक्टर्ज की लगातार नियुक्ति हो रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हो रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में जिस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज यहां पर उस रोबोटिक सर्जरी की बात की जा रही है। परंतु विपक्ष के लोग इसका भी बार-बार मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताना चाहता हूं। मैं किसी गांव में जा रहा था और मैंने वहां के एक व्यक्ति को कहा कि आपको बधाई हो, आपके यहां तो पुल बन गया। उसने बोला कि इससे क्या फर्क पड़ा, पहले पुल के नीचे से जाते थे और अब ऊपर से

जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर विकास को विकास की नज़र से न देखकर केवल विरोध करने की कोशिश की जा रही है। जबकि रोबोटिक सर्जरी, जो आज हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक कल्पना थी कि कोई इस प्रकार की सर्जरी भी होती है। अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि बताया ही नहीं और बिना बताए 30 हजार रुपये की सर्जरी कर दी। ऐसा कभी होता है

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1610/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री विवेक शर्मा(विक्कू) ....जारी

अभी मेरे साथी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि मरीज के साथ आए व्यक्ति को बताए बिना 30 लाख रुपये की सर्जरी कर दी गई। ऐसा कभी नहीं होता कि मरीज के साथ आए व्यक्ति को उसकी बीमारी तथा किए जाने वाले इलाज के बारे में बताए बिना इलाज कर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं होता है।

सभापति महोदय, हॉस्पिटलों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यहां ऐसे कितने लोग हैं जो अपने-अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल में जाकर दौरा करके देखते हैं कि वहां क्या उपलब्ध है और क्या उपलब्ध नहीं है? केवल मात्र चर्चा की जा रही है। मैं नहीं समझ सकता कि आज हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां उसकी फार्मेसी में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। आज हमने अपने क्षेत्र में सिविल सप्लाई की दुकानें तक खोली हैं और लोगों को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में छह काउंटर सिविल सप्लाई की दवाइयों के खोले गए हैं। अम्ब, बड़सर और बंगाणा में काउंटर खोला गया है। इसके अलावा तीन अन्य काउंटर भी खोले गए हैं। हॉस्पिटलों में रिलेक्सेशन के अंतर्गत दवाई मिल रही है। आपके अपने काउंटर पर भी दवाई उपलब्ध हो रही है। आज ऊना में हाई टेक मशीनरी के साथ एच0एस0 लैब के माध्यम से टेस्टिंग मशीनरी आ रही है। मेरे थानाकलाँ में ब्लड बैंक खोलने की सरकार ने

घोषणा की है और उसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे कह दें कि काम नहीं हो रहा है?

सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज हैल्थ के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक सुधार हुआ है। आज सी0एच0ओ0 और नर्सों को भी नियुक्त किया गया है। यदि यह स्टाफ पहले से उपलब्ध होता तो आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पूर्व की सरकारों द्वारा यह स्टाफ रखा गया होता तो शायद आज इन नियुक्तियों की आवश्यकता न पड़ती। आज हम देख रहे हैं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने के बाद जहां एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर बैठता था वहां आज एम0डी0 डॉक्टर बैठ रहा है। आज वहां हार्ट स्पेशलिस्ट तथा हार्ट के डॉक्टर बैठ रहे हैं और हर प्रकार के डॉक्टर की सुविधा लोगों को मिल रही है।

26.08.2026/1610/टी0सी0वी0/एच0के0-2

आज ऐसे क्षेत्रों में भी डॉक्टर तथा एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध हो रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यहां डॉक्टर आएंगे और एक्स-रे मशीन लगेगी। यह ठीक है कि हमारे पास अभी अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त स्टॉफ नहीं हैं। लेकिन क्या आपके ध्यान में ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी में हैं? यदि ऐसे लोग बेरोजगारी की सूची में हैं तो आप सरकार को बताएं। सरकार स्वयं कह रही है कि हमें मशीनों को ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए। इसलिए ये सारी बातें केवल अपने क्षेत्र के लोगों को यह बताने के लिए की जा रही हैं कि हम बहुत आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे यहां लगातार 32 वर्ष तक भाजपा के विधायक रहे हैं और 32 वर्षों में कुटलैहड़ में टेस्टिंग मशीन नहीं आई। आज हमने दो वर्षों में सरकार के माध्यम से वहां टेस्टिंग मशीनें और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करवाई है और हाई टेक ब्लड टेस्टिंग मशीनें भी उपलब्ध हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो क्या आज कोई डॉक्टर ऐसा है जो बेरोजगार घूम रहा है? लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और सरकार हर हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में कैंटीनें नहीं थीं। आज हॉस्पिटलों में कैंटीनें खोली जा रही हैं।

हॉस्पिटल में सुइयां तथा कॉटन उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि हम लगातार अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, सरकार काम कर रही है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी आज उपचार हो रहा है। आज लोगों को इसके बारे में बताया भी जा रहा है। जिन लोगों को पहले यह पता नहीं चलता था कि उन्हें कौन-सी बीमारी है उन्हें आज उनकी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। टीबी के बारे में आज घर-घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां टीबी के ऊपर इतना काम किया गया है कि आज हम जीरो प्रतिशत पर पहुंच चुके हैं।

सभापति महोदय, अतः मैं अधिक न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में हैल्थ की दृष्टि से मुख्य मंत्री की सोच के साथ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हैल्थ मिनिस्टर भी लगातार इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं और आने

26.08.2026/1610/टी0सी0वी0/एच0के0-3

वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है और जिस प्रकार परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे लगता है कि हम हैल्थ के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

सभापति : अब श्री माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री डी0एस0 ठाकुर **एन0एस0 द्वारा ... जारी**

26.08.2026/1615/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री डी0एस0 ठाकुर : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव माननीय विपिन सिंह परमार जी इस माननीय सदन में लेकर आए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं आज प्रदेश और विशेषकर जिला चम्बा की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अनेक योजनाएं दी हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवारों, गरीब परिवारों के 22 लाख लोग इसके दायरे में हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश और विशेषकर जिला चम्बा के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, टी0बी0, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की जांच एवं उपचार सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हैल्थ आई0डी0 के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को सस्ती जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाकर उपचार का खर्च कम किया जा रहा है।

प्रदेश में पूर्व श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमकेयर योजना शुरू की थी जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत के दायरे से बाहर रह रहे परिवारों को भी 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया था। जिला चम्बा के मेडिकल कॉलेज के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज, चम्बा में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सरोल स्थित नए भवन में ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है और उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए

आवश्यक सभी पद शीघ्र सृजित किए जाने चाहिए। वहां ऑक्सीजन प्लांट लगना भी बहुत जरूरी है। सरोल स्थित नए भवन में वर्तमान में केवल

26.08.2026/1615/एन0एस0-ए0जी0/2

ओ0पी0डी0 सेवाएं ही मरीजों को दी जा रही हैं। पुराने भवन और नए मेडिकल कॉलेज, चम्बा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। पुराना मेडिकल भवन 46 वर्ष पुराना है और जगह की कमी के कारण कई बार एक बैड पर दो-दो और तीन-तीन मरीजों को उपचार के लिए एडमिट किया जाता है।

सभापति महोदय, इसकी खबर अखबार में भी आई थी। (माननीय सदन में कागज दिखाते हुए) कि एक बैड पर तीन-तीन पेशेंट मेडिकल कॉलेज, चम्बा में रखे गए हैं और अपना उपचार करवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, चम्बा की यह हालत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वे कैसे ठीक होंगे? अभी हाल ही में मिंजर मेले के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी चम्बा आए थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरोल में नए मेडिकल कॉलेज का उद्‌घाटन किया। वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष चम्बा से संबंध रखते हैं और माननीय श्री नीरज नैय्यर भी उनके साथ थे। उन्होंने इसकी ओपनिंग तो करवा दी परन्तु हमारा मेडिकल कॉलेज, चम्बा पुराने सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। वहां आपने ओ0पी0डी0 तो चला दी है लेकिन वहां पूरा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि चम्बा की लगभग साढ़े पांच लाख जनता को लाभ हो क्योंकि चम्बा और आसपास के क्षेत्रों के लोग वहां स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं और उनको उपचार की सुविधा मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग भी उपचार के लिए चम्बा आते हैं। सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था नहीं की है। मेडिकल कॉलेज वहां शिफ्ट होना चाहिए। अब यहां अध्यक्ष महोदय होते तो मैं उनके ध्यान में भी यह बात लाता परन्तु वे सुन तो रहे होंगे।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

26.08.2026/1620/RKS/Ag-1

श्री डी0 एस0 ठाकुर जारी...

ऐसी व्यवस्था में मेडिकल कॉलेज का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से विशेष निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज की सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज सरोल में स्थानांतरित की जाएं ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। मुझे आशा है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस संस्थान को स्थानांतरित करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। चंबा में डायलिसिस सुविधा के लिए वर्तमान में केवल 20 बिस्तरों की ही व्यवस्था हैजबकि वहां डायलिसिस के लगभग 100 पेशेंट हर रोज आते हैं। ऐसी स्थिति में अनेक पेशेंट्स को टांडा या पठानकोट जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि नागरिक अस्पताल, चंबा में 100 बैड की व्यवस्था की जाए ताकि चंबा से हमारे क्षेत्र के पेशेंट्स को डायलिसिस करवाने के लिए टांडा या पठानकोट न जाना पड़े। इस विषय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज चंबा में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी भी एक गंभीर चिंता का विषय है। वहां 65 प्रतिशत डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं जोकि गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टरों की कमी के साथ-साथ दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है ताकि मरीज़ों को उपचार के लिए बाहर टांडा या पठानकोट न जाना पड़े। डलहौजी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के संदर्भ में मैंने आपको चम्बा अस्पताल की हिस्ट्री पहले ही बता दी है कि उसका उद्घाटन अधूरी व्यवस्था के साथ किया गया था। हमारे मेडिकल कॉलेज सलूणी के भवन निर्माण के लिए पूर्व सरकार के समय वर्ष 2022 में 11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2023 में उस भवन का टैंडर भी हो गया किन्तु वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2026 तक केवल साइट डवलपमैंट का कार्य ही हुआ और भवन निर्माण का कोई कार्य आरम्भ नहीं हो पाया। उस भवन के लिए11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। अतः मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करवाया जाए ताकि हमारे दूर-दराज क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। उस भवन के लिए धनराशि जारी कर दी गई है लेकिन सरकार उसका कार्य नहीं करवा रही है। मेरा मानना है कि सरकार का ध्यान सलूणी अस्पताल की ओर बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार उस कार्य को करने में

असमर्थ है तो उस भवन का निर्माण कार्य बी0एस0एन0एल0 एजेंसी को दिया जाए ताकि वह भवन शीघ्र तैयार हो सके।

26.08.2026/1620/RKS/Ag-2

...(व्यवधान) आपने तो हमारा मेडिकल कॉलेज ही डी-नोटिफाई कर दिया है।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया एक मिनट बैठ जाइए क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं कहना चाहूंगा कि उस भवन में दो बार मलबा आया है which I could make out. Although, I had not visited the site लेकिन मैंने चम्बा होस्पिटल का विजिट जरूर किया है। **लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि उस अस्पताल का निर्माण जरूर होगा। जब वहां कार्य शुरू हुआ तो वहां बहुत सारा मलबा आ गया था as a result, we are looking for an alternative site और वह प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। हम शीघ्र ही यह कार्य आरम्भ करवा देंगे।**

सभापति : माननीय सदस्य, श्री डी0एस0 ठाकुर।

श्री डी0 एस0 ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं उस क्षेत्र का विधायक हूं और कई बार उस स्थल का दौरा कर चुका हूं। ऊपर से कुछ मलबा अवश्य आया था जिसके कारण ब्रेस्ट वॉल में लगभग दो इंच का गैप आया था लेकिन बाकी तो बहानेबाजी ही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा इस भवन के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। सरकार इस भवन का निर्माण नहीं करवाना चाहती है। मैं सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उस भवन निर्माण का कार्य बी0एस0एन0एल0 एजेंसी को दिया जाए ताकि इसका निर्माण शीघ्र पूरा हो सके। नागरिक अस्पताल सलूणी-किहार में 6 डॉक्टरों के पद

रिक्त पड़े हुए हैं। पूर्व जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय हर माह के एक मंगलवार को डॉक्टरों के वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाते थे।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1625/बी.एस./ए.एस.-1

श्री डी0एस0 ठाकुर जारी...

पिछली आदरणीय जय राम जी की सरकार में हर महीने एक बार मंगलवार को डॉक्टरों के इंटरव्यू होते थे और सैकड़ों डॉक्टर पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाए गए थे। सलूणी के सिविल हॉस्पिटल के लिए 8 डॉक्टर लगाए गए थे। केहार सिविल हॉस्पिटल के लिए 8 डॉक्टर और ढलौजी हॉस्पिटल के लिए 15 डॉक्टर अदरणीय जय राम जी की सरकार ने दिए थे।

जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई हमारे डॉक्टरों की संख्या जो 50 थी वह कम होकर 20 रह गई। सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि सलूणी में डॉक्टरों के जो 25 पद खाली हैं उनको भरा जाए। इसके साथ ही ढलौजी, बाथरी, सुंडला, सलूणी और केहार में डॉक्टरों के जो पद खाली हैं उनको भी भरा जाए।

सभापति महोदय, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी हमारे विधान सभा क्षेत्र में ढलौजी में पूर्व में आदरणीय जय राम जी की सरकार द्वारा जो पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 दी गई थीं उनको डी-नोटिफाई कर दिया गया। यह दूर-दराज का क्षेत्र है और यह क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर का अंतर है। आप जानते हैं कि ढलौजी की स्थिति क्या है और वहां हमारा भद्रवाह बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र जम्मू-कश्मीर से लगता है और हमारी पॉप्युलेशन सवा लाख के करीब है। पी0एच0सी0 बढ़ेला को डी-नोटिफाई कर दिया गया, पी0एच0सी0 करवाल को डी-नोटिफाई कर दिया गया और टप्पर में जो सब-सैंटर था उसको भी डी-नोटिफाई कर दिया गया। जी0बी0 पधरोती में जो सब-सैंटर खोला गया था उसको भी डी-नोटिफाई कर दिया गया। नडल पंचायत में जो

सब-सैंटर खोला गया था वह हमारी सबसे इंटीरियर पंचायत है उसको भी डी-नोटिफाई कर दिया गया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा ढलौजी विधान सभा क्षेत्र 150 किलोमीटर की लंबाई में है। अगर पूरे विधान सभा क्षेत्र की बीच वाली लिंक रोड को शामिल करें तो इसकी दूरी 300 किलोमीटर तक पड़ती है। इस परिस्थिति में हमारे जितने संस्थान डी-नोटिफाई किए गए हैं उनको नोटिफाई किया जाए ताकि वहां के दूर-दराज क्षेत्र की जनता को उनका लाभ मिल सके।

25.08.2026/1625/बी.एस./ए.एस.-2

इसके साथ ही अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों के जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में स्टाफ की कमी है, स्टाफ नर्सों की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है और फार्मासिस्टों की कमी है। लगभग 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हुए हैं। उन सभी पदों को भरा जाए ताकि हमारी जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25.08.2026/1625/बी.एस./ए.एस.-3

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हेल्थ पर जो चर्चा माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी अपने साथियों के साथ लेकर आए हैं। आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने इधर से भी और उधर से भी कही है। विपक्ष में जो वक्ता बोलने वाले हैं उनमें से ज्यादातर जिला मण्डी से हैं और वे चिल्ला-चिल्लाकर यह बात हमेशा रख रहे हैं कि जिला मण्डी में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। डॉक्टरों और हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। मैं जिला मण्डी के लिए

स्पेशली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वे पहले वहां से मुख्य मंत्री रहे हैं।

क्या ये हालात साढ़े तीन साल में हुए? इससे पहले पांच साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, हमारे आदरणीय लोकेन्दर कुमार जी बोल रहे थे कि आनी में डॉक्टर नहीं हैं। बिल्डिंग नहीं है और स्टाफ नहीं है। तो आपने पिछले पांच वर्ष में क्या किया?

मैं इस सदन के माध्यम से यह बात पूछना चाहूंगा कि आज जो चीजें यहां बताई जा रही हैं और जो समस्याएं गिनाई जा रही हैं उन पर पिछले पांच वर्ष में आपने के द्वारा क्या काम किया गया था? जो ये बातें सामने आ रही हैं। आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी। मुख्य मंत्री जी ने जब प्रदेश की कमान संभाली थी तो आप लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गए थे। उस समय हालात कैसे थे? उसके बावजूद आज स्वास्थ्य विभाग में मुख्य मंत्री जी ने महत्वपूर्ण योगदान देकर इसे आगे बढ़ाने का काम किया है और

.... श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1630/DT/AS-1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी...

स्वास्थ्य विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो 86 वर्ष की आयु के एक युवा मंत्री हैं, मैं समझता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यह चाहते हैं पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य भी इनकी तरह ही रहे और इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में यह आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि सभी की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी इन्हीं की तरह रहनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग को अच्छी तरह चलाने के लिए भी इनका धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आज इसलिए भी आश्चर्य चकित हूं कि विधान सभा के अंदर आज चर्चा भी वहीं लेकर आएं हैं जब पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में कोराना जैसी महामारी

फैली थी जिनके समय प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले होते रहे, वही लोग आज स्वास्थ्य सेवाओं में चर्चा मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी को इस विषय पर बात करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र चिंतपुर्णी में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो मेरा सिविल हॉस्पिटल, अम्ब है, जब विधायक बनने के बाद मैं पहली बार इस हस्पताल में रोगी कल्याण समिति की मीटिंग में गया तो मुझे पता चला की पूर्व की सरकार में उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे वे अम्ब विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने गंभीर थे।

जब मैंने आर0के0एस0 की बैठक ली तो मैंने बी0एम0ओ0 से पूछा कि इससे पहले यह बैठक कब हुई थी? उन्होंने बताया कि इसकी तीन वर्ष से बैठक ही नहीं हुई। यह बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें आप पूरे हॉस्पिटल का बजट तय करते हैं, डाक्टर के कितने पद रिक्त हैं और कौन से डाक्टर का पद खाली है, कितनी स्टॉफ नर्सिज हैं, कौन सी मशीन की यहां पर आवश्यकता है, इस बारे में इस बैठक में चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण बैठक तीन वर्ष से वहां नहीं हुई थी। जब मैंने वहां जाकर उस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो मुझे पता चला कि उस हस्पताल में केवल 6 डाक्टर्ज ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई थी और जब मैंने पूछा कि क्या अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है तो उन्होंने जवाब

26.08.2026/1630/DT/AS-2

दिया कि जब इस अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्‌घाटन हमारे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने इसका उद्‌घाटन किया था और उससे केवल एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ था। मैंने पूछा कि किसका अल्ट्रासाउंड हुआ था? उन्होंने कहा कि हमारे माननीय विधायक का ही हुआ था। उसकी रिपोर्ट क्या आई यह तो उन्होंने मेरे साथ सांझा नहीं की परंतु उसके बाद मशीन बंद कर दी गई।

हमने उस समय उस मशीन के लिए डॉक्टर पोस्ट किया और लगभग साढ़े चार सौ महिलाओं तथा प्रेग्नेंट महिलाओं का अल्ट्रासाउंड वहां करवाया। पहले उस अल्ट्रासाउंड

को करवाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र में एक हजार रुपये लगता था अब वह इस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। उसके छह महीने बाद जब हम फिर आर0के0एसव की बैठ की तो उन्होंने मुझसे डिमांड की कि हमें अपनी निधि से पांच लाख रुपये दिए जाएं क्योंकि जो मशीन वहां पर लगी थी वह बहुत पुरानी हो गई थी और वह खराब भी हो गई है। हमें नई मशीन चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि नई मशीन तो हम दे देंगे लेकिन इसकी गारंटी क्या है तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने उनको मना किया और कहा कि हम नई मशीन रिपेयर नहीं करवाएंगे बल्कि नई मशीन लेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की। हमें एक नहीं बल्कि दो नई अल्ट्रासाउंड मशीनें मिलीं। 25-25 लाख रुपये की लागत से एक मशीन अम्ब हॉस्पिटल के लिए और एक चिंतपुर्णी हॉस्पिटल के लिए हमें मिली। आज वहां अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। जब मैं वहां गया था तो केवल चार डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैंने वहां डॉक्टर से बात की। वहां डेढ़ सौ की ओ0पी0डी0 थी और बी0एम0ओ0 ने बताया कि हमें महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी गाइनेकोलोजिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आशीर्वाद से वहां उनकी नियुक्ति करवाई।

इसके साथ-साथ जब पता चला कि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी आवश्यकता है तो हमने बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी नियुक्ति करवाई। इसके साथ-साथ वहां आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति हुई और उसके बाद जनरल सर्जन तथा एनैस्थिीया के डॉक्टर भी वहां आए। आज हमारे अम्ब हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

26.08.2026/1630/DT/AS-3

आज मैं हमारी सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल और विपक्ष के पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीरता रही है उस विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो लोग आज स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा कर रहे हैं उनके पिछले कार्यकाल और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंतर को भी सदन के सामने रखना

आवश्यक है। हमने वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। जब मैं एक बार हॉस्पिटल में गया तो एक बुजुर्ग महिला सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल में जा रही थी। मैंने उसी समय बी0एम0ओ0 से कहा कि हम यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। आज हमने हॉस्पिटल में हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन पहुंचाई है। नीचे बेसमेंट में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इसके साथ-साथ हमने जनरल लैब में ऑटो एनलाइजर मशीन भी लगाई है जिसकी कीमत साढ़े छह लाख रुपये है। चिंतपूर्णी हॉस्पिटल में जनरल लैब के लिए 8 लाख 20 हजार रुपये की ऑटो एनलाइजर मशीन लगाई है तथा 4 लाख 99 हजार रुपये की ब्लड गैस एनलाइजर मशीन भी उपलब्ध करवाई है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा जारी..

26.08.2026/1635/AS/PB/1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी...

चिन्तपूर्णी के दूसरे हॉस्पिटल में जनरल लैब के लिए 8.20 लाख रुपये की ऑटो एनालाइजर मशीन, 4.99 लाख रुपये का ब्लड गैस एनालाइजर, चालीस हजार रुपये की ई0सी0जी0 मशीन और 3.50 लाख रुपये की सी0बी0सी0 मशीन लगाई गई है। इसके अलावा हमारे ओटी टेबल पर एक लाख रुपये की लागत आई है और कार्डियक मॉनिटर 9.96 लाख रुपये का है। इसके बाद आई0सी0यू0 बेड, सक्शन मशीन और फोटोग्राफी मशीन भी उपलब्ध करवाई गई हैं। यदि इन मशीनों की कीमतों को कुल मिलाकर देखें तो एक मशीन सात लाख रुपये की और दूसरी 3.50 लाख रुपये की है।

सभापति महोदय, हमारे अम्ब हॉस्पिटल में सरकार द्वारा ब्लड बैंक बनाया गया है जिसकी लगभग 25 लाख रुपये की लागत आई है। हमारे टी0बी0 के मरीजों को देखने के लिए जब चिकित्सकीय टीम को गांव-गांव जाना पड़ता था तो उन्हें बड़ी मशीन लेकर जाना पड़ता था। इसलिए अम्ब हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख रुपये की लागत की पोर्टेबल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाई गई है। मैं ये सभी विवरण इस माननीय सदन के समक्ष

प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके अलावा अम्ब हॉस्पिटल में नई ओ0पी0डी0 के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अम्ब हॉस्पिटल में नई ओ0पी0डी0 के लिए 22 करोड़ रुपये दिए हैं और इसकी पांच करोड़ रुपये की किस्त भी जारी की गई है। मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए जो एन0डी0एस0 मिलना है उसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए क्योंकि हमारे अधिकारीगण भी यहां बैठे हैं। यदि एन0डी0एस0 शीघ्र मिल जाएगा तो हम इसका टेंडर लगाकर कार्य शुरू कर सकेंगे और जनता को इसका लाभ जल्द-से-जल्द मिल सकेगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से लोहारा में न्यू पी0एच0सी0 के लिए एक करोड़ रुपये दिए हैं। चुआर के अंदर डिस्पेंसरी के लिए 70 लाख रुपये दिए गए हैं। हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए उप-मुख्य मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि एम्स जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है और उन्हें लगभग चार बसें बदलनी पड़ती हैं। इसलिए चिन्तपूर्णी से सीधे एम्स हॉस्पिटल के लिए बस सेवा शुरू की गई है। मैं माननीय सदन, मुख्य मंत्री

26.08.2026/1635/AS/PB/2

जी और उप-मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब यह बस चिन्तपूर्णी से चलती है तो इसे हमारी कुछ पंचायतों से होकर चलाया जाए। इसके मार्ग में लोअर लोहारा, चुआर, पगड़ा, कोहारसर, सार्डा और पराम पंचायतें पड़ती हैं। यदि बस इन पंचायतों के बीच से होकर जाए तो सुबह साढ़े पांच बजे निकलने वाले मरीजों को एम्स में जांच कराने के लिए सुविधा मिल सकेगी। हमें न्यू ओ0पी0डी0 के लिए जो पैसा दिया गया है उसके लिए सरकार से एक अनुमति आनी है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमें इसकी अनुमति जल्द-से-जल्द दी जाए।

सभापति महोदय, माता चिन्तपूर्णी जी का एक धार्मिक स्थान है जहां बहुत से श्रद्धालु प्रदेश के बाहर से आते हैं। वहां शीतला में हमारी पी0एच0सी0 है और शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर भी है। इसलिए इसे अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए और

उसे 24X7 किया जाए। हमारे धोसाड़ा में भी अस्पताल है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसे भी 24X7 किया जाए। हमारी सुहारीट-कोली की पी0एच0सी0 काफी बड़े क्षेत्र को कवर करती है। उसे भी अपग्रेड किया जाए। इसके साथ लगते बाबा बड़भाग सिंह जी के धार्मिक स्थान पर एक पी0एच0सी0 खोली जाए क्योंकि वहां बहुत से श्रद्धालु प्रदेश के बाहर से आते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वहां पी0एच0सी0 खोली जाए।

सभापति महोदय, अम्ब हॉस्पिटल में अभी एक कमी रह गई है और वह डायलिसिस की सुविधा है। हमारे क्षेत्र में किडनी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें डायलिसिस करवाने के लिए ऊना हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यदि अम्ब हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा।

सभापति महोदय, आज मैं सदन में जिस प्रकार की चर्चाएं देख रहा था और जिस प्रकार कुछ लोग यहां चर्चा कर रहे थे, उस पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। पिछले दो दिन हमारा सदन केवल इस बात को लेकर नहीं चल पाया कि यहां पहले राष्ट्रगान होना चाहिए या राष्ट्रगीत होना चाहिए। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आजादी

26.08.2026/1635/AS/PB/3

के समय आजादी का विरोध किया और अंग्रेजों की दलाली करते रहे। आज वही लोग हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि आपको राष्ट्रगान गाना है या राष्ट्रगीत गाना है।

सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्वास्थ्य पर ही अपनी बात रखिए।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि 1500 रुपये पर वे चर्चा मांग रहे हैं जो लोग चुनाव के समय 15 लाख रुपये देने का वादा करके संसद में आए थे और आज वे 1500 रुपये की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1640/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) ....जारी।

जो लोग पंद्रह लाख रुपये का वादा करके विधान सभा में आए थे। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य स्वास्थ्य पर बोलिए।

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) सभापति महोदय, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि पंद्रह का फिगर इनके लिए बड़ा खतरनाक है। इन्होंने पंद्रह लाख रुपये का वादा किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए और पंद्रह सौ करोड़ रुपये की बात करके गए। उसके बाद आज ये पंद्रह सौ रुपये की बात कर रहे हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि पंद्रह सौ रुपये तो माननीय मुख्य मंत्री जी 2 अक्टूबर को देने की बात कर चुके हैं। आपको तब यह पता चलेंगा जब पंद्रह सौ रुपये मिलेंगे। आप पंद्रह हजार से हारोगे क्योंकि पंद्रह का फिगर आपके लिए बड़ा खतरनाक है। मुख्य मंत्री जी का दिल बड़ा है और मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन आपकी पंद्रह सीटें भी नहीं आने वाली हैं। पंद्रह का फिगर आपके लिए लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सर, हमें यह बात बोल रहे हैं कि हमसे मीठी वाणी में बात करें लेकिन इन्होंने आज चीनी का दाम पैंतीस रुपये से बढ़ाकर सत्तर रुपये कर दिया है और हमसे मिठास की उम्मीद रख रहे हैं। यह बात समझ से परे है। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य हैल्थ पर बोलिए।

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : जिन्होंने सोना पैंतीस हजार रुपये से आगे पहुंचाया, वे आज सोने की तरह राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चीजें होने वाली नहीं हैं। आज स्वास्थ्य के प्रति आप कितने गंभीर थे और युवाओं को लेकर कितने गंभीर थे, यह पूरे देश ने बता दिया है। नीट का पेपर लीक करके आपने हमारे नौजवानों (Gen-Z) को क्या जवाब दिया, यह सबके सामने है। मैं आपको यह

बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक चाल के रूप में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश आपके लिए ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका

26.08.2026/1640/डी0सी0/ए0पी0-02

धन्यवाद करना चाहता हूं। स्वास्थ्य को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बेहतरीन कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन न करते हुए यह कहना चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर इस मंच पर इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप तो घोटालेबाज लोग हैं। फिर भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिमाचल, जय माता चिन्तपुरनी जी।

26.08.2026/1640/डी0सी0/ए0पी0-03

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं। वे पहली बांर सदन में आए हैं, लेकिन सदन के अंदर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणी की कि आप लोगों ने आजादी का विरोध किया है। आजादी का विरोध करने वाले कौन हैं और किसकी ओर से ये इशारा कर रहे हैं? वह विपक्ष की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे आजादी सिर्फ इनके ही कारण मिली है। मैं समझता हूं कि यह जो गंभीर टिप्पणी इन्होंने कि है वैसे तो नाम इनका माननीय सदस्य श्री सुदर्शन जी है और वह बबलू के नाम से प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि आपको बबलू से बड़ा होना चाहिए, आप सुदर्शन सिंह बनिए, बबलू मत रहिए। इसलिए बड़ी बातें करिए, जिम्मेदारी के साथ बाते करिये। यह कतेई भी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

उन्होंने विपक्ष के सदस्यों के लिए कहा कि आप लोगों ने आजादी और स्वतंत्रता का विरोध किया है। यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी ने जो बोला, वह तथ्यों के साथ बोला है। जब तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो दर्द होता ही है। मेरा यह कहना है कि माननीय विपक्ष के नेता को यह टिप्पणी करना उचित नहीं लगता कि बबलू से बड़ा हो जाए। बबलू जी तो पहले ही बड़े हैं, क्योंकि नाम भी बहुत बड़ा है। इसलिए आप ऐसी बातें कहकर किसी विधायक की शान पर टिप्पणी मत कीजिए। यह आपको भी शोभा नहीं देता। भाजपा तो उस समय थी ही नहीं, जनसंघ था। जनसंघ ने किस प्रकार से इतिहास दोहराया, जनसंघ क्या बोलता था? आप कहां फंस गए कि भाजपा उस समय थी। उस समय न आप और न मैं पैदा हुआ था। माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह जी ने इतिहास ही तो पढ़ा है। इतिहास में जो लिखा हुआ था, वही उन्होंने पढ़ा है। अब आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चौदह-पंद्रह साल से इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए किसी भी

श्री ए0टी0 जारी .....

26.08.2026/1645/AT/HK/01

मुख्य मंत्री जारी ...

विधायक पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि फर्स्ट टाइम की बात नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य क्या है वह देखिये कि आप वो लोग हैं जो संघर्ष नहीं करते थे। हम लोगों ने संघर्ष किया, देश के लिए संघर्ष किया। जब देश में सुई नहीं बनती थी, तब पंडित नेहरू की नीतियों से सुई से लेकर जहाज बनाए गए, सब कुछ हमने बनाया। आप उसका श्रेय ले रहे हैं आप तो विरोधी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि टिप्पणी करने से जो बात इन्होंने बबलू वाली कही है, इसको भी आप एक्सपंज कर दें।

सभापति : माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी...(व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय ने बोल दिया कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं।

26.08.2026/1645/AT/HK/02

श्री इन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के तहत मुझे भी चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक की बात करता हूं। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। जब माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नेरचौक में गए थे, उससे पहले वहां से 41 डॉक्टरों को बदला गया और बदलने के बाद उस मेडिकल कॉलेज की जो दशा हुई है शायद उसे बताने में भी मैं चिंतित हूं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

जहां स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं कि हमने रोबोटिक सर्जरी लगा दी, क्या वो रोबोटिक सर्जरी हमें चाटनी है? जब वहां डॉक्टर नहीं आते हैं...(व्यवधान) सीधी-सीधी बात करूं, लोकल भाषा में बात करूंगा, क्या रोबोटिक सर्जरी हमें देखनी है, जब वहां डॉक्टर नहीं आते हैं? और जब रोबोटिक सर्जरी की जाती है तो 30 हजार रुपये से 50 हजार का पैसा लगता है जो आपने गरीब लोगों के साथ जो अन्याय किया है, जो पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने हिमकेयर योजना चलाई थी, सहारा योजना चलाई थी या अन्य जो सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग में दी जाती थीं वे आपने सारी बंद कर दी हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना का लाभ लोगों को मिलता था, आज उन लोगों को मौत के घाट जाना पड़ रहा है। जैसा कि कल हमने वीडियो में देखा, आपके टांडा मेडिकल कॉलेज से एक मरीज को रेफर किया गया और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अगर हिमकेयर योजना होती, तो शायद उस बेचारे की जान बच जाती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर न हो और एक्स-रे भी बाहर करवाने पड़ते हों, टेस्ट भी बाहर करवाने पड़ते हों, उस मेडिकल कॉलेज का होना कितना अर्थ रखता है यह आप जानते हैं?

आप 70 साल से राज कर रहे हैं। आपने इस देश का हाल खराब कर दिया है। यह सच्चाई मैं बोल रहा हूं। आज जो आप स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं उस स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में हृदय का

26.08.2026/1645/AT/HK/03

विशेषज्ञ होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं मंत्री कई दिनों से ऑर्डर की मांग कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर का ऑर्डर नहीं हुआ। बिना हृदय के विशेषज्ञ के वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है तभी तो वहां से मरीजों को रेफर किया जाता है। बड़े मजे की बात है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट स्थानांतरित करने की बात कही है। ऐसा होता कि उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां स्थानांतरित कर दिया होता, जहां आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी को बदला है।

मैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 200 बीघा जमीन आपको दे रहा हूं। आपके पास कागज दिए हैं, मैंने स्वास्थ्य मंत्री के पास कागज दिए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी के पास कागज दिए हैं। इसके अलावा 75 बीघा जमीन हमारे कंसा ग्राउंड के पास खाली पड़ी है। वहां आप मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। अगर जो जमीन हमने आपको दी थी कहीं खड्ड में उसका इरोजर हो भी गया, फिर भी उसके अलावा बहुत-सी जमीन है, जो 200 बीघा जमीन हमारे मुडापर और मंडलवाहन में जो खंडहर की है, उसको बनाइए और दो-ढाई किलोमीटर मेडिकल यूनिवर्सिटी दायरा है उसका वहां निर्माण कीजिए ताकि लोगों को उसकी सुविधा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदया, एम0आर0आई0 के लिए, सी0टी0 स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज से बाहर जाना पड़ता है। मैं इसका जीता-जागता उदाहरण हूं।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1650/av/hk/1

श्री इन्द्र सिंह गांधी-------जारी

मेरे पेट में जब दर्द हुई तो वहां पर अल्ट्रासाउंड, सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 का डॉक्टर नहीं था। मुझे ये सारे टैस्ट बाहर करवाने पड़े। अब आप खुद सोचिए कि आम आदमी की क्या दशा होती होगी जिसकी कोई सिफारिश भी नहीं होती। मैं तो एक विधायक हूं और मैंने बाहर पैसा खर्च करके अपना इलाज करवाया। मगर जिन गरीब लोगों की सहायता पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने की थी, आज वे उन सुविधाओं से वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल इन्स्टिच्यूट बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि भेजी है। मैंने वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज के साथ दस बीघे लैण्ड दी थी, मगर वह इंस्टिच्यूट अभी तक नहीं बना। उसका निर्माण तो क्या होना, उसके कागजों के संदर्भ में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बार-बार बोलता हूं, मगर इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला मण्डी और बल्ह निर्वाचन क्षेत्र के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी।

अगर दवाइयों की बात की जाए तो मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 472 दवाइयां ऐसी हैं जोकि फ्री मिलती हैं। लेकिन जब पैरासिटामोल, पट्टियां और सिरिंज जैसी छोटी-छोटी चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां पर सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी बातें कीं मगर धरातल पर कुछ नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बिलासपुर में एम्ज होस्पिटल न होता तो पता नहीं हमारे मरीजों की आज क्या दशा होती। मैं माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एम्ज को चलाया है। हमारा

नेरचौक मेडिकल कॉलेज एक सेंट्रल प्वाइंट है। वहां पर लाहौल-स्पिति, कुल्लू और बंजार से मरीज आते हैं। मगर वहां पर सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को एम्ज बिलासपुर और पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ के लिए रैफर किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आपने बैठक में कहा था कि जो 41 डॉक्टर्ज स्थानांतरित किए हैं उनको वापिस लाया जाएगा। उसके पश्चात 5

26.08.2026/1650/av/hk/2

महीने का समय बीत गया मगर वे डॉक्टर्ज अभी तक नहीं आए। आपने पैरामेडिकल स्टाफ देने की बात भी कही थी, मगर आज तक वहां पर वह स्टाफ भी नहीं दिया गया। अगर पार्किंग व्यवस्था की बात की जाए तो वहां शराबियों का अड्डा बना हुआ है। जब गाड़ी लगाई जाती है तो वहां शराब की बोतलें मिलती हैं। इस सरकार में इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन चला है। अगर मैं अपने सिविल होस्पिटल रिवाल्सर की बात करूं तो वहां पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने सी0एच0सी0 को सिविल होस्पिटल का दर्जा दिया था। माननीय मुख्य मंत्री मण्डी आए और मण्डी से उसका उद्घाटन करके चले गए। वहां न तो 50 बैड्ज लगे और न ही वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ व प्रयोगशाला है। उसका निरीक्षण किए बिना उसका उद्घाटन कर दिया और वहां पर सिविल होस्पिटल का फट्टा लगा दिया। अगर उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल होस्पिटल का दर्जा दिया है तो वहां पर डॉक्टर्ज की संख्या व इक्विपमैंट्स भी उसी के अनुरूप होने चाहिएं, मेरा आपसे यह आग्रह है। मैं वहां के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहां पर एक व्यक्ति ने दो लाख रुपये की राशि दी और उस राशि से वहां उस होस्पिटल का काम चलाया जा रहा है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपका व्यवस्था परिवर्तन इस प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय, नशा मुक्ति के बारे में सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। नशा मुक्ति के लिए बच्चों को दौड़ाया जाता है, हो क्या रहा है कि जिस बच्चे को नशे का पता भी नहीं होता उसे भी नशे के बारे में पता चल रहा है। वर्तमान सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये की राशि खर्च कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए क्योंकि पुलिस का डर होता है। मॉर्निंग

असेम्बली में टीचर्ज भाषण देते हैं और कई बार हम भी जाते हैं। परंतु डर केवल मां-बाप और पुलिस का होता है। इसलिए पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए तभी प्रदेश को चिट्टे से मुक्ति मिल पाएगी। इस प्रकार से जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा जो कभी रिज़ पर निकाल दिया तो कभी मण्डी या सुन्दरनगर में निकाल दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि नशे से मुक्ति तब मिलेगी जब आपका प्रशासन और कानून-व्यवस्था ठीक होगी। मैं रोबोटिक सर्जरी की

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री इन्द्र सिंह ... जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं रोबोट सर्जरी के विषय में कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री वहां गए थे और मैं भी उनके साथ था। वहां रोबोट सर्जरी हुई लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई अन्य ऑपरेशन हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया है कि वहां ऑपरेशन के लिए 30,000 से 50,000 रुपये तक की राशि खर्च होती है। यह राशि अमीर लोगों के लिए हो सकती है लेकिन गरीब व्यक्ति 50,000 रुपये का खर्च वहन नहीं कर सकता। इसलिए गरीब लोगों की चिंता करते हुए उनके लिए कोई पैकेज दिया जाना चाहिए। आपने रोबोट सर्जरी की बात कही है लेकिन जहां अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर न हो, जहां एक्स-रे का डॉक्टर न हो और जहां टैक्सी की सुविधा न हो वहां रोबोट सर्जरी का क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के पास बसें खड़ी होती हैं और मरीज आते-जाते रहते हैं। मरीजों के रुकने के लिए वहां पर्याप्त स्थान नहीं है। इसके कारण प्राइवेट बसों तथा सरकारी बसों के चालकों के बीच आपस में लड़ते रहते हैं और मरीजों को वहां 10 से 15 मिनट तक रुकना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था को सुधारा जाए। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि बस का स्टॉपेज वर्तमान स्थान से 100 मीटर आगे अथवा 100 मीटर पीछे किया जाए ताकि मरीजों को वहां बेहतर सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वहां फुट ब्रिज अथवा फ्लाईओवर की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वहां आने वाले मरीज तथा पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट फुट ब्रिज से होकर सड़क को क्रॉस कर सकें और आसानी से हॉस्पिटल पहुंच सकें। यदि मुख्य मंत्री जी इस विषय पर ध्यान दें तो यह वहां की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक है। वहां इतनी भीड़ रहती है कि गाड़ियां, टैक्सियां और बसें खड़ी होती हैं जिससे लोगों को सड़क क्रॉस करने में बहुत कठिनाई होती है। मैंने आपसे इस विषय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से चर्चा भी की थी और आपको लिखित रूप में भी दिया है। आप कभी मेडिकल कॉलेज में आएं और वहां बैठक करें ताकि हम आपको वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत करवा सकें। यदि व्यवस्था में सुधार

26.08.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-2

नहीं किया गया तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं चलेगा क्योंकि इस प्रदेश सरकार का पतन होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज में पानी टपकता है, मरीज सोए होते हैं और उनके ऊपर से पानी टपकता रहता है। जिस मेडिकल कॉलेज और जिस स्वास्थ्य संस्थान में पानी टपकता हो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध करवाई जा सकती हैं? जब मैंने डॉक्टर से इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह तो बिन बादल बरसात हो रही है। मैंने कहा कि इस बरसात को रोकिए क्योंकि अन्यथा लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। इस विषय में मैंने प्रिंसिपल महोदय से भी बात की है लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। केवल व्यवस्था परिवर्तन के स्तर पर मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ता रहे और अस्पताल चलता रहे इससे काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, डिस्पेंसरियों के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं। यहां आयुष मंत्री बैठे हैं। दो वर्ष पहले वे मेरे क्षेत्र में गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि वहां आयुर्वेद डिस्पेंसरी दी जाएगी लेकिन तीन वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी वहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। आपने 22 लाख रुपये की घोषणा की थी लेकिन एक नया पैसा तक नहीं आया। वहां न तो डिस्पेंसरी बन पाई और न ही उसका शिलान्यास हो पाया।

...(व्यवधान) सरकार गांव के द्वार की बात करती है लेकिन एक नया पैसा नहीं आया। न तो अभी जमीन मिली है और न भवन की बात आगे बढ़ी है। मेरे क्षेत्र में जिस स्थान पर डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाना था वहां ऊपर से तारें जा रही हैं। इसके कारण आयुर्वेद डिस्पेंसरी का निर्माण रुक चुका है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों को इस बात की चिंता नहीं है कि इन तारों को हटाया जाए ताकि आयुर्वेद डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया जा सके और लोगों को सुविधा मिल सके। जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पंचायत में चल रही है वहां भी ...(व्यवधान) पानी टपक रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं उपलब्ध करवाई जाएं जहां अच्छा भवन हो अच्छी स्थिति हो और उचित व्यवस्था हो।

26.08.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-3

अध्यक्ष महोदय, बाकी जैसा कि कहा गया कि डॉक्टरों ने मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन कर दिया। अरे भाई किसकी बच्चादानी का ऑपरेशन कर दिया? ऐसा मैंने पहली बार सुना है लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारी तो किसी की बच्चादानी नहीं है। कांग्रेस के लोगों को पता होगा कि किस मर्द की बच्चादानी है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इसके लिए साबित करें कि किसकी बच्चादानी है और किस मर्द की बच्चादानी है जिसका ऑपरेशन किया गया है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि

एन0एस0 द्वारा ... जारी

26.08.2026/1700/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री इन्द्र सिंह------जारी

यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और इस पर जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए। दोषी को दोषी करार देना चाहिए। यही मेरा आपसे कहना है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात की है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री इन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष : अब वैसे तो लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है क्योंकि सत्ता पक्ष से तो कोई माननीय सदस्य बोलने वाला नहीं है। विपक्ष से अभी श्री दलीप ठाकुर जी का नाम है और सदन का समय भी हो गया है यानी 5 बज गए हैं। सदन का समय अभी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मंत्री जी जवाब देंगे अन्यथा यह विषय सोमवार को जाएगा। अगर आप सबकी राय है तो पहले सदन की कार्यवाही का समय एक घंटा बढ़ा देते हैं।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की)

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 6.00 बजे तक बढ़ाई जाती है। अब श्री दलीप ठाकुर जी, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें। माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी, please be very-very brief and short. ...(Interruption) पहले तो आप ही बोलेंगे। Hon'ble Chief Minister will intervene only if it is required otherwise you will satisfy them. You have the capacity to satisfy them. श्री दलीप ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने प्रस्तुत किया है।

26.08.2026/1700/एन0एस0-ए0जी0/2

आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सभी वक्ताओं ने चर्चा की और हम सबने अपने-अपने क्षेत्र की बात भी कही। परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन वक्ताओं ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने पिछली सरकार द्वारा खोले गए लगभग 257 संस्थानों का उल्लेख किया है और व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने उन संस्थानों को बंद करने का काम किया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि संस्थान बंद हुए तो हजारों पद भी समाप्त हुए। कुछ वक्ताओं ने शिमला हॉस्पिटल की बात की और कुछ ने बिलासपुर एम्स की बात की। हम इस कम्पीटीशन में लगे रहे कि शिमला हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है और एम्स में क्या व्यवस्था है? केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस प्रदेश के लिए करोड़ों रुपये दिए परन्तु प्रदेश सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाई। केंद्र सरकार से करोड़ों रुपये मिले लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विभाग के अधिकारी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए तथा उसे धरातल पर नहीं ला पाए। यह भी हम सबका दुर्भाग्य है।

अध्यक्ष महोदय, यहां बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं और आदर्श संस्थान खोलने की बातें हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्श संस्थान कहां खुले हैं? मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सरकाघाट की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरकाघाट में कोई भी आदर्श संस्थान नहीं खुला है। यहां हमारे मित्र डॉक्टरों की बातें कर रहे थे कि मेरे क्षेत्र में इतने डॉक्टर आ गए। ...(व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए वह आपका ठीक से इलाज करेगी, वह हमारी

सांसद हैं और आप उसकी चिंता मत कीजिए। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। वह हमारे मित्र भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो संस्थान बंद हुए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

26.08.2026/1705/RKS/Ag-1

श्री दलीप ठाकुर जारी....

हैं उन्हें पुनः नोटिफाई किया जाए। मुख्य मंत्री जी द्वारा बार-बार कहा गया कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे और इन संस्थानों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड मशीन तथा एम0आर0आई0 मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं सरकाघाट की बात करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप बताएं कि सरकाघाट में आपने आदर्श संस्थान कहां खोला है? आपके दावे अब खोखले सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि इस दिशा में आपने कोई प्रयास नहीं किया है। सरकाघाट में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में सरकाघाट में कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने भी ऑक्सीजन प्लांट का उल्लेख किया था लेकिन आपने इस प्लांट को भी बंद करने का काम किया। वहां आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी हटा दिया गया। आज सरकाघाट का ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज सरकाघाट में स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार आवश्यकता पड़ने पर समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता। सरकाघाट एक सैनिक क्षेत्र है और आप स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ-साथ एक सैनिक रहे हैं। इसलिए मैं आपको यह बात विशेष रूप से याद दिलाना चाहता हूं कि आप सरकाघाट की ओर भी ध्यान दें। मैंने अनेकों बार सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट और बलद्वाड़ा की बात इस सदन में रखी है। मैंने हर विधान सभा सत्र के दौरान निवेदन किया कि चाहे सरकाघाट अस्पताल हो या बल्द्वाड़ा अस्पताल, दोनों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। आज स्थिति यह है कि

सरकाघाट में ई0एन0टी0 डॉक्टर, सर्जन और स्किन स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। वहां डॉक्टर्ज के पद रिक्त पड़े हुए हैं। मेरा आग्रह है कि सरकाघाट में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मैं पिछले चार वर्षों से लगातार यह मांग कर रहा हूं कि सरकाघाट से मरीजों को रेफर किए जाने पर उन्हें मण्डी, बिलासपुर या हमीरपुर तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकाघाट की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और जिस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात सरकार कर रही है, उसे सरकाघाट में भी स्थापित किया जाए।

26.08.2026/1705/RKS/Ag2

जहां तक सिविल हॉस्पिटल बलद्वाड़ा का प्रश्न है, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि वहां अल्ट्रासाउंड की मशीन तथा अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। सरकाघाट में अल्ट्रासाउंड मशीन तो उपलब्ध है किन्तु उसे संचालित करने वाला डॉक्टर नहीं है। जो मशीन वहां स्थापित है वह जंग खा रही है। यदि डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होंगे तो लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी? मेरा निवेदन है कि सरकाघाट में रेडियोलोजिस्ट की नियुक्ति की जाए और बलद्वाड़ा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाए। इसके अतिरिक्त बलद्वाड़ा में ओर्थो और मेडिसिन के डॉक्टर भी नियुक्ति किए जाएं। यदि वहां पूरे डॉक्टर उपलब्ध होंगे तो उस क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मैं जमनी अस्पताल की भी बात करना चाहता हूं। वहां आज डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। समैला में भी डॉक्टरों का अभाव है। समैला में एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। बलद्वाड़ा अस्पताल में केवल दो डॉक्टर कार्यरत हैं। जब भी समैला, जमनी या चंदेश से डॉक्टरों की मांग आती है तो उन्हें सरकाघाट या बलद्वाड़ा भेज दिया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकाघाट और बलद्वाड़ा दोनों सिविल अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। सरकार ने कहा था कि वह गांवों के विकास के लिए चिंतित है परन्तु गांवों में स्थित छोटे अस्पतालों एवं पी0एच0सी0 स्तर के स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति आज चिंताजनक है। मैं हवाणी प्रसादा पी0एच0सी0 की बात करुंगा। पूर्व सरकार के समय इसके लिए 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे किन्तु आपके चार वर्षों के कार्यकाल में भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस अस्पताल

के लिए भूमि भी उपलब्ध करवा दी गई है लेकिन अभी तक इसका कार्य आरम्भ नहीं किया गया है और न ही उसका टेंडर किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हवाणी प्रसादा हॉस्पिटल के भवन का कार्य भी शीघ्र आरम्भ करवाया जाए क्योंकि उसके लिए धनराशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मैं पी0एच0सी0 चंदेश की बात करना चाहूंगा। उसका कार्य भी तेज रफ्तार से आरम्भ करवाया जाए। समैला हॉस्पिटल के भवन की दशा भी अत्यंत खराब है, आप उसके लिए भी राशि जारी करने की कृपा करें।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1710/बी.एस./ए.एस.-1

श्री दलीप ठाकुर जारी...

ताकि हमारा वह हॉस्पिटल भी ठीक हो सके। अब प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की बात की है। यहां बहुत से मित्र बोलते-बोलते आजादी की तरफ चले गए। बोलते-बोलते कहा कि आजादी दिलाई है तो हमने दिलाई है। ऐसी अनेक प्रकार की बातें की गईं। चाहे राष्ट्रीय गान की बात की गई हो या कई अन्य प्रकार की बातें की गई हों। बहुत से लोगों ने अपने विषय से हटकर बात की लेकिन उनको रोका-टोका नहीं गया। हम तो अपने विषय पर बात करें कि पिछली सरकार ने कितना काम किया था और आदरणीय जय राम ठाकुर की सरकार ने कितना काम किया था।

अगर आप चार वर्षों के कार्यकाल में उस काम को आगे बढ़ाते तो हमारे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी अच्छी सुविधाएं मिलती। चाहे बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल हो वहां भी अच्छी सुविधाएं मिलती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकाघाट में जितने भी संस्थान हैं चाहे पी0एच0सी0 की बात करूं या सिविल हॉस्पिटल की बात करूं मेरा आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि वहां डॉक्टर देने की कृपा करें।

सरकाघाट में अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है। उसकी बहुत कमी है। कृपया करके इस कमी को भी पूरा करें। ब्लड बैंक की भी बहुत कमी है, कृपया करके इन सभी बातों को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए।

आप कह रहे हैं कि चार वर्षों में हमने बहुत काम किया और हमने बहुत से डॉक्टर दिए लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आपने कोई नया काम नहीं किया। इसलिए आप उन कामों को पूरा करने का प्रयत्न करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं और मुझे आशा है कि आप इन सभी कामों को पूरा करेंगे, धन्यवाद

25.08.2026/1710/बी.एस./ए.एस.-2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण चर्चा पिछले तीन दिन से स्वास्थ्य के विषय और स्वास्थ्य की सुविधाओं से संबंधित चल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि पिछले तीन दिन से सदन में बाकी लोग उपस्थित रहे या नहीं रहे लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक-एक सदस्य को चाहे वह सत्ता पक्ष से बोल रहा हो या विपक्ष से बोल रहा हो सभी की बातों को नोट किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको पूरी अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए और बोलने का अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सबमिशन करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस चर्चा में भाग लेने से स्वयं अपने आपको पीछे किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि माननीय सदस्यों को ज्यादा-से-ज्यादा अवसर मिल सके और ज्यादा-से-ज्यादा समय मिल सके। क्योंकि हम तो बोलते ही रहते हैं जैसा आप भी कहते हैं।

लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल में पहले दिन से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है।

मेरा यह मानना है कि आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। अगर आदमी की जिंदगी को हम बचा सकें तो यह बहुत बड़ा काम है। वह दायित्व सरकार का होना ही चाहिए। इसी भाव के साथ आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत' की शुरुआत की कि गरीब आदमी इलाज के बिना इस दुनिया से न जाए। यह जिम्मेवारी हमारी है कि उसको इलाज की सुविधा मिले और उसकी पीड़ा को हम कम कर सकें। यही भाव हिमाचल प्रदेश में 'हिमकेयर' योजना चलाने के लिए भी रहा और जो माननीय सदस्य पूर्व में मंत्री रहे हैं श्री विपिन सिंह परमार जिन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की और हमने घंटों इस सारे विषय पर चर्चा की कि आदमी की जिंदगी की पीड़ा हम कैसे कम कर सकें और आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए हम क्या काम कर सकें तथा कैसे काम कर सकें। इसी भाव के साथ हमने इस योजना को शुरू किया था।

25.08.2026/1710/बी.एस./ए.एस.-3

और मैं देख रहा हूं कि लगातार एक क्रम चल रहा है, एक ऐसा क्रम चल रहा है जिससे हमारी इस योजना को अपाहिज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के कारण लोगों को जिंदगी मिली और उसके बाद जब इस योजना को बंद करने की एकदम हिम्मत नहीं हो पाई तो

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

26.08.2026/1715/DT/DC-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

धीरे-धीरे पूरे प्रदेश भर में ऐसा एक कैंपेन चला दिया गया कि इसको बदनाम करो। इस तरह से बदनाम करने की जो साजिश है वह मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वस्थ सोच नहीं है। काम करते-करते कमी हो सकती है। अगर हमसे कोई कमी रही है तो आप उसमें सुधार करिए। इसका आशय यह नहीं है कि हमने कोई अच्छा काम शुरू किया है तो उसको बंद ही करना है। अगर आपने इससे अच्छी कोई योजना लाई होती तो हम उस बात

से भी सहमत होते। शायद हम उसकी बेहतरी के लिए सुझाव देते। अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां होते, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में कम रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं भाव पर जा रहा हूं कि वर्तमान सरकार का जो भाव रहा है वह यह रहा है कि अगर हिमकेयर को बंद नहीं कर सकते हैं तो उसको अपाहिज कर दो और उसका गला घोंट दो। पहले पैसा देना बंद कर दिया गया और उसके बाद इस योजना को बदनाम करने के लिए क्रम बनाया गया। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस की इंक्वायरी का एक माहौल खड़ा कर दिया गया है। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जब किसी विषय को लेकर इंक्वायरी शुरू होती है तथा विजिलेंस का शब्द आता है या जांच का शब्द आता है तो हर आदमी उस बात को लेकर सोचने पर विवश हो जाता है कि पता नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। हमें अच्छी तरह मालूम है, हम भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। पुराने अधिकारियों से भी मिलना होता है तथा नए अधिकारियों से भी मिलना होता है। उनसे बातचीत भी होती है। दिल से सब कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है- गलत क्यों हो रहा है- गलत क्यों हो रहा है? मैं कहूंगा कि वह इसलिए हो रहा है क्योंकि जोर-जबरदस्ती से इस मामले को उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हां, इसमें सुधार की अगर गुंजाइश बनती है तो उसके सुझाव दीजिए। उन सारी चीजों को लेकर के हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहा गया कि मामला 100 करोड़ रुपये से ऊपर के घोटाले का बनाना है। बोल दिया इसलिए बनाना है और हर हाल में बनाना है।

मैं एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि वक्त बहुत तेजी से निकल गया है और निकल रहा है। वर्तमान सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है अब जो एक वर्ष बचा है वह भी निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी

26.08.2026/1715/DT/DC-2

ऐसा कोई काम आसानी से नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो जो जांच चल रही है उसमें गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है तो उसकी जांच भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी। ऑथोरिटी के आधार पर फिर हम इस बात को

लेकर चर्चा करेंगे कि किसने जांच शुरू की और किस बात पर जांच शुरू हुई यानी इन सारी चीजों को लेकर भी चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय मैं सहारा योजना की बात भी करना चाहूंगा। ये दो योजनाएं ऐसी हैं जो बेबस लोगों की मदद करने के लिए हैं जिनको सही मायने में सहारे की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस योजना को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जिद पर आ गए हैं कि मुझे यह करना है तो वे ऐसा कर सकते हैं। आप इस योजना को बंद करके प्रदेश के उन गरीब लोगों का भला नहीं कर पा रहे हैं इसको और इससे न ही सरकार भला होने वाला है। इस बात को मैं साफ कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी का भला भी नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने हिमकेयर योजना को बंद किया और सहारा योजना को बंद किया तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन कैबिनेट की पहली बैठक में दोनों स्कीम्स को वहीं से शुरू करेंगे, उसी रूप में शुरू करेंगे जिस रूप में और जिस भाव के साथ हमने इन योजनाओं को शुरू किया था। यह मैं अपने दल की ओर से ऐलान करना चाहता हूं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों को लेकर के विचार करें और सोचें कि जनहित में क्या है तथा प्रदेश हित में क्या है और गरीब हित में क्या है? राजनीति चलती रहेगी और सत्ता का आना-जाना चलता रहेगा। कोई आदमी इस बात को लेकर सोचे। मुझे भी बहुत सारी चीजों को लेकर यह कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं ला पाए। कई लोग बोलते हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि आज से पहले बड़े-बड़े लोग इसी हिमाचल प्रदेश में रहे हैं उन सभी के प्रति सम्मान है लेकिन उनके कार्यकाल में भी सत्ता उनके हाथों में वापस नहीं आई है। पांच वर्ष के बाद परिवर्तन ही हुआ है। अब जब परिवर्तन हुआ है तो इस बात को मानकर चलना चाहिए कि हमें कुर्सी के लिए काम नहीं करना चाहिए।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1720/DC/PB/1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

बल्कि प्रदेश के भले के लिए काम करना चाहिए। हमने पूरे पांच वर्ष इस भाव के साथ समर्पित किए कि हम फालतू की बातों में नहीं उलझेंगे। हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। हम केवल प्रदेश के लिए काम करने और प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हमने उसी भाव के साथ काम किया। हमारे सामने यह लक्ष्य नहीं था कि हम सत्ता में आएं या न आएं। हमारे सामने केवल एकमात्र लक्ष्य था कि हम हिमाचल की जनता की बेहतर ढंग से सेवा कैसे कर सकें, उनके लिए राहत के क्या कार्य कर सकें और प्रदेश की भलाई तथा विकास के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। हमने इसी भाव के साथ काम करने की कोशिश की है। लेकिन वर्तमान सरकार की जो मंशा है, उसमें प्रदेश का भला सोचना छोड़ दिया गया है। इनके लिए यह सोचने का विषय ही नहीं है कि प्रदेश के लिए क्या अच्छा है। केवल मेरी कुर्सी कैसे बचेगी, मैं सत्ता में वापस कैसे आऊंगा और सत्ता में हमारे साथी कैसे वापस आएंगे, इसी भाव के साथ काम करने की सोच प्रदेश हित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यदि आप इन दोनों योजनाओं, 'हिमकेयर' और 'सहारा योजना', को बंद करेंगे तो सत्ता पक्ष के पास बहुत अधिक समय नहीं है। हम जब सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दोनों योजनाओं को उसी भाव के साथ रिस्टोर करेंगे, जिस भाव के साथ हमने उन्हें शुरू किया था, धन्यवाद।

अध्यक्ष : इस विषय पर लगभग आठ घंटे चर्चा हुई है और लगभग तीस माननीय सदस्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। अब मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा का उत्तर दें। जैसे ही वे उत्तर देंगे, वैसे ही चर्चा समाप्त हो जाएगी। ...(Interruption). Hon'ble Chief Minister will intervene only if it is required.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, it was very long marathon debate. हमारे पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री जी और जिन्होंने आपकी तरह अध्यक्षपीठ को सुशोभित

26.08.2026/1720/DC/PB/2

किया है, श्री विपिन सिंह परमार जी ने इस चर्चा का आरंभ किया। Sir, with your permission can I read the names of the Hon'ble Members who all participated in this debate?

Speaker: Yes, you are welcome to do that.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : इस चर्चा का आरंभ श्री विपिन सिंह परमार जी ने किया। इसमें माननीय सदस्य सर्वश्री नीरज नैय्यर जी, डॉ0 जनक राज जी, पवन काजल जी, राम कुमार जी, रणधीर शर्मा जी, जगत सिंह नेगी जी, डॉ0 हंस राज जी, मोहन लाल ब्राक्टा जी, राकेश जम्वाल जी, संजय अवस्थी जी, किशोरी लाल जी, बलबीर वर्मा जी, आ0 एस0 बाली जी, विनोद कुमार जी, चंद्र शेखर जी, त्रिलोक जम्वाल जी, सुरेश कुमार जी, सुरेन्द्र शौरी जी, मलेन्द्र राजन जी, प्रकाश राणा जी, विनोद सुल्तानपूरी जी, लोकेन्दर कुमार जी, डी0एस0 ठाकुर जी, सुदर्शन बबलू जी, इन्द्र सिंह गांधी जी, दिलीप ठाकुर जी और श्रीमती रीना कश्यप जी ने चर्चा में भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि लगभग तीस के करीब प्रतिभागिता हुई है और यह बहुत लंबी और संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। I am grateful to the kind remarks given by our former Chief Minister and senior leader Sh. Jai Ram ji and his feeling towards this debate. इस संवेदनशील तथा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें किस भावना से सोचना चाहिए, इसके लिए वास्तव में आभारी हूं। मैं आरंभ में ही कह देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से 'हिमकेयर' या 'आयुष्मान भारत योजना' को बंद नहीं किया जा रहा है। इसमें some sort of amendments will be there which will be known to you all. I don't think that these very useful schemes (HIMCARE & SAHARA) have been stopped.

अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत व्यापक है और बहुत लोगों ने इस विषयवस्तु पर अपने ऑब्जर्वेशन्ज या सुझाव दिए हैं उन्हें नोट किया है। मैं यह भी कहता हूं कि

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.08.2026/1725/एच0के0/ए0पी0-01

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी .....

बहुत लोगों ने इस विशेष विषय में अपने ऑब्जर्वेशन और सुझाव दिए हैं, मैंने उन सभी को नोट किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संत कबीर का एक दोहा है :-

"निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय;

बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।"

I personally do not take all these things otherwise which probably have been told in whatever toned. पर उसके पीछे जो भाव रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि हम किस प्रकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार सकते हैं। चाहे माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी ने बात कही हो या किसी और ने, सबका भाव यही रहा है कि जो भी गलतियां हैं, उनमें सुधार करना आवश्यक है। अगर कोई हमें बताए कि कहां कमी है या क्या सुधार करना है तो उस ओर हमारा बहुत ध्यान रहेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक ऐसा दृष्टिकोण है कि वे चाहते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास अपना कोई सहारा न हो, उसे सरकार का सहारा मिले। जैसे माननीय जयराम ठाकुर जी ने सहारा योजना की बात कही। अभी इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। लगभग तीन हजार कार्ड बन चुके हैं। मैंने आज ही स्टाफ से इसकी जानकारी ली है। हम सहारा योजना को क्यों नहीं जारी रखें? कुछ एक थोड़ा सा व्यवधान हुआ है because of shortage of staff or certain other things because they have to do from the angle how it has to be made proper. यह एक अच्छी योजना है और इसे बंद करने का कोई कारण नहीं है। "सहारा" शब्द ही बताता है कि जिसका कोई सहारा

न हो, उसके लिए सहारा योजना बनाई गई है। इसके पीछे यही भाव हमेशा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य संस्थानों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों के निर्माण, विस्तार, उन्नयन और आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए 13,714.98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में विभिन्न निर्माणाधीन भवनों के लिए 8,02,554.1 लाख तथा वर्ष 2026-27 में 13,11,256 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लगभग 63

26.08.2026/1725/एच0के0/ए0पी0-02

स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। Before I speak further on this मैं दो विषयों की बात करना चाहता हूं। एक विषय सरकाघाट से संबंधित है। माननीय सदस्य ने कहा है कि and I want to tell him that in Sarkaghat Constituency, the Civil Hospital Sarkaghat is already proposed as Adarsh Swasthya Sansthan. It will be staffed properly. मैंने आपके साथ देखा है इसलिए बाकायदा we seen soon the staffing patron also. दूसरा विषय श्रीमती रीना कश्यप जी ने नारग के संबंध में कहा है। It has been already notified also. यह दूसरे चरण में हो रहा है। हमारा दूसरा चरण सितंबर के अंत में शुरू हो जाएगा और आपको शीघ्र ही इसकी अपडेट दी जाएगी। नारग में मैंने स्वयं देखा है कि वहां पूरी सुविधाएं हैं। इसके अलावा, 130 स्वास्थ्य संस्थानों के नए भवनों के लिए नक्शा स्वीकृति, प्राक्कलन की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, एन0एच0एम0, पी0एम0-एभीम के अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज, डी0पी0एच0यूज0, एस0एन0यूज0 सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण और उन्नयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स में विभिन्न संस्थानों में कार्य प्रगति पर है। एन0एच0एम0 के अंतर्गत 73 बी0पी0एच0यूज0 स्वीकृत हैं, जिनमें से 67 का कार्य एच0एल0एल0 को सौंपा गया है। इनमें 29 पूर्ण हो चुके हैं और 38 का कार्य वर्ष 2026-27 में किया जाना प्रस्तावित है। 115 भवन विहीन एच0एस0सीज0 तथा 69 भवन विहीन

पी0एच0सीज0 के लिए 162.31 करोड़ रुपये का प्रावधान है; शेष भवनों और विभिन्न संस्थानों का कार्य डी0एच0एस0 और एन0एच0एम0 के माध्यम से

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.08.2026/1730/AT/HK/01

स्वास्थ्य मंत्री जारी.....

आगे बढ़ाया जा रहा है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत IGMC शिमला, RKGMC हमीरपुर, RPGMC टांडा, डॉक्टर YS परमार हमारा जो मेडिकल कॉलेज नाहन है, AIIMS चमियाणा और अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न भवन ब्लॉक निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। मैं अवश्य कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री की जो दूरदर्शिता है कि हम, there should be a world-class equipment and high-end technology, machinery and equipment, so that our various institutions are equipped accordingly. इसी भावना के साथ राज्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया गया, जो मैंने पहले कहा, इसमें एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सि0टी0 स्कैन एवं अन्य जांच सुविधाएं करवाने की ओर सरकार अग्रसर है। शायद अभी हमारे चौपाल के विधायक नहीं हैं, उनके पास दोनों ही जगह जहां मैं गया हूं चौपाल में भी और नेरवा में दोनों जगह एक्स-रे की मशीन और अल्ट्रासाउंड भेजे जाते हैं, किंतु हो सकता है उनके पास पहुंचने के लिए थोड़ा समय लग रहा हो पर दोनों चीजें स्वीकृत कर दी गई हैं। 37 नई एक्स-रे मशीनें, 24 अल्ट्रासाउंड मशीनें लगभग 10.71 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध करवाने के लिए आपूर्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सिटी स्कैन सुविधा के लिए पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से 34 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। पी0एम0 केयर के 8 आठ एम0आर0आई0, 5 मैमोग्राफी मशीनें स्वीकृत हैं, एम0आर0आई0 RH कुल्लू, RH सोलन, RH पालमपुर, RH बलासपुर, RH ऊना, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किन्नौर एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठियोग, मैमोग्राफी RH सोलन, CH पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल

हमीरपुर, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठियोग। डी0एम0ई0 के अंतर्गत रोबोटिक सर्जरी, AIIMS चमियाणा, RPGMC टांडा, IGMC शिमला और नेरचौक मंडी में प्रारंभ है। आर0के0जी0एम0सी हमीरपुर स्थापना के लिए प्रस्तावित है। 256 स्लाइस सि0टी0 स्कैन AIIMS चमियाणा तथा 128 स्लाइस सि0टी0 स्कैन IGMC शिमला में उपलब्ध हैं।

26.08.2026/1730/AT/HK/02

PET-CT स्कैन IGMC शिमला में स्थापित है तथा अन्य प्रमुख स्थानों में भी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है। Hon'ble Speaker, Sir, I just want to explain very briefly as to what is PET scan. PET scan can see the problem in a patient who is suffering from cancer from all angles and in a very detailed manner. So his diagnosis becomes easy. That is the main reason, and we are trying, with the blessing of God Almighty and the जो दूरदर्शिता माननीय मुख्य मंत्री महोदय की है कि हमें इसे जहां-जहां भी आवश्यक होगा देने का प्रयास कर रहे हैं। 30 Tesla MRI IGMC शिमला, AIIMS चमियाणा, RKGMC हमीरपुर और नेरचौक में उपलब्ध हैं। RPGMC टांडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। लाइन एक, IGMC शिमला एवं मंडी, CT Stimulator IGMC शिमला एवं मंडी तथा High-end Digital-Ray RPGMC Tanda में उपलब्ध है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला में CBCT एवं मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी उपलब्ध है। प्रदेश के 51 डेंटल क्लीनिक्स में आधुनिक डेंटल केयर्स उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और शेष में नई डेंटल केयर लगाने की प्रक्रिया जारी है। AIIMS, चमियाना में वर्ष 2024-25 में लगभग 4.29 करोड़ रुपये तथा HITES के माध्यम से 4 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे गए हैं। वर्ष 2025-26 में Da Vinci Surgical Robot Xi System सहित उपकरणों पर 28.88 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 15 SNCUs में equipment replenishment, 5 NBSU को SNCU में उन्नयन करना, 16

NBSUs के upgrading के लिए कार्य प्रगति पर है। दवाओं की उपलब्धता, I know there has been a cry that the medicines are really not available. मैं समझता हूं कुछ स्थानों पर सचमुच में कमियां नज़र आई हैं और उसका संज्ञान लिया गया है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मांग, उपलब्ध बजट, खपत एवं स्टॉक के नियमित समीक्षा की जाती है और आवश्यकता के अनुसार खरीद की जाती है। Essential drug list के अनुसार रिजनल, डिस्ट्रिक्ट, सिविल, CHC

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

26.08.2026/1735/av/hk/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-------जारी

स्तर के संस्थानों के लिए 571 दवाएं / औषधियां एवं 138 consumables PHC स्तर पर 170 दवाएं एवं 48 Consumables तथा Health Sub-Centre स्तर पर 91 दवाएं एवं 28 Consumables निर्धारित हैं।

राज्य Rate Contract में 571 दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त CPSU, ESI तथा BPPI की स्वीकृत Rate Lists में उपलब्ध दवाओं में से कम दर वाले स्त्रोत से खरीद की व्यवस्था है।

Drug & Vaccine Distribution Management System (DVDMS) के माध्यम से Rate Contract वाली आवश्यक दवाओं के लिए L-1 bidder को supply order जारी किया जाता है ।

बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता होने पर जन औषधि भंडार/अन्य अनुमोदित स्त्रोतों से कम दर पर दवाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। आवश्यक स्थिति में स्थानीय बाजार से खरीद हेतु संबन्धित बजट का 10% प्रवधान उपलब्ध है।

निःशुल्क दवा योजना के अन्तगर्त वर्ष 2026-27 में केन्द्र सरकार द्वारा 1613.48 लाख रुपये आंबटित किए गए, जिनमें से 1501.15 लाख रुपये की दवाएं खरीदी जा चुकी हैं। राज्य बजट से 945.09 लाख रुपये आंबटित हुए जिनमें से 589.13 लाख रुपये की खरीद हो चुकी है।

DME के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की मांग, खरीद एवं आपूर्ति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश किए जाते हैं।

NHM के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यक दवाओं, consumables तथा कार्यक्रम-विशिष्ट supplies की उपलब्धता सुनिश्चित

26.08.2026/1735/av/hk/2

की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री की दूरदर्शी सोच से मैन पावर सेक्टर has received due attention. We have really seen and gone into the details. Later on, the Hon'ble Chief Minister will also tell you in detail, but I can just tell you some of the figures.

सरकारी अस्पतालों में Staff Nurses के 1,938 स्वीकृत पदों में से 1,266 पद भर दिए हैं तथा 672 पद रिक्त हैं। 200 Staff Nurses की भर्ती के लिए दिनांक 12.06.2026 को स्वीकृति दी गई है और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है। 500 रोगी-मित्र Staff Nurses की भर्ती के लिए HPSEDC Shimla को मांग भेजी गई है। Assistant Staff Nurse के नए cadre के अंतर्गत 150 पद भरने की स्वीकृति दी गई है। जिनमें से 117 को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं और 103 ने कार्यभार ग्रहण किया है।

Pharmacy Officer के 66 रिक्त पदों के लिए मांग भेजी गई है। 28 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू है। MLT Grade-II के 21 रिक्त पदों के लिए मांग भेजी गई है तथा अतिरिक्त 41 पदों की भर्ती प्रक्रिया में हैं।

Laboratory Assistant के 8, Radiographer के 58, Ophthalmic Officer के 2, OTA के 158 तथा Physiotherapist के 6 रिक्त पदों को भरने के लिए मांग/प्रक्रिया संबंधित स्तर पर प्रगति पर है। It is on top priority. It is a very-very important subject. So many vacant posts are really not appreciated. We are trying. It is on our top priority.

DME/Medical Education

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन Faculty Members के 1,107 स्वीकृतं पदों में से 733 भरे हैं, Resident Doctors के 907 में से 429, Paramedical Staff के 1,567 में से 692 तथा Nursing के 2,784 में से 1,767 पद भरे हुए हैं। इन श्रेणियों में मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पद सृजन/भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मैं समझता हूं कि यह भी हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है।

26.08.2026/1735/av/hk/3

NHM/PM&ABHIM

NHM के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 6,088 पद अनुमोदित हैं; इनमें से 4,115 पद भरे हुए है।

Outsourcing के आधार पर 1.567 पद भरने के लिए HPSEDC को मांग भेजी गई, जिसके विरुद्ध 1.035 पद भरे जा चुके हैं।

PM&ABHIM के अंतर्गत 321 पद अनुमोदित हैं; outsourcing के लिए मांग भेजी गई है और 81 पद भरे जा चुके हैं।

Dental services में M.O. (Dental) के 382 स्वीकृत पदों में से 359 भरे गए हैं। 23 रिक्त Dental Hygienist के 113 में से 95 भरे गए हैं एवं 18 रिक्त है तथा Dental Mechanic के 175 में से 106 भरे गए हैं एवं 69 रिक्त हैं।

टी सी द्वारा जारी

26.08.2026/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ... जारी

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता एवं सेवा विस्तार

अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में I think one of the most important subjects, which receives his attention as well as that of our staff. सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुलभ गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है और ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच मजबूत करना है।

इसलिए चंबा से मांग आई हो या प्रदेश के दूसरे स्थानों से मांग आई हो या दूर-दराज के क्षेत्रों से संबंधित मांग हो या फिर जिनके बारे में माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार ने भी थोड़ी देर पहले बताया है उन सभी बातों को मैंने नोट किया है। मैं इन बातों को इसलिए नोट करता हूं ताकि यदि समय की कमी के कारण इस पूरे वक्तव्य में कोई बात छूट जाए तो मैं उसे देखकर संबंधित विषय की जानकारी लिखित रूप में भी उपलब्ध करवा सकूं और जिस कार्य की आवश्यकता हो उस पर आगामी कार्रवाई की जा सके।

कायाकल्प कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता साफ-सफाई संक्रमण नियंत्रण निर्धारित मानकों तथा प्रोटोकॉल के अनुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 51 तथा वर्ष 2025-26 में 52 कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। इन संबंधित पुरस्कारों की राशि क्रमशः 354.75 लाख रुपये तथा 451.50 लाख रुपये रही है। वर्ष 2026-27 के लिए

कायाकल्प में इंटरनल असेसमैंट पूरा हो चुका है। इसके बाद पीयर असेसमैंट एवं एक्सटर्नल असेसमैंट प्रस्तावित है।

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडड्र्स (एन0क्यू0ए0एस) के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं इंडिकेटर के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने वाले पात्र संस्थानों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पी0एम0एन0डी0पी0 के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के 29 में से 25 डायलिसिस यूनिट संचालित हैं।

26.08.2026/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

डायलिसिस के संबंध में अभी भी बहुत-सी मांगें प्राप्त हुई हैं। उन सभी मांगों को नोट किया गया है तथा जहां-जहां इन सुविधाओं की आवश्यकता होगी वहां ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 128 डायलिसिस मशीनें कार्यशील तथा 49 नये डायलिसिस सेंटरों के लिए 27.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत है। 26 केंद्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, एन0एच0 के अंतर्गत 18 डे केयर कैंसर केयर सेंटर की स्थापना एवं उन्नयन हेतु 303.80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 17 इस प्रकार के डे केयर सेंटरों के लिए एम0ओ0यू0 एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत 40 जिरिएट्रिक क्लीनिक्स के लिए 420.10 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है तथा वर्ष 2026-27 में उपकरण खरीद के लिए अतिरिक्त 1,667.49 लाख रुपये एवं सी0सी0यू0 के लिए 69.50 लाख रुपये आर0के0जी0एम0सी0, हमीरपुर को आवंटित किए गए हैं।

बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में 11 नये एस0एन0सीयूज तथा 17 एन0बी0एस0यूज0 स्वीकृत हैं। उपयुक्त स्थानों पर क्रमशः पांच एस0एन0सीयूज तथा 12 एन0बी0एस0यूज0 की स्थापना एवं उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। डेंटल सर्विसीज में 51 डेंटल क्लीनिक्स में आधुनिक डेंटल चेयर्स उपलब्ध हैं। शेष क्लीनिक्स में नए चेयर्स स्थापित करने की प्रक्रिया

जारी है।निःशुल्क डायग्नॉस्टिक सर्विसीज के अंतर्गत प्राइमरी हैल्थ सेंटर में 63, कम्युनिटी हैल्थ सेंटर में 96 सिविल हॉस्पिटल में 110 तथा जोनल रीजनल हॉस्पिटल में 133 लैबोरेटरी टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से हमारी लैबोरेटरीज को आधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, समग्र रूप से डी0एच0एस0, डी0एम0ई0, नेशनल हैल्थ मिशन तथा डेंटल सर्विसीज में भवनों, उपकरणों, दवाओं तथा मानव संसाधन की क्वालिटी एश्योरेंस सहित इन सभी प्रमुख क्षेत्रों में चरणबद्ध सुधार एवं व्यवस्था की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष महोदय,

एन0एस0 द्वारा .... जारी ।

26.08.2026/1745/एन0एस0-ए0एस0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ------जारी

मैंने अपने 19 पेजों के लंबे भाषण को 8 पेजों का किया है क्योंकि आप सब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत करवा दिया है। इसलिए एक-एक माननीय सदस्य जो यहां बोल रहे थे उनमें से जो बातें मुझे महत्वपूर्ण लगी हैं उन्हें मैंने नोट किया है। किसी के विधान सभा क्षेत्र में डायलिसिस की आवश्यकता है, किसी के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है और किसी के यहां कोई अन्य समस्या है तो मैंने उन सभी बातों को नोट किया है और जो मैं आपको नहीं बता सका I will attend to that latter on. I am grateful to you all that you have listened to me carefully. Thank you so much. Jai Hind!

अध्यक्ष : वैसे तो बैठक का समय सायं 6.00 बजे तक बढ़ाया गया है। अभी दो और विषय हैं और अगर सदन की राय हो तो कल तक के लिए स्थगित कर दें।

माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक 26 अगस्त, 2026 **सचिव।**